राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

भारत को झटका धवन विश्वकप से बाहर

>> 12

वर्ष 3 अंक 10

दैनिक जागरण

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 20 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर मोदी सरकार बनाएगी पैनल

सर्वदलीय बैठक ▶ अधिकतर दलों ने चर्चा के दौरान विचार का किया समर्थन : राजनाथ

बैठक में बीजद, राकांपा, नेकां, टीआरएस समेत 21 दल हुए शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पैनल का गठन करेंगे, जो तय समय के भीतर काम पूरा करेगा। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। बैठक का कांग्रेस समेत तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, द्रमुक जैसे कई दलों ने बहिष्कार किया, जबकि शिवसेना को छोड़कर राजग के सहयोगी दलों के साथ-साथ विपक्ष से राकांपा, नेकां, टीआरएस, बीजद और वाम दल बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि पार्टी स्थापना दिवस होने की वजह से शिवसेना बैठक में शामिल नहीं हुई।

प्रधानमंत्री ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समेत पांच मुद्दों पर विचार करने के लिए बुधवार को बैठक बुलाई थी। इसके लिए 40 दलों को न्योता भेजा गया था, लेकिन बैठक में 21 दलों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधि ही शामिल हुए। तीन ने लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजी। इन पांच मुद्दों में एक साथ चुनाव के साथ-साथ, संसद की उत्पादकता बढ़ाने, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर न्यू इंडिया के निर्माण, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम और पिछड़े हुए आकांक्षी जिलों के विकास पर चर्चा शामिल थी।

बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से कहा, अधिकतर दलों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार का समर्थन किया है। वाम दलों के इस लागू करने को लेकर विचार अलग थे। वहीं, भाजपा समेत कई दलों का मानना था कि एक साथ चुनाव समय की मांग है और देश को एक बार फिर से इस दिशा में बढ़ना चाहिए।

सिंह के मुताबिक, बैठक में मोदी ने साफ किया कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' राष्ट्रीय मुद्दा है। इसे किसी एक दल या सरकार का एजेंडा नहीं माना जाना चाहिए। इसमें सभी दलों के विचार को शामिल किया जाएगा। बैठक में मौजूद सभी दलों के विचार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कमेटी गठित करने की बात कही और सबने सहमति जताई। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी, बिहार के सीएम व जदयू नेता नीतीश कुमार, शिअद नेता सुखबीर सिंह बादल, ओडिशा के सीएम और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक और नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कोनार्ड संगमा भी बैठक में शामिल हुए। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला और एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी भी बैठक में मौजूद रहे। सीताराम येचुरी और ओवैसी ने इस विचार का विरोध किया। येचुरी ने कहा, यह संघीय भावना के विपरीत है। भाजपा बैकडोर से संसदीय लोकतंत्र की जगह राष्ट्रपति प्रणाली जैसी व्यवस्था लाना चाहती है।

कांग्रेस ने अंतिम समय में बैठक में न जाने का ऐलान किया। पार्टी प्रवक्ता गौरव गोगोई ने कहा, यह असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, बसपा प्रमुख मायावती, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में नहीं शामिल हुए है। ममता बनर्जी ने इस पर श्वेत पत्र लाने की मांग की, जबकि मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अगर बैठक ईवीएम को लेकर होती तो वह जरूर शामिल होतीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल नहीं हुए।

ज्ञात हो, एक साथ चुनाव भाजपा के एजेंडे में टॉप पर है और इसे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 2014 से ही इस बाबत अपील करते रहे हैं।

विभिन्न दलों के अध्यक्षों के साथ शानदार बैठक हुई। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गई। मैं विभिन्न नेताओं को उनके अहम सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं।-नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली में बुधवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में जदयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राकांपा प्रमुख शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक व आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी शामिल हुए। प्रेट्र

कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा पार्टी लाइन से हटकर केंद्र के साथ

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, सरकार के प्रस्ताव पर खुले मन से विचार किया जाना चाहिए। उन्हें अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं कि एक साथ चुनाव कराने से केंद्र में सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलेगा। हाल ही में लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। ओडिशा और आंध्र में वे दल जीते जिनका भाजपा के साथ गठबंधन नहीं था।

विधि आयोग इसके लिए सख्त कानूनी ढांचे के पक्ष में

नई दिल्ली, प्रेट्र : विधि आयोग ने गत वर्ष मसौदा सिफारिशों में संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की बात की थी ताकि एक साथ चुनाव सुनिश्चित हो सकें। आयोग ने कहा था कि लोस और विस के चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते है बशर्ते संविधान के दो प्रावधानों में संशोधन हों और बहुमत से राज्यों द्वारा उनका अनुमोदन किया जाए।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अभी संभव नहीं : चुनाव आयोग

नई दिल्ली, आइएएनएस : चुनाव आयोग का कहना है कि फिलहाल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करना संभव नहीं है। आयोग के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि अगर ऐसा संभव होता तो आयोग इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ ही करा लेता। इसके लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, जबकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या सीमित है। सूत्रों ने यह भी कहा कि देश में इस समय 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनके लिए बड़ी संख्या में मतदान अधिकारी, ईवीएम और अन्य संसाधनों की जरूरत होगी, जिसे जुटा पाना फिलहाल संभव नहीं है।

लोकतंत्र के प्रहरी
आपातकाल के 44 साल

ब्रिटिश सरकार से ज्यादा जुल्म आजाद भारत में सहे

आपातकाल के दौर में जेल की यातना यादकर आज भी उरई के राजाराम व्यास सिहर उठते हैं। बताते हैं कि पानी मांगने पर मूत्र पीने को दिया जाता था। पुलिस पेड़ से लटकाकर पीटती थी। मानसिक यातना भी कम नहीं थी। परिजनों के पत्र जेल के अधिकारी पढ़ने के बाद देते थे। ● पेज 13

हमारी सरकार
डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक', मानव संसाधन विकास मंत्री

आचार्य से शुरू सफर को मिला अहम मुकाम

● पेज 5

विश्वास • News

वायरल नंबर योगी आदित्यनाथ का नहीं, जीआरपी का है ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 7

सरोकार

ये है हुनरमंद सखियों का करोड़पति मंडल

गोड्डा : झारखंड के गोड्डा जिले का फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल कई मायनों में खास है। महिलाओं की लगन और मेहनत ने सखी मंडल को करोड़पति बना दिया है। कभी गरीबी से जूझने वाली गांव की महिलाएं आज हुनरमंद बन गुरबत को हरा चुकी हैं। मंडल का कारोबार पांच करोड़ के पार पहुंच गया है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि इसको एसोचैम ने सम्मानित किया है। मंडल से जुड़ी हर सखी सात से आठ हजार रुपये महीने कमा रही है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

खशोगी हत्याकांड में सऊदी युवराज के खिलाफ पुख्ता सुबूत

जिनेवा : पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में सऊदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिले हैं। यह बात संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करने वाली मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कही है। इस जांच निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने मुहम्मद की विदेशी संपत्तियों की जब्ती की मांग की है। खशोगी की अक्टूबर 2018 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में उस समय हत्या हुई थी जब वह अपने वीजा से संबंधित दस्तावेज पेश करने गए थे।

क्रिकेट महाकुंभ
ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश
दोपहर 3:00 बजे से
स्थान : नॉटिंघम
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

पाकिस्तान सीमा पर रणनीति बदलेगी सेना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अक्टूबर से होगी विशेष वार ग्रुप की तैनाती, युद्ध के जरूरी हथियारों से लैस रहेंगे ये फौजी दस्ता
- हमले और बचाव के लिए होंगे अलग दल, अगले चरण में चीन सीमा पर भी होगी तैनाती

पाकिस्तान की नापाक हरकतों और चीन से आए दिन के खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना रणनीतिक रूप से खुद को बेहतर करने का काम कर रही है। सीमा के पास लगातार बढ़ रहे खतरों को भांपते हुए भारतीय सेना ने खास रणनीति के तहत इसी साल अक्टूबर से पाकिस्तान से लगी सीमा पर 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' (आइबीजी) तैनात करने की योजना बनाई है। बाद में इसे चीन से लगी सीमा पर भी तैनात किया जाएगा।

आइजीबी के तहत आर्टिलरी गन, टैंक, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक जैसे सेना के अलग-अलग घटकों को एक साथ लाया जाएगा। यह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार समूह होगा। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के प्रयासों के बीच यह रणनीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रणनीति में रक्षात्मक भूमिका को मजबूती देते हुए पहले के मुकाबले ज्यादा थल सैनिकों को सीमा पर तैनात किया जाएगा। इनका काम मुख्य स्ट्राइक ग्रुप का साथ देना और अपने क्षेत्र का बचाव करना होगा।

युद्ध की स्थिति में दुश्मनों की सीमा में सेना की टुकड़ियों को तेजी से भेजने और त्वरित कार्रवाई के मकसद से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया गया है। यह इतनी तेजी से कार्रवाई करेगा कि दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। आइबीजी छोटा होगा और युद्ध के लिए आवश्यक सभी हथियार और सैनिकों से लैस होगा। आइजीबी की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के हाथ में हो सकती है। एक ग्रुप में करीब 5,000 सैनिक होने की उम्मीद है। साल के आखिर तक कम से कम ऐसे तीन ग्रुप तैयार हो जाएंगे।

इस कॉन्सेप्ट को साकार करने के लिए सेना के पूर्वी कमांड के अंतर्गत इस खास युद्ध रणनीति का अभ्यास किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह युद्धक फॉर्मेशन बेहद घातक होगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के अभ्यास और उसके फीडबैक को लेकर पिछले हफ्ते विस्तार से चर्चा हुई। सेना मुख्यालय में हुई बैठक में सात आर्मी कमांडरों ने भाग लिया। बैठक में कमांडर-इन-चीफ को ये निर्देश दिए गए कि वो अपने-अपने इलाकों में आइबीजी का निर्माण कराएं। पहले तीन ग्रुप पूर्वी कमांड की फॉर्मेशन की तर्ज पर बनाए जाएंगे। यह ग्रुप सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की उस खास रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो सेना को ज्यादा प्रभावशाली और खतरनाक बनाना चाहते हैं।

ब्रिगेड व्यवस्था की जगह लेगा आइबीजी : असल में सेना इस कॉन्सेप्ट को ब्रिगेड व्यवस्था की जगह लाना चाहती है। आइबीजी अपने आप में युद्ध की स्थिति से निपटने में सक्षम टीम होगी। वहीं ब्रिगेड व्यवस्था को युद्ध की स्थिति में साजो-सामान के लिए इंतजार करना पड़ता है। ब्रिगेड में कम से कम तीन से चार यूनिट होती हैं। प्रत्येक यूनिट में 800 सैनिक होते हैं।

अब किसी भी नापाक हरकत पर सेना साधेगी सटीक निशाना पेज>>6

ओम बिरला बने सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोटा से सांसद बिरला को अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए प्रधानमंत्री मोदी
- कांग्रेस, तृणमूल समेत सभी विपक्षी दलों ने बिरला पर जताया भरोसा

राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला बुधवार को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और चुने जाने के बाद अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। इस अवसर पर जहां पीएम ने बिरला की विनम्रता व समाजसेवा के भाव की तारीफ की, वहीं विपक्षी दलों ने सदन को निष्पक्षता से चलाये जाने की उम्मीद जताई।

ओम बिरला की विनम्रता की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, उनका जीवन अनुशासन और समाजसेवा का रहा है। उम्मीद है कि वे सदन को अपने अनुशासन से अनुप्रेरित करेंगे। पीएम ने कहा, बिरला की कार्यशैली में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि समाजसेवा है। समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए वह सदैव प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह बिरला गुजरात में 2011 के भूकंप के दौरान राहत कार्य में जुटे थे। केदारनाथ त्रासदी के समय भी लोगों की मदद के लिए पहुंच गए थे। कोटा की जनता की सेवा के लिए भी आधी रात को कंबल लेकर निकलते थे। कोटा में कोई भूखा न सोए इसके लिए प्रसादम नाम की योजना भी चला रहे हैं।

सुबह लोकसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही पीएम ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए बिरला का नाम प्रस्तावित किया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा, बसपा समेत समूचे विपक्ष ने भी साथ दिया और बिरला ध्वनिमत से अध्यक्ष चुने गए। बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए सांसदों को आश्वासन दिया कि वह किसी भी दल के हों, वह उनके हितों का ध्यान रखेंगे। सदन की कार्यवाही में सभी नियमों व नियमावलियों का पूरा पालन करेंगे। उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के सदस्यों से सहयोग मांगा। इसके बाद बिरला ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उसके बाद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर जाकर उनसे मिले।

लोकसभा का अध्यक्ष बनते ही सामने आई मांगों की लंबी फेहरिस्त पेज>>3

नई दिल्ली में बुधवार को भाजपा सांसद ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। पीएम मोदी उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। इस दौरान आभार जताते ओम बिरला (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

मानसून की धीमी चाल से सब परेशान, सूखे की आशंका

मुंबई : भारत में करीब एक हफ्ते देरी से केरल पहुंचे (आठ जून) मानसून की गति औसत से भी धीमी है। जून में अब तक बारिश औसत से 44 फीसद कम हुई है। इसके चलते खेती चौपट होने के साथ ही देश के कई हिस्से में भीषण सूखे की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। बारिश में कमी से उपभोक्ताओं की मांग, अर्थव्यवस्था की चाल और बाजार के हाल पर बहुत गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने इस साल औसत बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं मौसम का हाल बताने वाली देश की इकलौती निजी एजेंसी स्काईमेट ने औसत से कम बारिश का अनुमान जताया है। (पेज-5)

रेलवे बढ़ाएगी रफ्तार : दिल्ली से 12 घंटे में कोलकाता और 10 घंटे में मुंबई पहुंचेगी ट्रेन

- रेलवे ने तैयार किया 100 दिन की कार्ययोजना का मसौदा
- दो ट्रेनों और कुछ रेल मार्गों को निजी हाथों में सौंपने की भी तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को 100 दिन का एजेंडा तय करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में रेलवे ने योजना तैयार की है, जिसके तहत दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई के बीच रेल यात्रा के समय में पांच घंटे की कमी लाने का लक्ष्य है। रेलवे इसके लिए अगले चार साल में इन दोनों मार्गों पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 14,000 करोड़ का निवेश करेगी। रेलवे ने 10 और प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। 31 अगस्त तक इन्हें लागू करने को तत्काल कार्य शुरू करने की बात भी कही है। इन दोनों व्यस्त रेल मार्ग पर देश की कुल यात्री ट्रेनों में से 30 फीसद और 20 फीसद मालगाड़ियों का आना-जाना रहता है।

मौजूदा समय में दिल्ली से हावड़ा की दूरी तय करने में सबसे तेज रफ्तार ट्रेन को 17 घंटे, जबकि दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 15.5 घंटे लगते हैं। 100 दिन की योजना में इन दोनों ही मार्ग पर यात्रा समय को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के पास भेजा जाना है।

प्रस्ताव के मसौदे के मुताबिक, अभी इन दोनों ही रूट पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रतिघंटे है, जिसे बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रतिघंटे किया जाना है। इस प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली-हावड़ा रूट (1,525 किलोमीटर) पर 6, 684 करोड़ और दिल्ली-मुंबई रूट (1,483) पर 6,806 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मंजूरी मिलने के बाद चार साल का समय लगेगा। अन्य 10 प्रस्तावों में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई 'गिव इट अप' योजना शामिल है, जिसके तहत लोगों को रेल टिकट पर सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अगले 100 दिन की योजना में कम भीड़ वाले रेल मार्गों और दो ट्रेनों के संचालन को निजी हाथों में सौंपा जाना भी शामिल है। इसके अलावा सभी 6,485 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराना, 2023 तक सभी 2,568 लेबल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए मंजूरी हासिल करना और अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली इत्यादि लागू करना शामिल है।

फिर शुरू हुई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने की कोशिश पेज>>3

विश्वास की कमी

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोगों की भावना व अपेक्षा को समझ नहीं रही है, कांग्रेस के व्यवहार से आशंका होती है वह न सिर्फ संख्या में बल्कि सोच और मनोबल में भी छोटी होने लगी है

...कांग्रेस की एक और गलती

त्वरित टिप्पणी
प्रशांत मिश्र

- एक साथ चुनाव पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार पड़ेगा भारी

कांग्रेस की सोच समझ से परे है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो आचार व्यवहार रहा, उसकी बात छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि जनता ने ही उसका जवाब दे दिया। जनादेश ने जिस तरह कांग्रेस को लगातार दूसरी बार दस फीसद सीटों से भी नीचे खड़ा कर दिया, वह यह बताने के लिए काफी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी लोगों की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। वह जनता की भावना व अपेक्षा को नहीं समझ पा रही है। अफसोस तो यह है कि बार-बार के झटके के बावजूद कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रही है। एक देश, एक चुनाव यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का जिस तरह कांग्रेस ने बहिष्कार किया, वह साबित करता है कि कांग्रेस गलतियों से सीख लेने के लिए तैयार नहीं है।

अभी दो दिन पहले 17वीं लोकसभा की शुरुआत के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बयान आया था कि विपक्ष को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास कितने नंबर हैं। उन्हें अपने विचार रखने चाहिए और सरकार हर किसी के विचार को सुनकर आगे बढ़ेगी। तत्काल कांग्रेस की ओर से उत्तर आया था और उम्मीद जताई गई थी कि विधेयकों पर विपक्ष की राय सुनी जाएगी और बहुमत के बल पर उसे नहीं दबाया जाएगा। एक तरह से कांग्रेस ने तंज किया था। फिर बुधवार को कांग्रेस को क्या हो गया..? प्रधानमंत्री की ओर से एक बैठक बुलाई गई और कांग्रेस अपने विचार रखने तक को आने को तैयार नहीं हुई। कई छोटे विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी पांच राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। क्या उसके लिए यह उचित नहीं था कि बैठक में आए और विरोध करना है तो विरोध ही करे। तर्कों के साथ अपनी बात रखे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और उसके सलाहकारों की बलिहारी, उसने तो हार ही मान ली।

कांग्रेस के इस व्यवहार से आशंका जरूर होगी कि वह न सिर्फ संख्या में बल्कि सोच और मनोबल में भी छोटी होने लगी है। डरी हुई है। इस कोशिश में है कि किसी भी मुद्दे पर विरोधी दलों के साथ ही खड़ी रहे ताकि एक खेमा तो बना रहे। यह डर कांग्रेस के लिए खतरनाक है। बैठक में सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। अगर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं आ सकते थे तो किसी भी दूसरे वरिष्ठ नेता को भेजा जा सकता था जो तर्कों के साथ यह बात रख पाते कि एक साथ चुनाव कराना देश के हित में नहीं है। दरअसल अब तक अलग-अलग मंचों से जितनी भी चर्चा हुई है, उसमें यही बात मानी गई है कि एक साथ चुनाव हुए तो देश का पैसा भी बचेगा, वक्त भी और विकास की धारा भी अवरुद्ध नहीं होगी। वह पैसा, वह वक्त जनता का है। इसका विरोध करने वाले दल व्यावहारिकता आदि की दलील देते रहे हैं। सच्चाई यह है कि इसके पीछे दलों का डर छिपा है। बैठक से बाहर रहकर कांग्रेस ने इसे जाहिर कर दिया। अब उसे यह सोचना चाहिए कि जनता को कैसे समझाएगी।

राहुल गांधी फाइल फोटो

महाराष्ट्र में 4 हजार से ज्यादा महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र के बीड जिले में 4,605 महिलाओं के गर्भाशय सिर्फ इसलिए निकाल दिए गए, ताकि वह अनवरत गन्ने की कटाई का काम कर सकें। महाराष्ट्र विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका रहस्योद्घाटन किया। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने एक पैनल गठित कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, पिछले तीन साल में मराठवाड़ा के बीड जिले में 4,605 महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। बीड जिला सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच में इस बात का पता चला। रिपोर्ट के अनुसार, बीड में निजी क्षेत्र के 99 अस्पतालों में 2016-17 से 2018-19 के बीच इतनी बड़ी संख्या में 25 से 30 वर्ष आयुवर्ग की महिलाओं की अज्ञानता का लाभ उठाकर गर्भाशय निकाले गए। स्वास्थ्य मंत्री ने विधान परिषद में शिवसेना की दो महिला सदस्यों नीलम गोरे एवं मनीषा कायंदे के सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने की जांच के लिए बुधवार को एक पैनल का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव इसका नेतृत्व करेंगे। इस पैनल में तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ और कुछ महिला विधायक भी शामिल होंगी। पैनल दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।

28 हजार किलोग्राम से अधिक पॉलीथिन बैग जब्त किए हैं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अधिकारियों की टीम ने। टीम ने आजादपुर मंडी, सदर बाजार की पान मंडी और गाजीपुर मंडी में छापे मारे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 20 जून 2019

दिल्ली पुलिस को फटकार, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

मुखर्जी नगर मामला ▶ हाई कोर्ट की पीठ ने कहा– ग्रामीण सेवा के चालक और उनका बेटा पुलिस की क्रूरता के सुबूत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ग्रामीण सेवा चालक व उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) से मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयंत नाथ व न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि ग्रामीण सेवा चालक व उनका बेटा पुलिस की क्रूरता के सुबूत हैं। पीठ ने कहा कि अगर वर्दीधारी फोर्स ऐसा बर्ताव करेगी तो फिर इससे उन लोगों में भय व्याप्त होगा, जिन्हें यह महसूस करने की जरूरत है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। पीठ ने कहा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज में बेचैनी पैदा होगी। उक्त टिप्पणी करते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पीठ ने घटना के संबंध में एक संयुक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही मीडिया को निर्देश दिया कि ग्रामीण सेवा चालक के नाबालिग बेटे की पहचान न उजागर की जाए। याचिका पर अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयंत नाथ व न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने पूछा कि हम दिल्ली में रह रहे हैं या फिर कहीं और। पीठ ने कहा कि जब आपने ग्रामीण सेवा चालक को काबू कर लिया था तो उसे दिनदहाड़े सड़क पर लाठी-डंडों से पीटने की क्या जरूरत थी। पीठ ने पूछा कि क्या पुलिस से ऐसी उम्मीद की जाती है। पीठ ने पुलिस से दो टूक सवाल पूछा कि क्या आप इस कृत्य को न्यायसंगत मानते हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल सत्यकाम ने कहा कि हम पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई का बचाव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से एफआइआर दर्ज की गई है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि वीडियो के माध्यम से पहचान कर घटना में शामिल रहे तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच संयुक्त पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं।

पुलिस की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई अदालत : दिल्ली पुलिस की दलीलों से असंतुष्ट पीठ ने कहा कि वीडियो से साफ तौर पर पहचान की जा सकती है कि घटना में आठ से नौ पुलिसकर्मी शामिल थे तो फिर सभी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत में वीडियो देखने के बाद पीठ ने यह भी कहा कि पांच पुलिस अधिकारी 15 साल के किशोर को सड़क पर घसीट कर लाठी-डंडों से पीट रहे थे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

अधिकारियों की पहचान कर करें कार्रवाई : पीठ ने कहा उन पांच अधिकारियों की पहचान करिए, जिन्होंने किशोर को सड़क पर घसीट कर पीटा जो सिर्फ अपने पिता को उनके बीच से अलग ले जाना चाहता था। पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार समेत पुलिस से कहा कि उन पांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, जिन्होंने किशोर की पिटाई की।

यह है याचिका

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सीमा सिंघल ने अधिवक्ता संगीता भारती के माध्यम से याचिका दायर कर मामले की सीबीआइ से स्वतंत्र जांच कराने व पुलिस सुधारों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज के साथ मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी जाए और पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाएं। याचिका में यह भी मांग की गई कि चालक के नाबालिग बेटे की पहचान उजागर करने और उसकी तस्वीरें प्रकाशित करने या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार जारी करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

गृह मंत्री को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुखर्जी नगर की घटना को लेकर आम लोगों और राजनीतिक दलों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस घटना की निंदा किए जाने के बाद से आम आदमी पार्टी (आप) पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। तिलक नगर से आप के विधायक जरनैल सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि एक ग्रामीण सेवा चालक के साथ पुलिस का व्यवहार निदंनीय एवं बर्बरतापूर्ण था। इस घटना से यह जाहिर हो गया कि पुलिस को इस हालात पर जिस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए था, पुलिस ने वैसा रवैया नहीं दिखाया। ऐसी घटना समाज में कतई स्वीकार्य नहीं हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त व डीसीपी पर गिर सकती है गाज

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

ग्रामीण सेवा वाहन चालक व मुखर्जी नगर थाने के पुलिसकर्मियों के बीच झगड़े के बाद शुरू हुआ बवाल बुधवार को चौथे दिन भले ही शांत होता दिखा, लेकिन पूरे मामले में जिस तरह से कई स्तर पर दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आई है, उससे गृह मंत्रालय काफी नाराज है। मामले में मंगलवार को गृह मंत्रालय में सौंपी गई रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने माना कि पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की गलती से बवाल बढ़ता चला गया। कुछ नेताओं द्वारा मामले में धार्मिक रंग देने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। पुलिसिया लापरवाही के कारण माना जा रहा है कि उत्तरी रेंज के संयुक्त आयुक्त व उत्तर-पश्चिम जिले की डीसीपी पर भी गाज गिर सकती है। साथ ही शीर्ष स्तर पर भी फेरबदल हो सकता है। कुछ अधिकारी छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं। गृह सचिव ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं।

मामले में तीन पुलिसकर्मियों एएसआइ देवेंद्र सिंह, एएसआइ संजय मलिक व सिपाही पुष्पेंद्र को पहले लाइन हाजिर किया गया, बाद में डीसीपी विजयंता आर्या पर नेताओं द्वारा दबाव बनाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। गृह मंत्रालय को शीर्ष स्तर

▶ दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आने से गृह मंत्रालय नाराज

पर लापरवाही बरते जाने की बात पता चलने पर अब आला अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। दिल्ली में इतिहास को देखा जाए तो हमेशा निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही गाज गिरी है।

भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ 4 जून 2011 को जब बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान से आंदोलन की शुरुआत की थी, तब तत्कालीन विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के मौखिक आदेश पर आधी रात पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था। मामला तूल पकड़ने पर 25 से अधिक पुलिसकर्मियों को न केवल निलंबित किया गया, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये पुलिसकर्मी आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मुखर्जी नगर की घटना को भी उक्त घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिसकर्मियों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि डीसीपी ने नेताओं के दबाव में आकर कार्रवाई क्यों की? आला अधिकारियों ने जांच के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की? डीसीपी ने कार्रवाई संबंधी आदेश का वीडियो अपने कमरे में क्यों बनाने दिया? बाद में वीडियो वायरल कर दिए जाने से दिल्ली पुलिस की किरकिरी हुई। वीडियो में डीसीपी, नेताओं के आगे बेबस दिख रही हैं।

मामले को धार्मिक रंग देने पर जिस तरह से कार्रवाई की गई उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस में नाराजगी है। जब एएसआइ योगराज के सिर और पैर पर कृपाण से वार किया गया तो उनकी शिकायत पर हत्या के प्रयास की धारा क्यों नहीं लगाई गई? एसीपी केसी त्यागी को भी भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। उनकी शिकायत पर भी मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? खुद को पेशेवर होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस यह कहती है कि वह मेरिट के आधार पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन हाल के कुछ मामले देखें तो यह दावा खोखला साबित होता दिखता है। छह जून को जगतपुरी में एक वाहन चोर द्वारा गली से चोरी की कार लेकर भागने के दौरान उसने एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों को टक्कर मार दी थी। इसको लेकर अफवाह फैला देने पर समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। डीटीसी की कई बसों को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन पुलिस ने पहले दंगा करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया था। मीडिया में बात आने पर देर शाम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद मुखर्जी नगर मामले में भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि इससे दिल्ली में गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी।

क्राइम ब्रांच ने मौके पर पहुंच कर शुरू की जांच

जासं, नई दिल्ली : मुखर्जी नगर मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने बुधवार से शुरू कर दी। सोमवार देर शाम पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने मामले में पुलिस व ग्रामीण सेवा के चालक की ओर से दर्ज कराई गई दोनों एफआइआर को विस्तृत जांच के लिए क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया था। मंगलवार को थाना पुलिस ने दोनों केस की फाइल क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी।

दोनों केस की जांच की जिम्मेदारी दो अलग-अलग इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच राजीव रंजन के नेतृत्व में जांच की जा रही है। जांच के हर तथ्य के बारे में पुलिस आयुक्त को अवगत कराया जाएगा। आयुक्त ने जल्द से जल्द व निष्पक्ष तरीके से जांच करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मुखर्जी नगर पहुंच कर करीब दो घंटे तक मौके का मुआयना किया। स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पुलिस अधिकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच पहले घटना के सारे वीडियो की जांच कर पुलिसकर्मियों व उपद्रव मचा रहे लोगों की पहचान करेगी। उसके बाद उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजेगी।

क्राइम ब्रांच ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास घटना से संबंधित वीडियो फुटेज है तो वे क्राइम ब्रांच को सौंप सकते हैं। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीटीवीटी की फुटेज भी खंगालने की कोशिश करेगी ताकि जांच में उससे कुछ सहयोग मिल सके।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले को धार्मिक रंग देना बहुत ही गलत है। घटना के बाद लोगों ने तलवार, भाला व लाठी डंडा लेकर हंगामा किया। कई दिनों तक सड़क जाम कर और थाने के बाहर प्रदर्शन कर लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। ऐसे लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जाएगी।

केजरीवाल व शीला को योग करने का आमंत्रण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राजपथ पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारी करते लोग। संजय

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को भाजपा की ओर से दिल्ली में तीन सौ स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कई केंद्रीय मंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी योग करने के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि योग मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सभी को योग का अभ्यास करना चाहिए। वह घोंडा विधानसभा क्षेत्र में यमुना के किनारे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह चाहते हैं कि केजरीवाल व शीला दीक्षित भी उनके साथ योग का अभ्यास करें। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। देश में लगभग 13 करोड़ लोग योग दिवस के दिन योग करेंगे। आयुष्मान मंत्रालय की वेबसाइट पर 77 लाख लोगों ने योग करने के लिए पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में आयोजित कार्यक्रम में लोगों के साथ योग करेंगे। वहीं, दिल्ली में दस लाख लोग योग दिवस के दिन योग करेंगे।

दिल्ली भाजपा की ओर से 280 मंडलों के साथ ही अन्य स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रम होंगे। 40 स्थानों पर बड़े कार्यक्रम होंगे जिनमें मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी घोंडा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिली है। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम 21 जून 2015 को राजपथ पर आयोजित हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री के साथ 84 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि योग किसी धर्म से संबंधित नहीं है। सभी को स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करना चाहिए।

लीबिया मूल की डॉक्टर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में लीबिया मूल की महिला डॉक्टर के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर की शिकायत पर न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वर्ष 2011 में लीबिया से एमबीबीएस करने के बाद पीड़िता इंटर्नशिप के लिए गुरुग्राम आई थी और एक निजी अस्पताल में इंटर्नशिप करने के बाद बसई रोड स्थित निजी अस्पताल में काम के दौरान उसकी दोस्ती यहां कार्यरत डॉक्टर महेंद्र परमार से हो गई। आरोप है कि डॉक्टर महेंद्र परमार ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब वह शादी के लिए इन्कार करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। घटनाक्रम के बाद पीड़िता जनवरी में अपने देश लौट गई और अपने परिजनों की आपबीती बताई। बाद में वह वापस लौटी और न्यू कॉलोनी थाना पुलिस के पास पहुंच कर लिखित शिकायत दी, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

गो वे कंपनी के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

बाइक बोट की तरह फर्जीवाड़ा करने वाली गो वे कंपनी के खिलाफ दूसरा मुकदमा कासना कोतवाली में दर्ज किया गया है। गो वे कंपनी ने 62 हजार रुपये को एक साल में दोगुना करने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की है। अब तक करोड़ों रुपये ठगी होने की आशंका है। कंपनी के कर्ताधर्ता दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। मामले में पहला मुकदमा 16 जून को बुलंदशहर के रहने वाले दीपेश शर्मा ने दर्ज कराया था। कंपनी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आशंका है कि 17 हजार लोगों ने कंपनी में निवेश किया है। कंपनी के मालिक पति-पत्नी अनिल सेन व मीनू फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

शहर के साइट फोर स्थित जेएनएस प्लाजा में केडीएम इंटरप्राइजेज ग्रुप का दफ्तर है। इस ग्रुप ने बाइक बोट की तरह गो वे नाम की इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना शुरू की। इस कंपनी के मालिक अनिल सेन व उसकी पत्नी मीनू हैं। यह योजना एक साल पहले शुरू हुई थी। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया उद्देश्य के साथ शुरू की गई इस योजना में लोगों से पैसा निवेश कराया गया।

इस तरह के विज्ञापन देकर लुभाते थे निवेशकों को। यह तस्वीर सोशल मीडिया से ली गई है।

▶ पति-पत्नी ने 17 हजार लोगों से की करोड़ों की ठगी

कंपनी ने 62 हजार रुपये निवेश करने पर एक साल में दोगुना करके देने का वादा किया था। कंपनी में लोगों ने लाखों रुपये का निवेश किया। कुछ दिनों बाद कंपनी ने पैसा वापस देना बंद कर दिया। जब लोगों ने पैसा वापस मांगा तो तकनीकी दिक्कत का हवाला देकर कुछ दिन तक लोगों को टालते रहे। जब पैसा मिलने की उम्मीद नजर आनी बंद हो गई तो पीड़ितों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

गाजियाबाद की रहने वाली अर्चना चौधरी ने बताया कि नवंबर 2018 में उन्होंने अपना व अपने जानकार का कुल पांच लाख 58 हजार रुपये गो वे कंपनी में लगाया था। कंपनी मालिक ने एक साल में दो गुना यानी 11 लाख 16 हजार रुपये लौटाने का वादा किया था। यह रकम महीनावार किस्त में देने की बात कंपनी की तरफ से कही गई थी। एक महीने बाद ही किस्त मिलना बंद हो गई। ऑफिस में संपर्क किया तो पता लगा कि आरोपित-पति-पत्नी ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। अर्चना की तहरीर पर पुलिस ने अनिल सेन, मीनू सेन व एक अन्य कुणाल सेन के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज किया है।

एप पर हैं चार नाम : गो वे कंपनी के प्ले स्टोर पर चार एप हैं। गो वे ड्राइवर, गो वे इंडिया, टेस्टिंग ड्राइवर, टेस्टिंग राइडर एप के जरिये लोग इसकी सुविधा लेते थे। इन एप का स्वामित्व केडीएम ग्रुप के पास है। ई स्कूटर का किराया चार किलोमीटर प्रति रुपये रखा गया था। यह किराया बाइक बोट से दो रुपये प्रति किलोमीटर कम है। कंपनी ने महिला यात्रियों के लिए महिला चालक वाले स्कूटर का वादा किया था। दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सेवा का लालच भी दिया गया था।

स्नातक में दाखिले के लिए 28 को पहला कटऑफ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार देर रात स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कटऑफ की तारीखें घोषित कर दी हैं। पहला कटऑफ 28 जून को आएगा। विद्यार्थियों को इसके आधार पर 28 जून से एक जुलाई तक कॉलेजों में जाकर दाखिले कराने होंगे। इस दौरान 12वीं की मार्कशीट, दसवीं का सर्टिफिकेट और आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र या फिर उसके आवेदन की प्राप्ति रसीद जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे।

डीयू प्रशासन ने परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भी तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके लिए पहली अधिसूचना 17 जुलाई को जारी होगी, जिसके तहत 17 से 19 जुलाई तक कॉलेजों में जाकर दाखिला लेना होगा। इस दौरान कॉलेज प्रशासन शैक्षणिक दस्तावेजों की भी जांच करेगा। परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे। इनमें दाखिले के लिए डीयू 30 जून से छह जुलाई तक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।

स्नातक के कटऑफ की तारीखें

पहला कटऑफ- 28 जून : इस कटऑफ के आधार पर 28 से एक जुलाई के बीच कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को दाखिला लेना होगा।

दूसरा कटऑफ- 4 जुलाई : इस कटऑफ के आधार पर चार से छह जुलाई के दौरान कॉलेजों में दाखिला लेना होगा।

तीसरा कटऑफ -9 जुलाई : इस कटऑफ के आधार पर 9 से 11 जुलाई के दौरान कॉलेजों में दाखिले लिए जाएंगे।

चौथा कटऑफ- 15 जुलाई

इस कटऑफ के आधार पर 15 से 20 जुलाई के दौरान कॉलेजों में छात्रों को दाखिला लेना होगा।

पांचवां कटऑफ- 20 जुलाई : इस कटऑफ के आधार पर 20 जुलाई से 27 जुलाई के दौरान कॉलेज दाखिला लेंगे।

इन बातों का रखें ध्यान

- कटऑफ के तहत कॉलेजों में दाखिले रविवार को नहीं होंगे।
- कटऑफ में जिन भी छात्रों का नंबर आता है, उन्हें अपने मूल दस्तावेज कॉलेजों में लेकर जाने होंगे। दाखिले के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पाठ्यक्रम की सेमेस्टर फीस डीयू के दाखिला पोर्टल में जाकर जमा करनी होगी।
- **फीस जमा करने के लिए :** ऑनलाइन पेमेंट के लिए डीयू के परास्नातक वाले पोर्टल पर फीस का भुगतान करना होगा।
- प्रमाण पत्रों का सत्यापन व दाखिला डीयू के विभाग व फैकल्टी में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक होगा।
- **कॉलेज :** सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक खुलेंगे।

डीयू में दाखिला

परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की तिथियां

17 जुलाई : दाखिले के लिए पहली अधिसूचना जारी होगी। इसके तहत 17 से 19 जुलाई तक दाखिले दिए जाएंगे।

22 जुलाई : दाखिले के लिए दूसरी लिस्ट। इसके तहत 22 से 24 जुलाई तक दाखिले दिए जाएंगे।

27 जुलाई : दाखिले के लिए तीसरी लिस्ट। इसके तहत 27 जुलाई से 30 जुलाई (रविवार को छोड़कर) तक दाखिले होंगे।

2 अगस्त : दाखिले के लिए चौथी लिस्ट। इसके तहत पांच अगस्त तक दाखिले होंगे।

ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर छात्रों को राहत

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के छात्रों को बड़ी राहत दी है। दाखिला समिति ने बुधवार को कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आवेदन करने वाले छात्र अपने प्रमाणपत्र की प्राप्ति रसीद को दाखिला पोर्टल पर अपलोड करके दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है और अब तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है तो इसकी प्राप्ति रसीद के आधार पर कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि वे मूल दस्तावेज कॉलेज प्रशासन को दिखाएंगे। प्रमाणपत्र जारी होने के बाद मूल प्रमाणपत्र कॉलेज प्रशासन को दिखाना होगा।

डीयू के अकादमिक परिषद के सदस्य प्रो. रसाल सिंह ने बताया कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र 31 मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए और आवेदन कर रहे छात्रों की जाति राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की सूची में शामिल होनी चाहिए।

बंगाल मैंगो मेला

जनपथ स्थित हैंडलूम हाट में बंगाल मैंगो मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला 30 जून तक चलेगा। इसमें सभी आम बंगाल से लाए जाते हैं। अपनी गुणवत्ता के कारण ही इनकी मांग अधिक रहती है। इसमें लंगड़ा, आम्रपाली, मलिका व हिमसागर आदि आम लोगों की खास पसंद हैं। इसमें सबसे अधिक मांग हिमसागर आम की है, क्योंकि यह रसीला और मीठा होता है। इसको मालदा और मुर्शिदाबाद जिले से लाया जाता है। ध्रुव कुमार

योजना

निजी वाहनों का इस्तेमाल सीमित करने के उद्देश्य से डीडीए ने बनाई योजना, प्रदूषण को कम करने में मिलेगी मदद

मेट्रो के इंटरचेंज स्टेशनों के पास बनेंगे कॉमर्शियल हब

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ और यातायात जाम कम करने के लिए मेट्रो के इंटरचेंज स्टेशनों के पास कॉमर्शियल हब बनाए जाएंगे। यहां मनोरंजन, खानपान और खरीदारी से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोग मेट्रो से आएं, वहां घूमे-फिरें, खरीदारी करें और मेट्रो से ही लौट जाएं। सड़क पर उतरने या निजी वाहन निकालने की जरूरत ही नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की इस योजना का सारा खाका तैयार हो चुका है। जनता के सुझाव एवं आपत्तियां भी ले ली गई हैं। उपराज्यपाल की स्वीकृति के साथ जल्द ही इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा।

यह है योजना : डीडीए ने नेशनल इंस्टीयूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर ट्रांजिट ओरियेंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के आधार पर इस अति महत्वाकांक्षी योजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो के सभी प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों, अंतरराज्जीय बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के पास कॉमर्शियल हब बनाना प्रस्तावित है। सभी हब इन जगहों से पांच सौ मीटर के दायरे में बनाए जाएंगे। इनका क्षेत्र तीन हजार वर्ग मीटर से एक हेक्टेयर तक रहेगा। हब के साथ कम से कम 18 मीटर चौड़ी सड़क भी जरूरी है ताकि ट्रैफिक चलता रहे। इस बहुमंजिला कॉमर्शियल हब में घरेलू जरूरतों से जुड़ा हर सामान खरीदने की व्यवस्था होगी। मनोरंजन के लिए सिनेमा और बच्चों के लिए झूले वगैरह भी रहेंगे।

निजी वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करेगी यह योजना : इन कॉमर्शियल हबों में पार्किंग छोटी रखी जाएगी, जबकि पार्किंग शुल्क काफी ज्यादा रहेगा। दूसरी तरफ मेट्रो से आने वाले यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए इस हब तक पहुंचने के लिए या तो स्काईवॉक बनाए जाएंगे या फिर स्टेशन से हब तक जाने को अंदर ही अंदर एक अलग वातानुकूलित रास्ता बनाया जाएगा।

> योजना का ड्राफ्ट तैयार है। 45 दिनों की समयावधि में जनता की ओर से जो आपत्तियां एवं सुझाव आए हैं, उन्हें समायोजित कर अब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जल्द ही इसे बोर्ड की बैठक में लगा दिया जाएगा।
> –तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुने गए पांच मेट्रो स्टेशन : इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डीडीए ने फिलहाल द्वारका सेक्टर-21, रोहिणी सेक्टर-18, मयूर विहार एक्सटेंशन, मुकुंदपुर और सरोजनी नगर-आइएनए मार्केट मेट्रो स्टेशन का चयन किया है। इसके बाद रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के प्रमुख जंक्शन, आइएसबीटी और रेलवे स्टेशनों के नजदीक भी ऐसे हब बनाए जाएंगे।

डीडीए और यूटीपैक के निर्देशन में तैयार होंगे यह हब : सभी हब डीडीए और यूटीपैक के निर्देशन में बिल्डरों द्वारा तैयार किए जाएंगे। अगर हब बनाने के लिए किसी एक बिल्डर के पास पर्याप्त जगह नहीं है तो कुछ बिल्डर मिलकर कुछ प्लॉटों को आपस में जोड़कर भी कॉमर्शियल हब बना सकते हैं। वैसे यहां डीडीए ने यह छूट भी रखी है कि जमीन पर जिसका मालिकाना हक हो, वह स्वयं भी हब बना सकता है। सरकारी जमीन होगी तो सरकारी विभाग भी बना सकेंगे। हब का पूरा प्रस्ताव और नक्शा तैयार हो जाने पर उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र डीडीए द्वारा गठित उस विशेष कमेटी से मिलेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद वहां टीओडी नीति के आधार पर सारा काम डीडीए की निगरानी में होगी।

घटेगा प्रदूषण और बिजली की मांग : योजना के मुताबिक जब अधिकाधिक लोग मेट्रो से ही आएंगे तो सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा। इससे प्रदूषण भी घटेगा। चूंकि सभी कॉमर्शियल हब ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर तैयार किए जाएंगे, इसलिए वहां बिजली की बचत भी सुनिश्चित हो सकेगी।

डीयू में पढ़ने वाले शहीद जवानों के बच्चों की फीस भरेगी एनएसयूआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर घोषणा की है कि वह इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दाखिला लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देगा। यह छात्रवृत्ति देश के सशस्त्र बलों के शहीद जवानों और बैंक कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर चुके किसानों के बच्चों को दी जाएगी। इस शैक्षणिक सत्र में डीयू के किसी भी कॉलेज के पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पर उनकी एक साल की फीस छात्र संगठन देगा। इसके लिए एनसएयूआइ की ईमेल आइडी nsuifordu@gmail.com पर आवेदन भेज सकते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बुधवार को प्रेसवार्ता में एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने यह जानकारी दी।

नीरज कुंदन ने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर संगठन चाहता था कि वह सिर्फ केक न काटे, बल्कि देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों और अन्नदाता किसानों को समर्पित करते हुए कुछ बेहतर पहल की जाए। हम अपने देश के जवानों और किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं।

अक्षय लाकड़ा ने बताया कि सेना, सुरक्षाबल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस जैसे सभी सशस्त्र बलों की सेवा में शहीद हुए जवानों के बच्चों की एक साल की डीयू की फीस संगठन भरेगा। यह पायलेट प्रोजेक्ट है। इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। इस योजना में शामिल होने के लिए छात्रों को हमारी ईमेल आइडी में रजिस्टर करना होगा। छात्र जिस भी जिले में रहते हैं, वहां जाकर हमारी टीम आवेदन करने वाले छात्र का पता भी लगाएगी कि उसने जो जानकारी दी है वह सही है कि नहीं। छात्र संगठन को चंदा मिलता है। इसी चंदे की बदौलत छात्रों की एक साल की फीस भरी जाएगी।

21 जून को बिहार से खाली हुई एकमात्र सीट के लिए नामांकन करेंगे केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हुई है।

लोस अध्यक्ष बनते ही सामने आई मांगों की लंबी फेहरिस्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सत्ता व विपक्ष के छोटे दलों ने अपने हितों की रक्षा के लिए लगाई गुहार
- विपक्षी दलों के सांसद लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत करने की मांग की

राजग के उम्मीदवार भाजपा सांसद ओम बिरला को अभी स्पीकर बने कुछ ही मिनट हुए थे और उनके सामने मांगों की फेहरिस्त लगनी सिर्फ विपक्षी दलों की तरफ से ही नहीं बल्कि राजग गठबंधन में दलों की तरफ से भी अपनी-अपनी मांगें रखी गईं। विपक्षी दलों के सांसद लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत करने की मांग रखते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे थे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के छोटे दल यह कह रहे थे कि आने वाले दिनों में उनकी आवाज को भी बुलंद करने का पर्याप्त मौका मिले। सभी की यह गुजारिश थी कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बाद बिरला सभी दलों के साथ समान व्यवहार करें।

लोकसभा में कांग्रेस के नवनिर्वाचित नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात पर चिंता जताई कि राजग सरकार के पहले के कार्यकाल में महत्वपूर्ण विधेयकों को चयनित संसदीय समिति के पास भेजने की परम्परा कम हो गई है। इस परम्परा को फिर से बहाल करने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से बिरला को संसद चलाने में पूरी मदद की पेशकश की लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि उन्हें विपक्षी दलों के साथ भी पूरा न्याय करना होगा ताकि वह आम जनता से जुड़े मुद्दों को खुल कर उठा सकें। कुछ इसी तर्ज पर आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने लोकसभा अध्यक्ष के जरिए सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि पिछले सदन में विभिन्न विधेयकों में 500 संशोधनों का सुझाव दिया गया लेकिन उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि, 'बगैर मजबूत विपक्ष के लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो सकता।' एआइएमआइएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब यह लोकसभा अध्यक्ष बिरला की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि सत्ताधारी पार्टी राजशाही में तब्दील न हो जाए। ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से मुखातिब हो कर कहा, 'मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपको संविधान ने बेशुमार शक्तियां दी हुई हैं। इन शक्तियों को आप सोच समझ कर लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें।'

राजग गठबंधन में शामिल अकाली दल और अपना दल ने भी अपनी मांग सामने रख दी कि किस तरह से सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बावजूद उनकी बात को कई बार सामने रखने में परेशानी आती है। यह इसलिए होता है कि छोटे दल होने की वजह से उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। विपक्ष के छोटे दलों ने भी यही बात सामने रखी और अपेक्षा जताई कि बिरला इस बात का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। सभी दलों को समान अवसर दिया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा।

नई दिल्ली में बुधवार को संसद भवन में अपने पिता से आशीर्वाद लेते नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। प्रेट्र

लोकलुभावन ताकतों के खिलाफ खड़ी हो न्यायपालिका : सीजेआइ

- रूस में एससीओ बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से राजग सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आजादी को न्यायपालिका की आत्मा बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को लोकलुभावन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। साथ ही संवैधानिक रीति-नीति को तहस-नहस होने से बचाना चाहिए। रूस के सोचि में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) में चीफ जस्टिसों की बैठक में सीजेआइ रंजन गोगोई ने मंगलवार को अपने भाषण में कहा कि न्यायपालिका की आजादी पर हमले करने वाले ऐसे लोकलुभावन हमलों के प्रति इस संस्था को खुद को तैयार और मजबूत रखना होगा।

चीफ जस्टिस ने अपने व्याख्यान को मुख्य तौर पर वैश्विक संदर्भों में ही रखा, लेकिन सांकेतिक तौर पर केंद्र की राजग सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लोकप्रिय ताकतों के उदय को भारतीय न्यायपालिका के लिए चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों के उदय से न्यायपालिका के सामने निष्पक्षता बचाने की चुनौती पैदा हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों की नियुक्ति राजनीतिक दबाव और प्रभाव से भी मुक्त होनी चाहिए। न्यायपालिका और विधायिका के टकराव की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका के लिए बहुत खतरनाक दौर बनता जा रहा है। कुछ आलोचक टकराव के इस दौर को क्लासिक उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने कहा, 'जजों को गैर-निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया जा रहा, जो बहुमत से निर्वाचित सरकार के फैसलों को पलट देते हैं।' गोगोई ने कहा, 'लोकप्रिय ताकतें इन दिनों प्रभावी होती जा रही हैं।' न्यायपालिका के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त मानते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस समय पूरे विश्व में कुछ ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं और इस कारण न्यायपालिका बहुत अधिक दबाव में है। उन्होंने कहा, 'कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि न्यायपालिका भी कई बार लोकप्रिय ताकतों के दबाव में आ जाती है।'

न्यापालिका को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा, 'न्यायिक संस्थाओं की स्वायत्तता को बचाने के लिए लोकलुभावन ताकतों के दबाव से खुद को मुक्त रखना होगा। जस्टिस गोगोई ने कहा, 'जजों की नियुक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए।' बता दें कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति में विधायिका की भूमिका की बात पहले भी कर चुकी है।

रंजन गोगोई की फाइल फोटो। रायटर

> जजों को गैर-निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया जा रहा, जो बहुमत से निर्वाचित सरकार के फैसलों को पलट देते हैं। **-भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई**

दूर नहीं हो रही राहुल की मनीष से नाराजगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : श्री आनंदपुर साहिब से लोकसभा चुनाव जीते मनीष तिवारी के रिश्ते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से नहीं सुधर पाए हैं। मंगलवार को पंजाब के सांसद राहुल गांधी के साथ दिखे, लेकिन उसमें मनीष तिवारी नहीं थे। इसके बाद से ही चर्चा आम हो गई है कि भले ही तिवारी सांसद बन गए हों, लेकिन राहुल गांधी की नाराजगी खत्म नहीं हुई है।

दरअसल, राहुल गांधी की नाराजगी 2014 से शुरू हो गई थी। 2009 से 2014 तक मनीष तिवारी लुधियाना से सांसद थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। उस समय जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए चेहरे ढूंढने पड़ रहे थे, तब मनीष तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि, उन्होंने इसका कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या बताया था, लेकिन इससे पार्टी हाईकमान खासा नाराज हो गया। 2014 में राहुल गांधी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेताओं व विधायकों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। तब श्री आनंदपुर साहिब से सांसद रहे रवनीत बिट्टू ने लुधियाना से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। चुनाव खत्म होने के बाद मनीष तिवारी काफी समय तक पार्टी में हाशिये पर रहे। लंबे समय बाद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया।

राहुल गांधी श्रीआनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी को टिकट देने के हक में नहीं थे। उन्होंने टिकट दावेदारों के पैनल को भी बदलने के लिए कहा, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मनीष के टिकट को लेकर अड़ गए। कैप्टन हर हाल में तिवारी को चुनाव लड़वाना चाहते थे। आखिर राहुल मनीष को टिकट देने पर सहमत हुए। तिवारी ने शानदार जीत भी अर्जित की।

पिछले सत्र में ही शुरू हो गई थी एक साथ चुनाव पर चर्चा की कवायद

बड़ा मद्दा ▸ इसके लिए संविधान में करने होंगे पांच संशोधन

चुनाव आयोग को भी करनी होगी भारी मशक्कत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर जो कवायद शुरू की उसकी शुरुआत पिछली मोदी सरकार में ही हो गई थी। 16वीं लोकसभा सचिवालय ने एक साथ चुनाव को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक की थी। ऐसी सिफारिशें विधि आयोग की ओर से भी होती रहीं और 1967 से पहले यही चलन भी रहा। वक्त की मांग है कि टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ा जाए। सहमति बनती है तो संविधान के पांच अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा और लोकसभा के कार्यकाल की तिथि निर्धारित करनी होगी।

इतिहास बताता है कि देश के पहले आम चुनाव 1951-52 के बाद 1957, 1962 और 1967 में एक साथ ही चुनाव हुए। यह तारतम्य तब टूटा जब 1968 और 1969 कुछ राज्य विधानसभा भंग हुई और 1970 में लोकसभा भी समयपूर्व भंग हो गई। 1999 में जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश दी थी। 2015 में राज्यसभा ने विधि आयोग की सिफारिश की जांच करते हुए भी ऐसा ही सुझाव दिया था। एक विचार था कि आधे राज्यों के चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं और बाकी के राज्यों के चुनाव 2021 के अंत में कराए जाएं।

वैसे एक साथ चुनाव की दशा में संविधान में पांच संशोधन करने होंगे। अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 को संशोधित करना होगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। फिलहाल अवधि संबंधित सदन की बैठक से निर्धारित होता है। इसे बदलकर एक तिथि तय करनी होगी। अनुच्छेद 85 में लोकसभा और विधानसभा के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विघटन संबंधी अधिकार हैं। एक साथ चुनाव की स्थिति बनाने के लिए कई राज्यों के विधानभा का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना होगा और इसके लिए अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। 174 में राज्यों की विधानसभा संबंधी विघटन के नियम हैं और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। पर इस मोड़ तक पहुंचने से पहले सभी दलों और राज्यों की सहमति लेना दुरूह होगा। यह बुधवार को भी दिखा जब कई दल बैठक में मौजूद ही नहीं हुए। वहीं इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को व्यापक तैयारी करनी होगी जो आसान नहीं है।

जनमत मुद्दा

क्या एक देश एक चुनाव प्रणाली से केंद्र सहित राज्य सरकारों को जनहित में काम करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

facebook.com/muddajagran

mudda@jagran.com

'एक देश एक चुनाव' भाजपा का नया छलावा : मायावती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बसपा प्रमुख मायावती ने 'एक देश एक चुनाव' को भाजपा का नया ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा ईवीएम की सुनियोजित धांधलियों के जरिए लोकतंत्र पर कब्जा किए जाने को लेकर उपजी गंभीर चिंता की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई होती तो मैं उसमें जरूर शामिल होती। 'एक देश एक चुनाव' के मसले पर पीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में मायावती शामिल तो नहीं हुईं लेकिन भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को ऐसी सोच, मानसिकता एवं कार्यकलापों से दूर रहना चाहिए, जिससे देश के संविधान एवं लोकतंत्र को आघात पहुंचता है। इतने विशाल देश में 'एक देश-एक चुनाव' के बारे में सोचना ही प्रथमदृष्टया अलोकतांत्रिक व गैर-संवैधानिक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव कोई समस्या नहीं हो सकते। न ही चुनाव को कभी धन के व्यय-अपव्यय से तौलना चाहिए। 'एक देश, एक चुनाव' की बात वास्तव में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हिंसा जैसी ज्वलंत समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास और छलावा है।

कांग्रेस की अर्जी पर चुनाव आयोग से जवाब तलब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव का मामला
- सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नोटिस भेज 24 जून तक जवाब देने को कहा

गुजरात में खाली हुई दो राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग को 24 जून तक जवाब देना है। 25 जून को कोर्ट मामले पर फिर सुनवाई करेगा।

अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गुजरात की दो राज्यसभा सीटें खाली हो गई हैं। चुनाव आयोग ने इन दोनों सीटों पर एक ही दिन पांच जुलाई को अलग-अलग उपचुनाव कराने की घोषणा की है।

जस्टिस दीपक गुप्ता एवं जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश कालीन पीठ ने कांग्रेस की याचिका पर वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा की दलीलें सुनने के बाद आयोग को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें चुनाव याचिका दाखिल की जा सके इसलिए इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है।

इससे पहले तन्खा ने गुजरात की दोनों राज्यसभा सीटों पर एक ही दिन अलग-अलग उपचुनाव कराने का चुनाव आयोग का फैसला रद करने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश उनके हक में है। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि वह फिलहाल मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उन्हें पहले यह देखना होगा कि जो सीट खाली हुई हैं वह आकस्मिक रिक्तियां हैं या विधायी रिक्तियां हैं। इस पर विचार की जरूरत है।

कांग्रेस ने याचिका में कहा है कि दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है। उसने चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है। असल में 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में भाजपा के 100 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 75 विधायक हैं। सात सीटें इस समय खाली हैं। अगर एक साथ चुनाव हुए और विधायकों ने सिर्फ एक बार वोट दिया तो कांग्रेस के पास एक सीट जीतने का मौका होगा। लेकिन अगर दोनों सीटों के लिए अलग-अलग वोटिंग हुई तो भाजपा दोनों सीटों को जीत सकती है क्योंकि विधानसभा में वह बहुमत में है। संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए।

बता दें कि एक बैलट पर एक ही उम्मीदवार को वोट डाला जा सकेगा। इस स्थिति में कांग्रेस एक सीट आसानी से निकाल लेगी क्योंकि उसके पास 75 विधायक हैं। लेकिन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, विधायक अलग-अलग वोट करेंगे। ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा। इस तरह भाजपा के विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वे दो बार वोट कर दोनों उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं।

कर्नाटक में गठबंधन सरकार चलाने में हर दिन पीड़ा से गुजर रहा हूं : कुमारस्वामी

चन्नापटना, एएनआइ : कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के एक बयान से राज्य में कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार के बीच दरार की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए उन्हें हर दिन जिस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है उसे वो बयां नहीं कर सकते। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्दरमैया ने कहा है कि गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है।

कुमारस्वामी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, 'मैं वादा करता हूं मैं आपकी उम्मीदों को पूरा करूंगा। जिस दर्द से मुझे रोज गुजरना पड़ रहा है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं आपसे अपना दर्द बताना चाहता हूं, लेकिन बता नहीं सकता। लेकिन मुझे राज्य के लोगों के दर्द को दूर करना है। सरकार को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी मेरी है।'

कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। भाजपा के एक नेता ने उनकी पार्टी के एक विधायक को भाजपा में शामिल होने पर 10 करोड़ रुपये देने का लालच दिया है। विधायक ने उन्हें फोन करके खुद यह जानकारी दी है। वहीं, नई दिल्ली में सिद्दरमैया ने बुधवार को कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। कोई समस्या नहीं है। भाजपा लगातार सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाया था। राजभवन में आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल वजूभाई वाला ने आर शंकर और एच नागेश को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को बेंगलुरु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। एएनआइ

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई भंग, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : पार्टी के भीतर बढ़ रही तनातनी को देखते हुए कांग्रेस ने बुधवार को अपनी कर्नाटक इकाई भंग कर दी। हालांकि, अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष अपने पदों पर बने रहेंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'एआइसीसी ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव नहीं किया गया है।'

हालिया लोकसभा चुनाव में राज्य में मिली करारी हार के बाद कर्नाटक कांग्रेस के भीतर तनातनी बढ़ गई थी। यहां तक कि राज्य की कांग्रेस-जदएस सरकार के साथ समन्वय में भी परेशानी आने लगी थी। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को लेकर मतभेद के बीच प्रदेश कांग्रेस में विरोध के सुर मुखर होने लगे थे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के दो सदस्यों को हाल ही में कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बाद कांग्रेस अपनी कर्नाटक इकाई को भंग कर दिया है।

अदालत ने जाकिर नाइक को दिया पेश होने का आदेश

मुंबई, एएनआइ : विशेष अदालत ने बुधवार को जाकिर नाइक को 31 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।

नाइक पर भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। वह जुलाई 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में भारत और बांग्लादेश दोनों जगह जांच का सामना कर रहा है। आतंकी हमले के दो संदिग्धों ने दावा किया था कि वे नाइक के कट्टरपंथी प्रचार से प्रेरित थे। ईडी ने नाइक के खिलाफ 22 दिसंबर 2016 को मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उस पर 193.06 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी 50.46 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच कर ली थी।

मलेशिया कर चुका है प्रत्यर्पण से इन्कार : जाकिर के अलग-अलग देशों में होने की खबरें मिलती रहीं, लेकिन वह इस समय मलेशिया में है। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत ने वहां की सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले वहां के प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद ने प्रत्यर्पण के अनुरोध को ठुकरा दिया था। हालांकि इसके जवाब में भारत ने कहा था कि वह उसके प्रत्यर्पण की कोशिश जारी रखेगा। बता दें कि जाकिर नाइक ने हाल ही में कहा था कि अगर उसे गिरफ्तारी से आजादी का भरोसा मिलता है तो वो भारत आने को तैयार है। हालांकि भारत की जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि किसी शर्त को माना नहीं जा सकता है।

जाकिर नाइक फाइल

केरल सरकार की मांग सबरीमाला पर केंद्र सरकार लाए कानून

तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र : केरल की माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह ऐसा कानून लाए जिससे सबरीमाला मंदिर में आने वाले भगवान अयप्पा के भक्तों के विश्वास की रक्षा हो सके। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खोलने का आदेश दिया था।

केरल के देवासोम मंत्री कडकंपल्ली सुरेंद्रन ने संवाददाताओं से कहा कि सबरीमाला मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष बतौर प्राइवेट बिल आएगा। हर किसी को पता है कि प्राइवेट बिलों का हश्र क्या होता है। दरअसल, भगवान अयप्पा के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी एक प्राइवेट बिल लोकसभा में इसी हफ्ते पेश होने वाला है। केरल के मंत्री सुरेंद्रन ने कहा कि ऐसे हालात न बनें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भाजपा नेतृत्व को केंद्र पर दबाव डालना चाहिए और कानून की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा का जबरदस्त बहुमत है और इसलिए उसे इस मामले में कोई कानून लाना चाहिए।

तैयारी

केंद्र की पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने तेज किए भूमि अधिग्रहण के प्रयास, प्रोजेक्ट की पड़ताल कर जापान ने बढ़ाया परियोजना में तेजी लाने का दबाव

फिर शुरू हुई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी की कोशिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही मोदी सरकार ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की बाधाएं दूर करने के उपाय शुरू कर दिए हैं। देश में आम चुनाव के कारण पिछले छह महीनों से परियोजना का काम काफी सुस्त हो गया था। हालांकि मोदी सरकार की सत्ता में पुनः वापसी के साथ ही जापान सरकार ने भी भारत पर परियोजना में तेजी लाने का दबाव बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार भी परियोजना को 2023 की नियत तिथि से पहले पूरा करने की इच्छुक है।

इस सिलसिले में जापान के महावाणिज्य दूत ने हाल ही में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों का दौरा कर परियोजना की प्रगति की पड़ताल की और अधिकारियों से अड़चनों का ब्यौरा लिया। यही नहीं, केंद्र की सलाह पर महाराष्ट्र सरकार ने भी परियोजना की भूमि अधिग्रहण संबंधी रुकावटों को दूर करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं।

गुजरात में हो चुका है 60 फीसद से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण : बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जरूरी 825 एकड़ जमीन में से अब तक गुजरात में 60 फीसद से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। हालांकि किसानों के विरोध के चलते महाराष्ट्र में न के बराबर जमीन अधिग्रहीत हो सकी है। यहां पालघर के 73 गांवों और ठाणे के 22 गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण में कानूनी रुकावटें आड़े आ रही हैं।

सितंबर 2017 में हुआ था परियोजना का भूमिपूजन : अहमदाबाद-मुंबई परियोजना भारत की पहली हाईस्पीड रेल परियोजना है जिसका कार्यान्वयन जापान की मदद से किया जा रहा है। इसके तहत अहमदाबाद और मुंबई के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 508 किलोमीटर लंबे हाईस्पीड कारीडोर के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 1.10 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए जापान ने 0.1 फीसद की नगण्य ब्याज दर पर 88 हजार करोड़ रुपये की राशि (81 फीसद) कर्ज के रूप में प्रदान करने का वादा किया है। शेष लागत रेलवे, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना का भूमि पूजन सितंबर, 2017 में ही हो गया था।

किसान और पर्यावरणविद बने प्रोजेक्ट की राह में बाधा : परियोजना के लिए लगभग 3600 किसानों की जमीन ली जानी है, लेकिन ज्यादातर किसान मुआवजे की कम दर के कारण जमीन देने को तैयार नहीं हैं। वे बाजार दर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों के अलावा पर्यावरणवादियों ने भी परियोजना के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा समिति के नाम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है, जिसका फैसला जुलाई तक आने की संभावना है। समिति को इस बात पर आपत्ति है कि परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी क्यों नहीं ली गई है। यही नहीं, समिति ने जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जीका) को भी पत्र लिखा है और उस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है, जिसे जीका के अधिकारियों ने गत दिसंबर- जनवरी में गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करने के बाद तैयार किया था।

बांग्लादेश व दक्षिण कोरिया में भी होगा डीडी इंडिया का प्रसारण

नई दिल्ली, प्रेट्र : पड़ोसियों से अपने रिश्ते मजबूत करने के क्रम में भारत सरकार ने बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ समझौते किए हैं। इनके तहत दूरदर्शन (डीडी) इंडिया का प्रसारण उन देशों में किया जाएगा, जबकि उनके टीवी चैनल डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध होंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'बांग्लादेश के स्वामित्व वाले टीवी चैनल बीटीवी वर्ल्ड का प्रसारण डीडी फ्री डिश पर किया जाएगा। यह चैनल भारत में डीडी के दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा। इसी प्रकार डीडी इंडिया का प्रसारण बांग्लादेश में किया जाएगा।'

सरकार ने प्रसार भारती के उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी, जिसमें भारतीय दर्शकों के लिए दक्षिण कोरिया सरकार के अंग्रेजी चैनल केबीएस वर्ल्ड का प्रसारण डीडी फ्री डिश पर करने की बात कही गई है। इसके तहत डीडी इंडिया का भी प्रसारण दक्षिण कोरिया में होगा। प्रसार भारती व बांग्लादेश टीवी के बीच का समझौता इसी साल सात मई को हुए एमओयू का परिणाम है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

10 साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी नियमित होंगे झारखंड सरकार में। कैबिनेट ने झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली-2015 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 20 जून 2019

महाराष्ट्र में बराबर का हक चाहती है शिवसेना

रखी बात ▸ मुख्यमंत्री फड़नवीस के सामने शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ने साफ किया अपनी पार्टी का रुख

कहा, आज हम सब एक साथ आए हैं, तो गठबंधन टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, हिंदुत्व के लिए रहेंगे एक

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

मुंबई में शिवसेना के 53वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस, पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे व उनके पुत्र आदित्य ठाकरे। प्रेट्र

शिवसेना ने अपने 53वें स्थापना दिवस पर साफ कर दिया है कि वह अगली विधानसभा में भाजपा से बराबरी का हक चाहती है। यह बात बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुंबई के खचाखच भरे षड्मुखानंद सभागार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के सामने कही। शिवसेना प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि आज हम सब एक साथ आए हैं, तो गठबंधन टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। हम हिंदुत्व के लिए एक रहेंगे। लेकिन बंटवारा बराबरी का होना चाहिए। बुधवार को शिवसेना के स्थापना दिवस समारोह में पहली बार मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

उद्धव द्वारा कही गई बराबरी के अधिकार की बात का अर्थ ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री पद से लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह स्पष्ट संदेश देने के लिए ही शिवसेना ने स्थापना दिवस में पहली बार भाजपा के किसी बड़े नेता को आमंत्रित किया था। शिवसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री को अपना व्यक्तिगत मित्र भी करार दिया। बुधवार को ही शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में साफ कहा गया है कि भाजपा से हमारा गठबंधन अवश्य है लेकिन शिवसेना तेवरवाला संगठन है। पार्टी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ी है। इसी संकल्प के आधार पर हम विधानसभा को भगवा करके छोड़ेंगे और 54वें स्थापना दिवस समारोह में शिवसेना का मुख्यमंत्री विराजमान होगा। इस संपादकीय के जरिये पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से इसी संकल्प को लेकर काम पर जुट जाने का आह्वान भी किया है। शिवसेना हमेशा से महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करती रही है। इसी महत्वाकांक्षा के कारण 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ 25 साल से चला आ रहा गठबंधन टूट गया था। भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने का उसे कोई लाभ नहीं मिला। वह भाजपा से आधी सीटों पर सिमटकर रह गई। चुनाव के बाद उसे भाजपा की ही शर्तों पर सरकार में शामिल होना पड़ा। उपमुख्यमंत्री का पद भी उसे नहीं मिल सका।

शिवसेना इस दुर्गति को भुला नहीं सकी। शिवसेना अध्यक्ष ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी भाजपा से अलग लड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों दलों में फिर से समझौता हो गया। जिसके फलस्वरूप गठबंधन राज्य की 48 में से 41 सीटें जीतने में कामयाब रहा। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी वह भाजपा के साथ नई शर्तों पर गठबंधन करने को तैयार हो जाएगी। दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले शिवसेना 171 पर और भाजपा सिर्फ 117 पर चुनाव लड़ा करती थी। अब शिवसेना को भाजपा की बढ़ती ताकत का अहसास हो चुका है। वह समझ चुकी है कि बराबर सीटों पर लड़कर उसके विधायकों की संख्या भाजपा से ज्यादा नहीं हो सकती है। ऐसे में अब वह भाजपा के सामने ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव रखना चाहती है।

अब बंगाल विधानसभा में गूंजा 'जय श्री राम' और 'जय हिंद'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण में तृणमूल-भाजपा की ओर से हुई नारेबाजी
- आठ सीटों के उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं भाजपा के चार विधायक

लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों के बाद अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए हैं। बुधवार को विधानसभा में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों ने शपथ लेने के बाद 'जय श्री राम' का नारा लगाया तो तृणमूल के विधायकों ने भी पलटवार में 'जय हिंद' का नारा लगाया। दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी को लेकर विधानसभा के स्पीकर नाराज हो गए और विधायकों को सतर्क किया।

लोकसभा चुनाव के साथ पश्चिम बंगाल में आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। बुधवार को नवनिर्वाचित विधायकों के लिए शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ लेने के बाद हबीबपुर से विधायक जेयेल मुर्मु ने जय श्री राम का नारा लगाया। इनके समर्थन में बाकी के भाजपा विधायकों ने भी 'जय श्री राम' का नारा बुलंद किया। इसे लेकर तृणमूल विधायकों ने ऐतराज जताया। इसके बाद जब बारी उलबेड़िया पूर्व से विधायक चुने गए इद्रिश अली की आई तो उन्होंने शपथ के बाद जय हिंद का नारा लगाया।

विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा कि नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि कोई भी विधायक सदन में नारेबाजी नहीं कर सकते। पहले ही विधायकों को इसकी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं विधायक सदन में कागज फाड़ कर भी नहीं फेंक सकते, फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है। बाद में जयेल मुर्मु ने कहा कि जानबूझ कर मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे अंदर से ही 'जय श्री राम' की ध्वनि निकल पड़ी, और फिर ईश्वर का नाम लेने में कोई बुराई भी तो नहीं है। वहीं, इद्रिश अली ने कहा कि 'जय हिंद' तो पूरे देश में बोला जाता है।

भाजपा विधायकों की संख्या हुई छह

बता दें कि विधानसभा की जिन आठ सीटों के लिए उपचुनाव हुए उनमें से चार सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि तृणमूल को तीन व कांग्रेस को एक सीट पर। इस तरह अब भाजपा विधायकों की संख्या बढ़ कर छह हो गई है। हालांकि, लोकसभा चुनाव के बाद हालिया दिनों में चार तृणमूल व एक माकपा विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया है।

न्यूज गैलरी

उप्र में निजी विवि में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के परिसरों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं हो सकेगा। निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कैबिनेट की ओर से मंगलवार को मंजूर किए गए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2019 के ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के मुताबिक, इसे निजी विवि की स्थापना की शर्तों में शामिल किया गया है। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को यह वचनबद्धता देनी होगी कि विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा और न ही विवि परिसर के अंदर या विवि के नाम से किसी को ऐसा करने की अनुमति होगी। विश्वविद्यालय में ऐसी गतिविधि पाए जाने पर इसे स्थापना की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। अध्यादेश के प्रावधानों या प्रचलित विधि के तहत राज्य सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकीकरण, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक समरसता, नैतिकता समेकन तथा देशभक्ति को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी शामिल किया गया है। (राब्यू)

'चुनाव में जब्त 3800 करोड़ रुपये की होगी जांच-पड़ताल'

कटक : देश में संपन्न हुए आम चुनाव के दौरान 3800 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। इनका मालिक कौन है, रुपये कहां से आए, इसकी जांच की जाएगी। यह बात स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) के उपाध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अर्जित पशायत ने कही है। देश में कालाधन जांच को लेकर कटक स्थित आवास पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस पशायत ने कहा कि चुनाव में लगाए गए कालेधन की गहन छानबीन के लिए चुनाव अधिकारी एवं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि एसआइटी आगामी दो महीने के अंदर जांच रिपोर्ट की सातवीं अंतरिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। इस साल संपन्न हुए देशभर के चुनाव में 3800 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। इसके साथ ही जब्त हजारों करोड़ रुपये की शराब व अन्य नशीले पदार्थों की जांच करने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो को कहा गया है। बैठक के दौरान विदेश में होने वाले कारोबार, आयात एवं निर्यात पर भी फोकस कर कालेधन की हेरफेर तथा टैक्स धांधली करने वाले कारोबारियों पर कड़ी नजर रखने का जस्टिस पशायत ने निर्देश दिया। (जासं)

हिमाचल प्रदेश में नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, शिमला

- 21 वर्ष की आयु तक 7500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे

हिमाचल सरकार बाल उत्पीड़न के शिकार नाबालिगों का आत्मविश्वास और स्वाभिमान वापस लौटाने का प्रयास करेगी। नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों व बाल उत्पीड़ितों के लिए पुनर्वास सहायता योजना शुरू कर इन्हें वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। इस योजना को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को लागू करने की कवायद में जुट गया है।

योजना के तहत सरकार नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों व बाल उत्पीड़न का शिकार हुए नाबालिगों को आजीविका समर्थन के रूप में 21 वर्ष की आयु तक 7500 रुपये प्रति माह देगी। इसके अलावा दुष्कर्म सहित अन्य बाल उत्पीड़न का शिकार नाबालिगों को सरकार उनके कौशल का विकास करने और उनके पुनर्वास के लिए भी काम करेगी। योजना के तहत पीड़ित नाबालिगों की प्रोफेशनल काउंसलर से काउंसिलिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा बाल उत्पीड़न का शिकार बने बच्चे के अभिभावकों की भी काउंसिलिंग होगी। इस तरह बाल उत्पीड़न का शिकार बने बच्चों में आत्मसम्मान लौटा कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास होगा।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना शुरू करने को मंजूरी दी। इस योजना में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत चल रहे बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को दस हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृति 10 लड़कों और 10 लड़कियों को मिलेगी। छात्रवृत्ति आठवीं, नौवीं, दसवीं, जमा एक व जमा दो कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में पहले दो स्थानों पर रहने वालों को दी जाएगी। इसमें प्रत्येक कक्षा से एक लड़का और एक लड़की को छात्रवृत्ति मिलेगी।

महिलाएं बनेंगी उद्यमी : महिला विकास निगम की योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1,50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा मिलती है। मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनकी पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इससे पहले केवल उन्हीं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाता था जिनके परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये वार्षिक थी।

ओडिशा : एम्स में भी इलाज करा सकेंगे बीजू स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण (बीएसकेवाइ) के लाभार्थियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज की सुविधा देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की उपस्थिति में एम्स भुवनेश्वर और स्वास्थ्य सचिव ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के सरकारी अस्पताल सहित 196 गैरसरकारी व निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया था। अब भुवनेश्वर के एम्स को भी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना से जोड़ दिए जाने से लाभार्थियों को उत्तम इलाज की सुविधा मिल पाएगी।

इसके अलावा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए ओडिशा कैंसर केयर फाउंडेशन का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। इस फाउंडेशन की पहली बैठक जुलाई में करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में कैंसर मरीजों को कटक के आचार्य हरिहर कैंसर संस्थान पर निर्भर होना पड़ रहा था। अब सरकार बारंग के निकट तथा भवानीपटना में अपेक्स कैंसर निदान केंद्र की स्थापना करने जा रही है, जिससे मरीजों को फायदा होगा।

चुनावी तल्खी भूल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल को दी जन्मदिन की बधाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राहुल भी जन्मदिन पर दिखे सक्रिय, पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की
- संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेसी सांसदों के साथ खिंचवाई फोटो

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलते हुए। प्रेट्र

लोकसभा चुनाव की तल्खी को भूलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की। गांधी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

49 साल के हो चुके राहुल गांधी भी अपने जन्मदिन पर सक्रिय दिखे। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। साथ ही उनकी शुभकामनाएं भी स्वीकार की। इससे पहले गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से उनके आवास पर मिले और आशीर्वाद लिया। द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी उन्हें ट्वीट के जरिये बधाई दी। द्रमुक ने राहुल के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'मैं अपने प्यारे दोस्त को जन्मदिन की बधाई देता हूं। दुआएं हैं कि वह वर्षों लोगों की सेवा करते रहें।'

जन्मदिन के मौके पर वह संसद में भी अलग रंग में दिखे। संसद परिसर में पंजाब के कुछ कांग्रेसी सांसद एक साथ फोटो खींच रहे थे, तभी गांधी का काफिला वहां से गुजरा। फोटोग्राफी होती देख गांधी भी रुक गए और पार्टी सासंदों के साथ फोटो खिंचवाई। गांधी के इस व्यवहार से पार्टी के पंजाब से चुनकर आए सांसद भी गदगद दिखे।

चंद्रबाबू के नदी किनारे वाले बंगले पर विवाद

अमरावती, आइएएनएस : आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व तेदेपा प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के नदी किनारे वाले बंगले को लेकर राज्य में नया विवाद पैदा हो गया है। वाइएसआर कांग्रेस के विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा है कि नायडू को नदी किनारे वाला बंगला छोड़ना होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) नेता पी. केशव ने कहा कि प्रदेश की नई सरकार बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में लंबित है। इसलिए वाइएसआर कांग्रेस विधायक की टिप्पणी अनुचित है।

रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि तेदेपा प्रमुख को बंगला खाली करना होगा, क्योंकि वह नदी की जमीन पर बना हुआ है। वाइएसआर कांग्रेस विधायक की यह टिप्पणी चंद्रबाबू द्वारा सरकार को लिखे गए उस पत्र के क्रम में आई है, जिसमें उन्होंने कृष्णा नदी के किनारे स्थित बंगला 'प्रजा वेदिका' का इस्तेमाल पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आदि के लिए करने की अनुमति मांगी थी। नायडू इस बंगले में वर्ष 2016 से रह रहे हैं, जब आंध्र प्रदेश का प्रशासन हैदराबाद से अमरावती स्थानांतरित हुआ था। 'प्रजा वेदिका' पूर्व सीएम का आधिकारिक आवास रहा। नेता विपक्ष होने के कारण फिलहाल नायडू के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी है।

तू-तू, मैं-मैं कर रहे दिग्गजों को घर बैठने की सलाह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- हरियाणा में नेताओं की आपसी लड़ाई पर महिला कांग्रेस की नाराजगी
- सुमित्रा ने कहा, पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है

हरियाणा में कांग्रेस दिग्गजों की आपसी लड़ाई के बीच महिला कांग्रेस ने 50 फीसद टिकटों पर अपनी दावेदारी जताई है। राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 45 टिकट महिला कांग्रेस ने मांगे हैं। संगठन के नेतृत्व और टिकट आवंटन के नाम पर आपस में लड़ने वाले दिग्गजों को घर बैठने की सलाह देते हुए महिला कांग्रेस ने गुरुवार से फील्ड में उतरने का एलान किया है। इस दौरान चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं से आवेदन मांगे जाएंगे। बूथ स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करने वाली महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी।

संगठनात्मक बैठक लेने चंडीगढ़ पहुंची हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रभारी अनुपमा रावत और प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने प्रांतीय पदाधिकारियों को निचले स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में तय हुआ कि अगले माह महिला कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सम्मेलन से पहले हर जिले में संगठन, टिकट के दावेदार और जीत सकने वाली उम्मीदवारों के नाम की रिपोर्ट बनाई जाएगी। यह सम्मेलन चंडीगढ़ या पंचकूला में छह व सात जुलाई अथवा 13 व 14 जुलाई को आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव शामिल होंगी। बैठक के बाद सुमित्रा चौहान ने कहा कि फील्ड में बूथ स्तर पर संगठन दिखाओ और टिकट की दावेदारी करो का नारा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता तू-तू, मैं-मैं की राजनीति में उलझकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी वजह से कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है, ऐसे तमाम नेताओं को अपने घर बैठ जाना चाहिए। पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, जबकि असलियत यह है कि ऐसे नेता अपनी जरूरत के लिए पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। सुमित्रा ने कहा कि आधी आबादी-पूरा हक का नारा बुलंद करते हुए महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी।

किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम भरेगी झारखंड सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड में किसानों के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी। गत वर्ष आधे से अधिक प्रखंडों में पड़े सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। कृषि मंत्री रणधीर सिंह से सोमवार को रांची में राज्यस्तरीय खरीफ कार्यशाला में यह घोषणा की। कहा कि गत वर्ष 129 प्रखंडों में पड़े सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए फसल बीमा के पूरे प्रीमियम के भुगतान का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सूखे के कारण खरीफ का आच्छादन कम हुआ था। गत वर्ष भी किसानों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार ने किया था। मंत्री ने कहा कि कई जिलों में फसल बीमा की राशि का भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया है। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल बीमा से संबंधित जितने भी क्लेम हैं उनका सेटेलमेंट 15 दिनों में किया जाए। कृषि मंत्री ने बताया कि 24 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना (सीएम किसान) की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी।

हरियाणा में भाजपा का विकल्प बनने को जोर लगा रहा इनेलो

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

अभय चौटाला फाइल फोटो

- ओमप्रकाश चौटाला ने कसे संगठन के पेंच, अब अभय संभालेंगे मैदान में मोर्चा
- कांग्रेस की गुटबाजी का लाभ उठाने की फिराक में चौटाला एक दिन में नापेंगे तीन हलके

हर बार लड़खड़ा कर संभलने में माहिर इनेलो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा का विकल्प बनने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इसके लिए पार्टी ने सौ दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है। इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल लौटने से पहले संगठन के कील-कांटे दुरुस्त कर गए। अब बारी इनेलो विधायक दल के नेता अभय सिंह चौटाला की है। चौटाला अगले 100 दिन तक लगातार मैदान में रहकर जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे।

हरियाणा के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके ओमप्रकाश चौटाला ने जिस तरह से संगठन में बदलाव किया है, उससे अभय सिंह चौटाला काफी मजबूत हुए हैं। इनेलो को शुरू से ही काडर बेस पार्टी माना जाता है। राज्य में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब इनेलो बिखराव का शिकार हुआ। मगर हर बार काडर बेस कार्यकर्ताओं के बूते फिर से खड़ा हो गया। लोकसभा चुनाव में भले ही इनेलो और अजय सिंह चौटाला व दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता दोनों को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से ओमप्रकाश चौटाला ने पार्टी से चले गए लोगों (अजय सिंह व दुष्यंत चौटाला) को वापस लेने से इन्कार कर दिया, उससे स्पष्ट है कि अब अभय सिंह चौटाला पार्टी कार्यकर्ताओं के बूते भाजपा के विरुद्ध लंबी और मजबूत पारी खेलने की तैयारी में हैं।

भाजपा की बड़ी जीत से बिखरा विपक्ष : हरियाणा में भाजपा ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीता है। इन नतीजों के बाद विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया है। कांग्रेस आधा दर्जन गुटों में बंटी है, जबकि जजपा को अपना वजूद बनाना पड़ रहा है। ऐसे में इनेलो को लग रहा कि इन 100 दिनों के भीतर यदि धरातल पर मजबूती के साथ काम कर लिया गया तो खुद को भाजपा के विकल्प के रूप में पेश करते हुए उसे कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इनेलो को अपनी इस मुहिम में कांग्रेस की गुटबाजी का लाभ मिलने के आसार हैं। पार्टी का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग-अलग होते हैं। ऐसे में लोगों से जुड़े मुद्दों के आधार पर अभय चौटाला गुरुवार से अपनी पूरी टीम के साथ फील्ड में सक्रियता बढ़ाते नजर आएंगे।

> हरियाणा में इनेलो का संगठन बेहद मजबूत है। जो लोग हमारी पार्टी में टूट होने की बात कहते हैं, उन्हें शायद यह अहसास नहीं कि हमारा कार्यकर्ता फौलाद है और कभी टूटता या हारता नहीं है। जिस तरह से श्रीराम का वनवास खत्म हुआ था, उसी तरह से अब हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं का वनवास खत्म हो चुका है। गैरवाजिब लोग संगठन से पहले ही चले गए। 30 जून तक सभी प्रकोष्ठों के साथ बैठकें कर संगठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। पहली जुलाई से प्रधान महासचिव, प्रदेशाध्यक्ष की टीम सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेगी। हर दिन तीन विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। इनेलो ही एकमात्र ऐसा दल है, जो भाजपा का विकल्प बन सकता है।
>
> **-अभय सिंह चौटाला, नेता इनेलो विधायक दल हरियाणा**

पिता का गुरु मंत्र आएगा काम, साथियों का मिलेगा सहयोग

इनेलो के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी ढालिया विधायक दल के नेता अभय के विश्वासपात्रों में शुमार हैं। चौटाला ने इस पूरी टीम को फील्ड में सक्रिय रहकर कार्यकर्ताओं के बूते भाजपा के विरुद्ध राजनीतिक जंग लड़ने का संदेश दिया है। चौटाला कार्यकारिणी में बदलाव और विस्तार भी कर चुके हैं। अब पिता ओमप्रकाश चौटाला के गुरुमंत्र पर अमल करते हुए अभय सिंह चौटाला जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन की मजबूती के साथ ही चुनाव लड़ने वाले दमदार चेहरों का चयन करेंगे। साथ ही विधानसभा सत्र के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त तैयार होगी, जिनके बूते चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसके बाद अभय चौटाला लगातार एक माह तक जुलाई में एक दिन में तीन-तीन विस क्षेत्रों को कवर करेंगे।

बड़ी मांग

हरियाणा में अकाली दल मांग रहा भाजपा से 30 विधानसभा सीटें, एक साथ इतनी सीटें देने के मूड में नहीं भाजपा

अकाली दल का दबाव बढ़ा तो रिश्ता तोड़ देगी भाजपा!

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा की 30 विधानसभा सीटों पर टिकट की दावेदारी जताते हुए शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके मद्देनजर नहीं लगता कि भाजपा हरियाणा में अकाली दल को अधिक अहमियत देगी। विधानसभा चुनाव में कम से कम 30 सीटें छोड़ने का अकाली दल का दबाव ज्यादा ही बढ़ा तो दोनों दलों की दोस्ती पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। भाजपा साथ छोड़ सकती है।

पंजाब में अकाली दल और भाजपा का बरसों पुराना साथ है। लोकसभा चुनाव में जब अकाली दल ने हरियाणा में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की थी, तब भरोसा दिलाया गया कि अकाली इस चुनाव में भाजपा का साथ दें, इसके एवज में अकाली दल के लिए विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें छोड़ी जा सकती हैं। उस समय सीटों की संख्या पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब अकाली दल ने हरियाणा में कम से कम 30 विधानसभा सीटें मांग ली हैं।

हरियाणा में भाजपा के लिए अकाली दल की अहमियत उतनी ही है, जितनी पंजाब में अकाली दल के लिए भाजपा की है। पंजाब में अकाली दल ने भाजपा को कभी पनपने नहीं दिया। इसी फार्मूले पर अब भाजपा हरियाणा में चल रही है और अकाली दल को उसकी मांग के अनुरूप किसी सूरत में 30 टिकट देने को तैयार नहीं है। भाजपा के प्रांतीय नेताओं का मानना है कि अगर अकाली दल वास्तव में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए पांच सीटें छोड़ी जा सकती हैं। यह सीटें कौन सी होंगी, इसका निर्धारण भी भाजपा खुद ही करेगी।

भाजपा की इस पेशकश पर यदि अकाली नेता तैयार नहीं हुए तो दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। दोनों दलों के बीच इन दूरियों का असर पंजाब में अकाली दल व भाजपा के रिश्तों पर पड़ना स्वाभाविक है। शुरू में अकाली दल के नेताओं को कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने की कोशिश रहेगी। इसमें सफलता नहीं मिली तो अकाली दल और भाजपा के रिश्ते जुदा होना तय हैं, जिसकी नींव हरियाणा से पड़ सकती है।

भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान 90 में से 79 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। इसके बावजूद पार्टी ने कम से कम 75 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बाकी 15 सीटों पर भी भाजपा ने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी, लेकिन उसका टारगेट 75 सीटें जीतने का ही है। इसमें यदि बढ़ोतरी होती है तो यह भाजपा के लिए बोनस होगा। इन्हीं 15 सीटों में से पांच सीटें भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी अकाली दल को देने की पेशकश कर सकती है।

सीटों के बंटवारे के लिए अकाली दल के नेताओं ने भाजपा हाईकमान से मांगा मिलने का समय

सीटों के बंटवारे के लिए अकाली दल नेताओं ने भाजपा हाईकमान से मुलाकात के लिए समय मांगा है। अकाली दल का दावा है कि हरियाणा की कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा और अंबाला लोकसभा सीटों की 15 से 20 विधानसभा सीटें सिख बाहुल्य हैं। पार्टी के मुताबिक, इन सीटों पर अकाली दल की पकड़ मजबूत है। इसलिए यह सीटें अकाली दल को आवंटित की जाएं। शुरू में हरियाणा में अकाली दल और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, मगर एसवाइएल नहर निर्माण के मुद्दे पर दोनों दलों के राजनीतिक रिश्ते खत्म हो गए। इसके बावजूद बादल व चौटाला परिवार के पारिवारिक रिश्ते अभी भी कायम हैं। यदि अकाली दल और भाजपा की राजनीतिक राहें जुदा हुईं तो चौटाला व बादल परिवार के राजनीतिक रिश्तों को ऑक्सीजन मिल सकती है।

> लोकसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के भरोसे के बाद अकाली दल मैदान से हट गया था। अकाली दल ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की पूरी मदद की, जिसके बाद भाजपा की सभी 10 सीटों पर जीत हुई। अब अकाली दल द्वारा अमित शाह को प्रस्ताव दिया गया है कि हरियाणा भाजपा व अकाली दल की संयुक्त बैठक हाईकमान की मौजूदगी में कराई जाए, जिसमें सीटों के आवंटन पर फैसला हो सके। अकाली दल हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
>
> **-बलविंदर सिंह भूंदड़, राज्यसभा सदस्य एवं प्रभारी, शिरोमणि अकाली दल हरियाणा**

10 हजार से कम आबादी वाले गांवों को भी महाग्राम योजना से जोड़ा जाएगा हरियाणा में। योजना में शामिल गांवों में पेयजल आपूर्ति बढ़ने के साथ सीवरेज की सुविधाएं भी लोगों को मिलेंगी। यह निर्णय सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड की बैठक में लिया गया।

हमारी सरकार डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक', मानव संसाधन विकास मंत्री

आचार्य से शुरू सफर को मिला अहम मुकाम

विकास धूलिया ● देहरादून

बात 1982-83 के आसपास की है। सरस्वती शिशु मंदिर उत्तरकाशी में एक युवा आचार्य सेवारत थे। नाम था रमेश। शिक्षण में निपुण लेकिन सबसे बड़ा गुण यह कि वह अपने छात्रों के घर जाकर उनकी शिक्षा और रुचि को लेकर अभिभावकों से संवाद करते थे। आज लगभग 36 साल बाद वही डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में देश की शिक्षा व्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में संभाले हुए हैं। बतौर शिक्षक अपने करियर की शुरुआत कर निशंक ने इसके बाद साहित्य, पत्रकारिता, फिर राजनीति में कदम रखा और सफलता के तमाम सोपान तय करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे।

अत्यंत गरीबी में गुजरा बचपन: डॉ रमेश पोखरियाल निशंक का बचपन अत्यंत गरीबी में गुजरा। पौड़ी गढ़वाल जिले के पिनानी गांव, जहां जन्म हुआ, वहीं प्राथमिक शिक्षा ली। रोजाना 15-16 किमी पैदल पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता था। इस दौरान दो बार मौत से भी सामना हुआ। पहली बार एक पहाड़ी नदी में बहे, किसी तरह दूसरे गांव की महिलाओं की मदद से नदी से निकले। दूसरी बार सर्दियों में बर्फ के बीच स्कूल जाते हुए अचानक सामने बाघ आ गया। मृत्यु निश्चित मान चुपचाप खड़े रहे। पांच मिनट बाद बाघ खुद ही जंगल की ओर चला गया।

शिक्षण के बाद पत्रकारिता: शिक्षण के साथ निशंक साहित्यिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। डॉ शंकर दयाल शर्मा उप राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने निशंक की पहली पुस्तक 'समर्पण' का लोकार्पण किया। कोटद्वार की साहित्यांचल संस्था ने वर्ष 1990 के आसपास 'निशंक' उपनाम दिया।' निशंक ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'दैनिक जागरण' से की। कोटद्वार में हिमालयी सरोकारों पर आधारित पत्रिका 'नव राह, नव चेतना' निकाली और फिर 1986-87 में सीमांत वार्ता समाचार पत्र आरंभ किया।

अटल जी के कहने पर राजनीति में प्रवेश: निशंक के मुताबिक, '1990 में अटल जी ने बुलाया और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने को कहा। कर्णप्रयाग सीट दिग्गज कांग्रेस नेता डॉ. शिवानंद नौटियाल की थी, वह नजदीकी रिश्तेदार भी थे। अपने परिवार के विरोध के बाद भी उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा और जीत दर्ज की। यह जिंदगी का दूसरा अहम पड़ाव था और यहीं से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई।'

28 वर्ष का सक्रिय राजनीतिक जीवन: निशंक वर्ष 1991 में पहली बार कर्णप्रयाग क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 2012 तक पांच बार, पहले उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य रहे। 1997 व 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री और फिर 2007 में भी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2009 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और इस पद पर लगभग सवा दो साल रहे। वर्ष 2014 में हरिद्वार सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और पूरे पांच साल लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति के सभापति के रूप में दायित्व संभाला। इस आमचुनाव में हरिद्वार से लगातार दूसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी मिली।

साहित्यिक सफर: 1983 में निशंक की पहली कविता संग्रह 'समर्पण' प्रकाशित हुई। अब तक 14 कविता संग्रह, 12 कहानी संग्रह, 11 उपन्यास, चार पर्यटन ग्रंथ, छह बाल साहित्य, चार व्यक्तित्व विकास सहित पांच दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देश-विदेश में कई भाषाओं में उनके साहित्य का अनुवाद हुआ है। युगांडा, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका, जर्मनी, हॉलैंड, रूस, नार्वे, जापान, इंडोनेशिया, भूटान सहित यूरोपीय देशों में सम्मान मिला है। देश-विदेश की 300 से अधिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्र गौरव, भारत गौरव, प्राइड ऑफ उत्तराखंड एवं यूथ आइकन अवार्ड दिए गए हैं।

पहाड़ के लिए समर्पित व्यक्तित्व

एक कार्यक्रम में डॉ अनिल प्रकाश जोशी से मिलते डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ● फाइल फोटो

शिक्षक से लेकर सियासत की ऊंचाईयां छूने तक के निशंक के सफर को प्रसिद्ध पर्यावरणविद् पद्मश्री डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने बेहद करीब से देखा है। डॉ. जोशी ने बताया, 'निशंक से मेरा परिचय 1979 में तब हुआ, जब मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में शिक्षक था। 1991 में वे पहली बार कर्णप्रयाग सीट पर कांग्रेसी दिग्गज शिवानंद नौटियाल को टक्कर देने चुनाव में उतरे थे। तब हम सभी ने निशंक का मजाक उड़ाया कि वह किस दिग्गज से लोहा ले रहे हैं। चुनाव में निशंक ने अपने विस क्षेत्र के कोने-कोने का दौरा कर एक-एक घर को छाना, मैं इसका साक्षी हूं। निशंक की मेहनत रंग लाई और वह चुनाव जीत गए। निशंक एक ऐसा व्यक्तित्व है, जो अपनी धुन में लगा रहता है और हमेशा पहाड़ के लिए समर्पित भाव से जुटे रहना उनकी सबसे बड़ी खासियत है।'

न्यूज गैलरी

बंगाल में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दर्जी की दुकान की आड़ में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। पुलिस ने अभियान चला आरोपित शौकत को गिरफ्तार कर लिया। वह पेशे से दर्जी है। उसके पास से सात सिंगल लांग बैरल पाइपगन, एक 7एमएम पिस्तौल, एक वन शॉटर पाइप गन, 29 कारतूस, मैगजीन और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस को मंगलवार रात शौकत की फैक्ट्री में अवैध हथियार मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने शौकत के घर छापेमारी कर उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। शौकत लंबे समय से अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री कारोबार से जुड़ा था। (जासं)

मेघालय, हरियाणा व पंजाब से चुनी गईं बेस्ट सेल्फी विद डॉटर

जींद : सेल्फी विद डॉटर उत्सव में 27 हजार से ज्यादा बेटियों के साथ भेजी गई सेल्फी में मेघालय, पंजाब और मेवात से तीन बेस्ट सेल्फी चुनी गईं। बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्हें सम्मानित किया। सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक व बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि मेघालय से हितेश व उनकी लाडो यादवी, पंजाब से नवजोत व उनकी लाडो सुमेल और हरियाणा के मेवात के दाऊद व उनकी लाडो महरू निशा को सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी ने सुनील जागलान को अभियान को सफल बनाने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार इस अभियान की तारीफ कर चुके हैं। (जासं)

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्वास्थ्य जांच को पहुंचीं मेदांता

गुरुग्राम : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी बुधवार को मेदांता अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराने पहुंचीं। वह सुबह साढ़े दस बजे अस्पताल पहुंचीं और दोपहर साढ़े तीन बजे वापस दिल्ली लौट गईं। सूत्रों ने बताया कि फिजिशियन डॉ. सुशीला कटारिया की देखरेख में केंद्रीय मंत्री के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान अल्ट्रासाउंड व अन्य पैथ लैब में उनकी जांच कराई गई है। मंत्री को रसौली संबंधित परेशानी बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। (जासं)

केंद्रीय मंत्री पटेल का बेटा 24 घंटे के रिमांड पर

नरसिंहपुर (मप्र) : मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के गोटेगांव गोलीकांड मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल के गिरफ्तार बेटे प्रबल को न्यायालय ने 24 घंटे के रिमांड पर पुलिस को दिया है। वहीं, बाकी छह आरोपितों को एक जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में गिरफ्तार सभी सात आरोपितों को बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय कुमार चौहान की कोर्ट में पेश किया गया था।

मानसून की धीमी चाल से सब परेशान, बढ़ी सूखे की आशंका

बिगड़े हालात ▶ जून में अब तक औसत से 44 फीसद कम हुई बरसात

उपभोक्ताओं की मांग, अर्थव्यवस्था की चाल और बाजार के हाल पर पड़ेगा व्यापक असर

मौसम की मार : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित एक जलाशय, जो लगभग पूरी तरह सूख चुका है। एपी

मुंबई, रायटर : भारत में मानसून की चाल औसत से भी धीमी है। इसकी वजह से मानसून केरल में करीब एक हफ्ते देर से पहुंचा है। जून के महीने में अब तक बारिश भी औसत से 44 फीसद कम हुई है। इसके चलते बारिश पर आधारित खेती चौपट होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में भीषण सूखे की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है।

बारिश में कमी से उपभोक्ताओं की मांग, अर्थव्यवस्था की चाल और बाजार के हाल पर बहुत गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने इस साल औसत बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं, मौसम का हाल बताने वाली देश की इकलौती प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने औसत से कम बारिश का अनुमान जताया है।

आइएमडी के मुताबिक, सामान्य या औसत मानसून से मतलब जून से सितंबर के चार महीने के दौरान पिछले 50 साल के औसत 89 सेंटीमीटर (35 इंच) बारिश का 96 और 104 फीसद के बीच बरसात होना होता है। 90 फीसद से कम बारिश को कम बरसात की श्रेणी में रखा गया है, जो सूखे जैसी स्थिति के समान होता है। 2018 में देश में औसत से नौ फीसद कम बरसात हुई थी। कुछ क्षेत्रों में तो यह कमी 37 फीसद तक दर्ज की गई थी।

इसी तरह अगर 110 फीसद से ज्यादा बारिश होती है तो इसका मतलब है कि मानसून औसत से भी बेहतर है। इसका भी नुकसान है। इससे कहीं बाढ़ का खतरा पैदा होता है कुछ फसलों की उपज भी कम हो सकती है। पहली जून को केरल में बारिश के साथ मानसून की शुरुआत होती है और जुलाई के मध्य तक मानसून पूरे देश में फैल जाता है।

इस साल का क्या है हाल : इस साल केरल में मानसून एक हफ्ते की देरी से आठ जून को पहुंचा। वहीं, अरब सागर में पैदा हुए चक्रवाती तूफान 'वायु' ने इसकी नमी को सोख लिया, जिससे इसकी चाल धीमी हो गई है। आमतौर पर 15 जून तक आधे देश में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस साल देश के एक चौथाई हिस्से तक ही अभी मानसून पहुंचा है।

कम बारिश की आशंका : आमतौर पर देखा गया है, जिस साल मानसून में देरी होती है उस साल कम बरसात भी होती है। इस साल भी अब तक 44 फीसद कम बारिश हुई है। 2016 में भी केरल में आठ जुलाई को मानसून पहुंचा था, लेकिन पूरे देश में मानसून के पहुंचने में देरी हुई थी और वह 13 जुलाई तक पहुंचा था। इससे औसत बारिश हुई।

फसलों को हो सकता है नुकसान : भारत में मानसून अपने साथ 70 फीसद बरसात लेकर आता है। मानसूनी बरसात से ही धान, गेहूं, गन्ना और सोयाबीन जैसे तिलहन की खेती का भविष्य तय होता है। भारत की 2.5 खरब की अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा भले ही 15 फीसद है, लेकिन देश की 130 करोड़ में से 50 फीसद आबादी खेती पर ही निर्भर है। अच्छे मानसून से पैदावार बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामान की मांग में वृद्धि होती है।

पीएम के वादे पर पड़ेगा प्रभाव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का वादा किया है। कम बारिश से इस पर असर पड़ सकता है। उपभोक्ता सामान का उत्पादन करने वाली कंपनियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग कम हुई है। अगर बारिश अच्छी होगी तो पैदावार भी बढ़ेगी और पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें काबू में रहेंगी।

भयानक सूखे की चपेट में आधा बिहार पानी बिन किसान बेचैन, खेत प्यासे

राज्य ब्यूरो, पटना

- 15 जिलों में 10 फीसद भी नहीं हो सकी है बारिश
- पांच जिलों में बारिश की स्थिति शून्य बता रहे प्रदेश सरकार के आंकड़े

आधा से ज्यादा जून बीत गया। पूर्वा नक्षत्र भी खत्म हो गया। उत्तरा नक्षत्र में भी अभी तक धान के बिचड़े लग नहीं पाए हैं। बिहार के किसान बेचैन हैं। खेत प्यासे हैं। बीज है, किंतु पानी नहीं है। बारिश का इंतजार है। मानसून की तिथि रोज आगे खिसक रही है। मानसून पूर्व होने वाली बौछारों ने भी दगा दिया है। जून में अभी तक 15 जिलों में 10 फीसद से भी कम बारिश हुई है। बिहार सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पांच जिलों में बारिश की स्थिति शून्य है। बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद जिलों में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने सीमांचल के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे बिहार को हाई अलर्ट पर रखा है। पिछले साल के सूखा प्रभावित 280 प्रखंडों को अभी तक सूखाग्रस्त घोषित कर रखा है। मौसम का मिजाज बता रहा है मानसून की नीयत भी ठीक नहीं है। प्रारंभ में जून के पहले सप्ताह में आने का अनुमान था। दो सप्ताह बाद भी बिहार के बाहर ही अटका है। कृषि विभाग के आंकड़ों के हिसाब से 19 जून तक अनुमानित आंकड़ों से 52 फीसद कम बारिश हुई है। पिछली बार यह आंकड़ा 23 फीसद था। 2017 में 19 जून तक सिर्फ 13 फीसद कम बारिश हो सकी थी। पिछले साल इस समय तक 81.1 मिमी बारिश हो चुकी थी। अबकी महज 29.2 मिमी ही हो सकी है। जाहिर है, बारिश का ग्राफ साल दर साल गिर रहा है। पिछले साल की तुलना में तो अबकी अभी तक आधी बारिश भी नहीं हो सकी है। इसका सीधा असर धान के बिचड़े पर पड़ रहा है। अभी तक सिर्फ 19.65 फीसद ही बिचड़े लग सके हैं। 11 जिलों में तो बिचड़ा लगाना शुरू भी नहीं हुआ है। पटना समेत 10 जिलों में यह आंकड़ा 10 फीसद भी नहीं पार कर सका है। हालांकि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया एवं सुपौल की स्थिति थोड़ी ठीक है। इन जिलों में 50 फीसद से ज्यादा आच्छादन हो चुका है। धान की तरह मक्के का हाल भी बुरा है।

> अभी मानसून का इंतजार है। राज्य में पिछले साल से 280 प्रखंड सूखा प्रभावित हैं। जबतक स्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक इन प्रखंडों को सूखा मानकर किसानों को राहत दी जा रही है। डीजल सब्सिडी, कृषि इनपुट एवं अन्य तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं।
> **-दीपक कुमार, मुख्य सचिव, बिहार**

बारिश का हाल (19 जून तक)

शून्य बारिश वाले जिले : बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद

पांच फीसद से कम : कैमूर, गया, नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा

10 फीसद से कम : सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुंगेर, बांका,

धान के बिचड़े की स्थिति

अभी तक शुरू भी नहीं : नवादा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बांका, सारण

10 फीसद से कम : पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, सिवान, शिवहर, भागलपुर

(नोट : स्रोत - कृषि विभाग, बिहार सरकार)

मांग आधारित खेती हो रही सफल

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

- रेगिस्तान में संतरा तो गंगा के मैदान में होने लगा केले का उत्पादन

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की माटी में उम्दा किस्म का संतरा होने लगा है। आंवला व बेल जैसे फल दक्षिणी राज्यों में नहीं होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से हर साल पहुंच रहे लाखों पौधों से व्यावसायिक खेती होने लगी है। यही हाल केला व अमरूद समेत अन्य कई फलों का है, जो गैर परंपरागत क्षेत्रों में धमाल मचा रहे हैं। इससे किसानों को तो लाभ हो ही रहा है, उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर ताजा उत्पाद उपलब्ध हो जा रहे हैं।

देशभर के खानपान में प्रमुखता से शामिल आलू की खेती भी गैर उत्पादक क्षेत्रों में होने लगी है। राजस्थान जैसे गरम प्रदेश में भी आलू की खेती होने लगी है। आइटीसी यहां आलू के उन्नत बीज तैयार कर रही है। यहां की मिट्टी में आलू को नुकसान पहुंचाने वाले रोग व कीटाणु नहीं लगते। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात का केला सबसे ज्यादा साल भर आता था, लेकिन अब यहीं इसकी व्यावसायिक बागवानी होने लगी है। मांग के हिसाब से कृषि उत्पाद तैयार करने की देशव्यापी योजना को और बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) में बागवानी के उप महानिदेशक डॉ. एके सिंह वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि इस अभियान को सघन तरीके से चलाने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ संबंधित राज्यों को भी आगे आना होगा। इससे किसानों में गैर परंपरागत खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने गर्व से बताया कि उत्तर प्रदेश में केले की व्यावसायिक खेती नहीं होती थी, लेकिन किसानों को जागरूक करने के साथ इसके फायदे गिनाए गए। नई फसलों की खेती में भरोसा होते ही किसानों ने इसे अपना लिया। केले की सर्वाधिक खेती पूर्वांचल के साथ तराई के जिलों में होने लगी है।

उत्तर भारत की बागवानी उत्पादों में आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला और बेल लखनऊ और आसपास के जिलों में केंद्रित थी। अब इसकी व्यावसायिक खेती तमिलनाडु और कर्नाटक में भी होने लगी है, जिसका फायदा वहां के किसान उठा रहे हैं। कम बारिश और ज्यादा गर्मी वाले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देश का सर्वोत्तम संतरा पैदा होने लगा है। डॉ. सिंह का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जरूरी खाद्य पदार्थों को पहुंचाने में भारी लागत आती है। स्थानीय स्तर पर खेती होने से जहां उपभोक्ताओं को ताजा उत्पाद सस्ती दर पर मिलने लगेगा, वहीं किसानों को भी फायदा मिलेगा।

ई-वाहनों को पंजीकरण शुल्क से मिल सकती है छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र: पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) को पंजीकरण शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर)-1989 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि बैटरी से चालने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या उसका नवीकरण कराने में और नया रजिस्ट्रेशन मार्क देने के मामले में शुल्क से छू दी जाएगी।

यह छूट सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगी, जिसमें दोपहिया वाहन भी शामिल होंगे। अधिसूचना के मसौदे में इस तरह की छूट देने के लिए नियमावली के नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर विभिन्न पक्षों की राय एक महीने में आमंत्रित की गई है।

अधिसूचना के मसौद में कहा गया है कि भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रति के प्रकाशित होने के 30 दिनों के बाद मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न पक्षों से मिली टिपणियों पर केंद्र सरकार गौर करेगी।

योग व विश्वकप का बेजोड़ संगम...

इन दिनों लोगों पर क्रिकेट विश्वकप का खुमार चढ़ा हुआ है, वहीं 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। चेन्नई में स्कूल के छात्रों ने योग और क्रिकेट विश्वकप का जोड़ इस तरह किया और योगाभ्यास के जरिये कप की तस्वीर तैयार कर दी। रायटर

दाभोलकर मामले में सीबीआइ ने फिर मांगी पुनालेकर की हिरासत

पुणे, प्रेट्र : सीबीआइ ने नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में फिर से वकील संजीव पुनालेकर को हिरासत में लेने की मांग की है। जांच एजेंसी ने कहा है कि मामले में जांच के दौरान जब्त गजेट से मिली कुछ सामग्री के संबंध में उससे पूछताछ करने की जरूरत है।

सीबीआइ ने बुधवार को अपने विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) आरएम पंडे से अनुरोध किया। कोर्ट गुरुवार को अपना आदेश सुनाएगा। इसी कोर्ट में पुनालेकर की जमानत पर भी सुनवाई होगी। पुनालेकर और विक्रम भावे को सीबीआइ ने 25 मई को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में बंद हैं। जांच एजेंसी ने चार जून को हिरासत में लेने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बुधवार को दाखिल अर्जी में कहा है, 'कुछ दस्तावेज और पुनालेकर के कार्यालय से बरामद गजेट से प्राप्त सामग्री के आधार पर हमें उनसे पूछताछ करनी है। इसीलिए सीबीआइ हिरासत की मांग कर रही है।' पुनालेकर पर दाभोलकर के कथित शूटर शरद कलास्कर को हत्या में प्रयुक्त हथियार नष्ट करने का सुझाव देने का आरोप है।

तैयारियां पूरी

प्रभात तारा मैदान में आयोजन की तैयारियां पूरी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करने का दिख रहा क्रेज, दो दिन में ही 50 हजार रजिस्ट्रेशन

रांची में पीएम संग 50 हजार से अधिक लोग करेंगे योग

राज्य ब्यूरो, रांची

पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मेजबान रांची पूरी तरह योग के रंग में रंग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। यही वजह है कि पीएम के साथ योग करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी तेज गति से चली कि दो दिनों में ही 50 हजार लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। लोग इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन को उत्सुक दिखे, लेकिन सीटें फुल होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को निराश होना पड़ा।

21 जून को रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में 50 हजार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार 20 जून को भारतीय वायुसेना के विमान से रांची पहुंच जाएंगे। राजभवन में वह रात्रि विश्राम करेंगे।

45 मिनट का होगा योगाभ्यास : प्रधानमंत्री भगवान बिरसा की धरती से लोगों को अपनी जीवनशैली में योग को शामिल करने का संदेश देंगे। वह पूरी दुनिया के योग प्रेमियों को यहां से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई भी देंगे। सुबह साढ़े छह बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत 45 मिनट का योगाभ्यास होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री योग प्रेमियों को संबोधित करेंगे।

दूसरे राज्यों और देशों से भी आ रहे हैं लोग : इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई दूसरे राज्यों व देशों के प्रतिनिधि भी रांची पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्य कार्यक्रम में लगभग 35 हजार लोगों के लिए योग करने की व्यवस्था की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बगल के नेहरू स्टेडियम में भी व्यवस्था की गई है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम स्थल पर योग के लिए लगाए गए मैट। जागरण

पीएम के योग को लाइव दिखाएगा उत्तर प्रदेश के गोंडा का लाल

अजय सिंह, गोंडा : उप्र स्थित गोंडा के हेमंत त्रिपाठी योग दिवस पर रांची में होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सोशल मीडिया पर करेंगे। उनकी कंपनी को आयुष मंत्रालय ने यह जिम्मा सौंपा है। जिले के मझवा गांव के मूल निवासी, बडगांव गोंडा के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले हेमंत त्रिपाठी (37) योग दिवस के कार्यक्रम की कवरेज के लिए रांची निकल चुके हैं। रांची रवाना होने से पहले गोंडा पहुंचे हेमंत ने बताया कि सोशल मीडिया पर पूरे कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए 15 लोगों की टीम लगेगी। सोशल मीडिया के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर प्लेटफार्म के साथ ही आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भी पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उनकी टीम के ही जिम्मे होगा।

टिफिन धोने को लेकर विवाद दो घंटे देरी से उड़ा विमान

- पायलटों को विमान में घर से खाना लाने पर प्रतिबंध लगा सकता है एयर इंडिया
- विमान एआइ 772 के कैप्टन और केबिन क्रू के बीच हुआ था विवाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : बेंगलुरु से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाला विमान एआइ 772 के कैप्टन और केबिन क्रू के बीच टिफिन धोने को लेकर हुए विवाद के कारण दो घंटे की देरी उड़ान भर सका। सोमवार को यह विमान 11:40 पर उड़ान भरने वाला था। दोनों को इस विमान से हटा दिया गया है। इस विवाद के बाद एयर इंडिया पायलटों को विमान में घर से खाना लाने पर प्रतिबंध लगा सकता है।

कैप्टन ने खाना खाने के बाद क्रू मेंबर को टिफिन धोने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेशनल कैरियर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सोमवार को जो कुछ हुआ उसे हमने गंभीरता से लिया है। हम जल्दी ही पायलटों को अपने घर से विमान में खाना नहीं लाने के लिए कहेंगे।' एक दूसरे अधिकारी ने कहा, 'मुझे बताया गया है कि कैप्टन ने खाना खाने के बाद केबिन क्रू मेंबर से टिफिन साफ करने के लिए कहा था। संभवतः यही उनके बीच विवाद का कारण था। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। कठोर कार्रवाई की जाएगी।' इससे पहले 27 मार्च को एयर इंडिया ने अपने पायलटों को उड़ान के दौरान विशेष खाने का आर्डर नहीं देने के लिए कहा था। इसका कारण यह है कि उन्हें कंपनी द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार ही खाना दिया जाना है। पायलट अपने लिए बर्गर, सूप, तली हुई मछली जैसी चीजों का आर्डर दे रहे थे जिसे देखते हुए यह निर्देश दिया गया।

33 जिलों में गुजरात के बनेंगे एससी-एसटी के लिए विशेष अदालतें, यहां फिलहाल 16 जिलों में इस तरह की अदालतें चल रही हैं। यह जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 20 जून 2019

अब नापाक हरकत पर सेना साधेगी सटीक निशाना

नवीन नवाज, जम्मू

▶ सीमा पर बैरेट एम 95.50 और .338 लापुआ मैग्नम आधुनिक स्नाइपर राइफलों से लैस हुई सेना

अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर अक्सर भारतीय सैनिकों को स्नाइपर शूटिंग से निशाना बनाने वाली पाकिस्तानी सेना अब घबराई हुई है। पिछले दो-तीन माह से सीमा पर हमारे जवानों को निशाना बनाने के लिए उसने स्नाइपर शूटिंग, घुसपैठ या बैट (बार्डर एक्शन टीम) के हमले की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। दुश्मन में यह खौफ भारतीय सेना की सजगता के साथ नई बैरेट एम 95.50 बीएमजी और ब्रेटा स्कार्पियो टीजीटी विक्ट्रिक्स .338 लापुआ मैग्नम स्नाइपर राइफलों से आया है। जब से हमारे स्नाइपरों के हाथों में (भेदक शक्ति) ये स्नाइपर राइफलें आईं हैं, दुश्मन थर्राया हुआ है।

भारतीय सेना के स्नाइपर अब तक रूस निर्मित द्रागनोव स्नाइपर राइफल इस्तेमाल करते आए हैं। इसकी मार 800 मीटर तक ही है और यह गैस आप्रेटिंग रोटेटिड बोल्ट है। इसके विपरीत पाकिस्तानी सेना के स्नाइपर अमेरिकी फौज द्वारा इस्तेमाल की

सेना को मिलने वाली बैरेट एम 95.50 आधुनिक स्नाइपर राइफल। फाइल फोटो

जाने वाली एम4 सीरीज की स्नाइपर इस्तेमाल करते हैं, जो डेढ़ से दो किलोमीटर तक मार करती है।

पूरे सेक्टर स्नाइपर राइफलों से लैस : सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना ने अब जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर तैनात अपने स्नाइपरों को इन अत्याधुनिक राइफलों से लैस करना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया गत मार्च माह में शुरू की गई और इस समय पूरे सेक्टर में सभी चिन्हित जगहों पर स्नाइपर इन राइफलों से लैस हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के कुछ स्नाइपरों को भी यह राइफलें दी गई हैं।

अमेरिका और इटली से बुलाए ट्रेनर : सैन्य अधिकारी ने बताया कि बैरेट एम 95.50 बीएमजी और .338 लापुआ मैगनम को इस्तेमाल किए जाने के बारे में जानकारी देने के लिए अमेरिका और इटली से विशेषज्ञ ट्रेनर व इंस्ट्रक्टर भी यहां बुलाए गए थे। पहले चरण में एलओसी पर तैनात विभिन्न सैन्य यूनिटों के स्नाइपरों को ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद अन्य स्नाइपरों को उनके क्रमानुसार इनकी जानकारी दी जा रही है।

जवाबी प्रहार के डर से दुस्साहस नहीं करेगा पाकिस्तान : सैन्य अधिकारी ने बताया कि पुंछ और गुलमर्ग सब सेक्टर के अलावा गुरेज में भी इन राइफलों से लैस हमारे स्नाइपरों ने पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों व निगरानी पोस्टों को प्रभावी तरीके से निशाना बनाया है, जहां से आतंकियों को हमारे इलाके में घुसपैठ कराई जाती है।

उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कहते कि पाकिस्तानी सेना के स्नाइपर हमेशा शांत बैठेंगे या बैट कारवाई भविष्य में कभी नहीं होगी, लेकिन अब वह पहले की तरह इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमारा जवाबी प्रहार उन्हें भारी जानी नुकसान पहुंचाएंगे।

बैरेट एम 95.50 की खासियत
किसी भी कठोर धातु को भेदने में सक्षम
दो किलोमीटर तक मारक क्षमता
अमेरिका में निर्मित बैरेट एम 95.50 बीएमजी एंटी मैटेरियल राइफल है। इसे एएमआर भी कहते हैं।
338 राइफल की खासियत
ढाई किमी दूर तक स्टीक मार करने की क्षमता।
सैन्य बख्तरबंद वाहन अथवा शील्ड को भेद सकती है।
338 लापुआ मैगनम की प्रहार शक्ति को अफगानिस्तान और इराक युद्ध में देखा जा चुका है।

समय पर जमीन न मिलने पर राज्यों से छिनेंगे मंजूर किए गए केंद्रीय संस्थान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वीकृत संस्थानों के लिए राज्यों से समय पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। निशंक ने कहा कि यदि राज्य ऐसा नहीं करते हैं तो एक तय समय सीमा के बाद संस्थानों की स्वीकृति वापस ले ली जाएगी। सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पोखरियाल ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी।

निशंक का जमीन नहीं मिलने पर राज्यों से स्वीकृत संस्थानों को छीनने का यह निर्देश इसलिए अहम है, क्योंकि गृह राज्य उत्तराखंड में भी जमीन नहीं मिलने के चलते एनआइटी श्रीनगर का काम सालों से लटका पड़ा है। इस दौरान उन्होंने मंत्रालय के कामकाज को लेकर पांच साल और एक-एक साल की योजना बनाए जाने की जानकारी भी साझा की। साथ ही बताया कि मंत्रालय सौ दिन के कामकाज को लेकर भी योजना बना रहा है। हालांकि उन्होंने योजनाओं को लेकर कोई ब्योरा तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि ऐसा कोई काम हाथ में लिया जाएगा, जो लोगों के बीच दिखाई दे। जल्द ही इसका ब्योरा भी साझा करने की जानकारी दी।

उत्साहवर्द्धक नहीं है भारतीय शिक्षण संस्थानों की गति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आइआइटी बांबे की फाइल फोटो।

▶ क्यूएस-2020 की रैंकिंग में 24 की जगह 23 संस्थानों को मिली जगह

▶ आइआइटी बांबे ने लगाई छलांग, दिल्ली व बेंगलुरु की खिसकी रैंकिंग

दुनिया की शीर्ष-200 उच्च शिक्षण संस्थानों में आइआइटी बांबे, आइआइटी दिल्ली और आइआइएससी बेंगलुरु ने जगह बनाई जरूर है लेकिन नतीजे अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। आइआइटी बांबे की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले दस अंकों का सुधार भी हुआ है। हालांकि यह कोई उत्साहवर्द्धक नतीजे नहीं हैं, क्योंकि पिछले पांच सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में जिस स्तर पर कोशिश हुई, उसका बहुत असर नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में की जा रही कोशिशों के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिलेंगे।

इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के बेहतर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की 2019 की सूची (क्यूएस रैंकिंग) में दुनिया के शीर्ष एक हजार बेहतर विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 24 संस्थानों ने जगह बनाई थी। जबकि 2020 की रैंकिंग में सिर्फ 23 संस्थान ही इनमें जगह बना पाए।

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के विश्वस्तर पर बेहतर प्रदर्शन को दर्शाने वाली 2020 की क्यूएस रैंकिंग (क्वेकक्वेरली सायमंड्स) बुधवार को जारी की गई है। इनमें आइआइटी बांबे की रैंकिंग 162 से इस बार 152 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही जिन संस्थानों की रैंकिंग में पिछली रैंकिंग यानि क्यूएस रैंकिंग 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है, आइआइटी खड़गपुर है, जिसकी रैंकिंग में 2019 में 295 थी, जबकि इस बार यह चौदह अंकों के सुधार के साथ 281 वें स्थान पर पहुंच गया है।

इस तरह दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंकिंग 487 से सुधरकर अब 474 वें स्थान पर आ गई है। मनीपाल विवि की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है, जिसने इस बार 701 से 800 शीर्ष संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। पिछली बार यह इससे नीचे थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम हरियाणा का ओपी जिंदल विश्वविद्यालय है। जिसे विश्वस्तरीय रैंकिंग में पहली बार शीर्ष के 751 से 800 रैंकिंग वाले संस्थानों की सूची में जगह बनाई मिली है।

इसी बीच, क्यूएस रैंकिंग-2020 में देश के 23 उच्च शिक्षण संस्थानों के शामिल होने पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने खुशी जताई है। साथ ही ऐसे संस्थानों को ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव आर. सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश में जिस तरह से उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की पहल शुरू की गई है, उसका असर अगले कुछ सालों में देखने को मिलेगा।

दुनिया के शीर्ष हजार संस्थानों में यह संस्थान भी हैं शामिल

क्यूएस रैंकिंग-2020 की बुधवार को जारी हुई सूची में देश के जिन संस्थानों ने जगह बनाई है, उनमें आइआइटी बांबे, आइआइटी दिल्ली, आइआइएससी बंगलौर, आइआइटी मद्रास, खड़गपुर, आइआइटी कानपुर, रूड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय, आइआइटी गुवाहाटी, जाधवपुर विवि, मनिपाल विवि, अन्ना विवि, जामिया मिलिया विवि, ओपी जिंदल, अलीगढ़ मुस्लिम विवि, अमृता विवि, बनारस हिंदू विवि, बिट्स, साबित्रीबाई फूले विवि पुणे, थापर विवि, कोलकाता विवि, मुंबई विवि, वीआइटी वेल्लोर शामिल है। रैंकिंग के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात और शोध समेत 13 मानक थे।

इस संस्थानों की रैंकिंग नीचे खिसकी

क्यूएस 2020 रैंकिंग में देश के जिन संस्थानों की रैंकिंग में 2019 के मुकाबले गिरावट दर्ज हुई है, उनमें आइआइटी दिल्ली (172 से 182) आइआइटी मद्रास(264 से 271) आइआइटी कानपुर (283 से 291) आइआइटी रुड़की (381 से 383) और आइआइटी गुवाहाटी (472 से 491) है। जिन संस्थानों की रैंकिंग में बेंगलुरु (170 से 184) भी शामिल है।

जिहाद शब्द के इस्तेमाल करने मात्र से कोई आतंकी नहीं होता

मुंबई, प्रेट्र : महज जिहाद शब्द के इस्तेमाल से किसी को आतंकी नहीं ठहराया जा सकता। महाराष्ट्र की अदालत ने यह बात तीन लोगों को आतंकवाद फैलाने के आरोप से मुक्त करते हुए कही है।

अकोला की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश एएस जाधव तीन युवकों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई कर रहे थे। अब्दुल रज्जाक (24), शोएब खान (24) और सलीम मलिक (26) के खिलाफ इन मुकदमों के अतिरिक्त हत्या के प्रयास और सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हमले का भी आरोप था। मामला 25 सितंबर, 2015 को अकोला में मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमले का था। घटना ईद के मौके पर गोमांस पर लगे प्रतिबंध को लागू कराने से संबंधित थी। घटना के दिन रज्जाक मस्जिद के भीतर से छुरा लेकर आया और उसने दो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। उसने यह हमला गोमांस पर लगे प्रतिबंध से नाराज होकर किया। घटना के बाद पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने आरोप लगाया कि रज्जाक ने यह सब मुस्लिम युवकों में उत्तेजना पैदा करने के लिए किया जिससे कि वे आतंकवादी संगठन में शामिल हों। न्यायाधीश जाधव ने कहा, घटना का विवरण देखने पर लगता है कि रज्जाक का गुस्सा सरकार और कुछ हिंदू संगठनों के खिलाफ था इसमें कोई शक नहीं कि रज्जाक ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया हो लेकिन इसके लिए किसी को आतंकी नहीं ठहरा सकते।

हिज्ब के पांच आतंकवादी गिरफ्तार

सफलता ▶ आइईडी तैयार करने में जुटे थे, पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश नाकाम

आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और आइईडी तैयार करने का सामान बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पुलवामा जैसे आतंकी हमले को दोहराने के लिए एक बड़े आइईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) धमाके को अंजाम देने की साजिश में जुटे आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन का एक मंसूबा बुधवार को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने आइईडी तैयार करने में जुटे हिज्ब के पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और आइईडी तैयार करने का सामान बरामद किया है। पकड़े गए पांचों आतंकियों से पूछताछ जारी है। पकड़े गए युवकों ने माना है कि उन्हें दो जगहों पर अलग-अलग आइईडी लगानी थी। एक आइईडी हाईवे पर सुरक्षाबलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए थी और एक अन्य किसी भीड़ भरे इलाके में धमाके के लिए बनाई जानी थी।

गत सप्ताह पाकिस्तान ने भारत सरकार को अलर्ट किया था कि दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठन 14 फरवरी को लिथपोरा पुलवामा जैसा कोई हमला दोहराने की फिराक में है। सोमवार को आतंकियों ने अरिहाल पुलवामा में एक सैन्य वाहन को वाहन बम से उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन नाकाम रहे। इस हमले में दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए और 17 जख्मी हुए थे।

सोमवार की साजिश के नाकाम होने के बाद आतंकी एक बार फिर किसी बड़े धमाके की साजिश में जुटे हुए थे। इस बीच पुलिस ने सोमवार को अरिहाल हमले में लिप्त आतंकियों को पकड़ने के लिए अपने तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर रखा था। इसके अलावा पुलिस ने कुछ दिन पहले आतंकी कमांडर नवीद के सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो की भी छानबीन की, जिसमें वह आइईडी तैयार करता नजर आ रहा था।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि गत शाम पुलिस को पता चला कि शोपियां के जेनपोरा व उसके साथ सटे इलाकों में कुछ आतंकी आइईडी तैयार करने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने इन आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना व सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर मंगलवार शाम एक अभियान चलाया और बुधवार सुबह तक पांच आतंकियों को उनके ठिकानों से पकड़ लिया गया।

इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, आइईडी तैयार करने का सामान, आतंकी साहित्य व और अन्य साजो सामान मिला है। शुरुआती पूछताछ में सभी ने आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के साथ अपने संबंधों को स्वीकारा है। फिलहाल, पांचों से पूछताछ जारी है।

आतंकी हमलों की साजिश साझा करना फर्ज समझे पाकिस्तान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने आतंकी ढांचे को नष्ट करने का किया दावा

▶ कहा- राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचे का नष्ट किए जाने का दावा किया है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि वह जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होने वाले आतंकी हमलों की खुफिया जानकारी भारत से साझा करे। पाकिस्तान को अपनी यहां से आतंकी गतिविधियों का संचालन रोकना होगा।

शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान द्वारा खुफिया सूचना देने पर कहा कि यह अच्छी बात है। ऐसा करना पाकिस्तान का फर्ज बनता है, वह इस तरह की खुफिया सूचनाएं हमारे साथ साझा करे।

दरअसल, गत सप्ताह पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया था कि आतंकी संगठन एक बार फिर पुलवामा में किसी जगह 14 फरवरी के लिथपोरा पुलवामा हमले जैसी वारदात करने की फिराक में हैं। इस अलर्ट के बाद गत सोमवार को पुलवामा के अरिहाल इलाके में आतंकियो ने सुरक्षाबलों के एक वाहन पर वाहनबम से हमला भी किया। इसमें दो सैन्य कर्मी शहीद और और 17 अन्य जख्मी हो गए।

अमरनाथ यात्रियों पर कोई खतरा नहीं: राज्यपाल ने कहा कि यहां पर्यटकों और श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यहां पथराव की घटनाएं कम हो गई हैं, जुमे के बाद जो पथराव और हिंसक घटनाएं होती थीं, वह भी लगभग समाप्त हो गई हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि वह इस रास्ते से कहीं नहीं पहुंचेंगे। दो दिन पहले ही दो युवक आतंकी हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटे हैं। आतंकियों की नई भर्ती बंद हो गई है। जमीनी हालात बहुत अच्छे हैं।

छग में नक्सलियों ने की सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या

नईदुनिया, बीजापुर

▶ सड़क निर्माण में लगे उनके तीन वाहनों को लगाई आग

▶ विधानसभा चुनाव में संतोष बीजापुर से पार्टी प्रत्याशी थे

छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पुनेम की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। नक्सलियों ने उन्हें मंगलवार की रात अगवा कर लिया था। हत्या के बाद शव पहाड़ियों के पीछे निर्माणाधीन सड़क के किनारे फेंक दिया। सड़क निर्माण में लगे उनके तीन वाहनों को भी नक्सलियों ने फूंक दिया है।

विधानसभा चुनाव में संतोष बीजापुर से पार्टी प्रत्याशी थे। चुनाव के बाद वह ठेकेदारी में मद्देड़ इलाके में सड़क निर्माण करा रहे थे। मंगलवार सुबह वह कार से निर्माण कार्य देखने मिनकापल्ली पहुंचे, जहां से वह जेसीबी से मरिमल्ला गांव तक गए थे। इसी दौरान उन्हें नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। ।इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई।

शव देने से किया इन्कार : संतोष की हत्या के बाद उनका शव लेने के लिए बेटा राकेश पुनेम वारदातस्थल पर पहुंचा तो नक्सलियों ने शव देने से इन्कार कर उसे लौटा दिया। नक्सलियों के पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) संगठन ने वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए संतोष को जनविरोधी व महेंद्र कर्मा का करीबी सलवा जुडूम नेता बताया है।

13 लाख के इनामी समेत चार ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा: ओडिशा के नक्सल संगठन सेंट्रल कमेटी सुरक्षा प्लाटून नंबर तीन के कमांडर गुड्डू उर्फ सुरेश उर्फ वासुदेव समेत चार नक्सलियों ने बुधवार को एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गुड्डू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच और ओडिशा सरकार ने आठ लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अलावा एक लाख का इनामी जनमिलिशिया कमांडर दिलीप पुनेम, जनमिलिशिया सदस्य लक्ष्मण अटामी व मुन्नाराम ने दो भरमार बंदूक के साथ आत्मसर्मपण किया है।

सीएएफ जवान ने साथियों पर चलाई गोली, दो जवानों की जान गई

नईदुनिया, बीजापुर: जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर मिंगाचल स्थित छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स (सीएएफ) 15वीं वाहिनी कैंप में एक आरक्षक ने विवाद के बाद अपने दो साथियों को गोलियों से भून दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। आरोपित आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि की है।

मिली जानकारी के अनुसार शाम करीब पांच बजे ड्यूटी से कैंप लौटे आरक्षक संजय निषाद की साथी जवानों संजय कुमार भास्कर व सुरेंद्र कुमार साहू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आपा खोए संजय निषाद ने अपनी सर्विस रायफल इंसास एलएमजी से दोनों पर दनादन गोलियां दाग दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुन बैरक के अन्य जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से संजय निषाद को काबू में कर उसकी रायफल छीनी। आरोपित जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विवाद किस बात को लेकर हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक जवान संजय कुमार भास्कर छत्तीसगढ़ के पेंडरीखुर्द कबीरधाम व सुरेंद्र कुमार साहू ग्राम लोहसी जांजगीर-चांपा जिले के निवासी हैं। वहीं आरोपित भंडारपुरी कबीरधाम का रहने वाला है।

फिल्म 'आर्टिकल 15' पर उठा विवाद

माला दीक्षित, नई दिल्ली

▶ अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने फिल्म पर की आपत्ति

▶ फिल्म ब्राह्मणों को आहत करने वाली, निर्माता-निर्देशक को नोटिस

▶ 30 मई को आया था ट्रेलर, 28 जून को फिल्म रिलीज होने वाली है

आर्टिकल-15 का पोस्टर। फाइल

फिल्म 'आर्टिकल 15' विवादों में घिरती नजर आ रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने फिल्म को जाति के आधार पर समाज को बांटने वाला और ब्राह्मणों का अपमान बताते हुए आपत्ति उठाई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने फिल्म के निर्माता-निर्देशक को कानूनी नोटिस जारी कर फिल्म से आपत्तिजनक हिस्सा हटाने की मांग की है। इस फिल्म का ट्रेलर 30 मई को रिलीज हुआ था और 28 जून को फिल्म रिलीज होने वाली है।

फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक फिल्म में ऊंची जाति के अभियुक्तों के नीची जाति से दुष्कर्म और हत्या का अपराध करने का जिक्र है। साथ ही जाति आधारित संवाद और टिप्पणियां हैं।

संस्था की ओर से वकील सुनील कुमार तिवारी ने कानूनी नोटिस भेज कर 24 घंटे के भीतर यू-ट्यूब व सोशल मीडिया पर फिल्म के जारी ट्रेलर की वीडियो क्लिप से आपत्तिजनक भाग हटाने की मांग की है। कहा गया है कि अगर तय समय में वीडियो क्लिप से आपत्तिजनक हिस्सा नहीं हटाया गया तो संस्था आपराधिक व दीवानी कानूनी कार्रवाई करेगी। नोटिस में कहा गया है कि किसी को भी आम जनता की निगाह में किसी व्यक्ति, समूह और उसकी परंपराओं, उसकी जाति या धर्म को कमतर करने का अधिकार नहीं है। यह फिल्म ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकती है जो कि आइपीसी की धारा 499 में दंडनीय अपराध है।

सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया नागरिकों के मानवीय, मौलिक और प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षक है। इसलिए सेंसर बोर्ड प्रमाणपत्र की आड़ में लोगों की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी आडियो वीडियो फिल्म जारी नहीं की जा सकती। अगर ऐसी कोई गैर कानूनी इजाजत दी गई है तो उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। कहा गया है कि इस फिल्म से समाज में विभिन्न जातियों और धर्मों का आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। शांति भंग हो सकती है। इतना ही नहीं फिल्म का जारी किया गया ट्रेलर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आत्मसम्मान के खिलाफ है। उसमें उन्हें दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराध का पीड़ित दिखाया गया है।

रितिक की बहन सुनैना को लेकर रंगोली ने लगाए रोशन परिवार पर आरोप

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : कंगना रनोट और रितिक रोशन के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस बार मामला उनकी बहन सुनैना रोशन से जुड़ा है। हाल ही में सुनैना ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मैं पूरी तरह से कंगना का समर्थन करती हूं।' सुनैना का यह ट्विटर अकाउंट आधिकारिक है या नहीं इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद कंगना की बहन ने ट्विटर पर सुनैना को लेकर कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं।

रंगोली ने ट्वीट किया है, 'सुनैना रोशन कंगना से मदद मांग रही हैं। दिल्ली के एक मुस्लिम युवक से प्यार करने के चलते उनका परिवार उनके साथ मारपीट कर रहा है। मुझे डर है कि उनका खतरनाक परिवार उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हमने इसे इसलिए सार्वजनिक किया है, क्योंकि सुनैना कंगना को कॉल करके रोती रहती हैं। आखिरकार हर किसी को प्यार करने का हक है। उम्मीद है कि इससे रोशन परिवार डरेगा और यह हरकतें बंद कर देगा।'

इस पूरे मुद्दे पर रितिक की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रोशन परिवार के करीबियों की मानें तो सुनैना मानसिक रोग से पीड़ित हैं और परिवार उनका पूरा ख्याल रख रहा है। रितिक के चचेरे भाई ईशान ने ट्वीट कर रोशन परिवार का बचाव किया है।

नई तस्वीर

श्रीनगर में फुटबाल मैच देखने उमड़ी भीड़, किक मारते नजर आए बाइचुंग भूटिया, रेनेडी सिंह और मेहराजुदीन वडू जैसे दिग्गज

तालियों और किक के बीच दम तोड़ता नजर आया आतंक का खौफ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जिस शहर में दिन का शोर शराबा अंधेरा होते ही डराने वाले सन्नाटे में बदल जाता हो, वहां मंगलवार रात लोगों की सीटियां और तालियां गूंजती रहीं। यह शोर लालचौक से महज दो किलोमीटर दूर पर स्थित टीआरसी फुटबाल मैदान से आ रहा था। यह भीड़ मैदान में फ्लडलाइट्स लगने के बाद पहली बार रात में होने वाले फुटबाल के प्रदर्शन मैच को देखने के लिए जमा हुई थी। मैदान में फ्लडलाइट्स ने हिंसा और डर के अंधेरे को भगा दिया।

फुटबाल स्टेडियम का मंगलवार रात औपचारिक उदघाटन हुआ। इस मौके पर पहला मैच जेके स्टार्स इलेवन व इंडियन स्टार्स इलेवन के बीच खेला गया। भारतीय फुटबाल के दिग्गज और राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया, रेनेडी सिंह और मेहराजुदीन वडू मैदान पर फुटबाल को किक मारते नजर आए। मंगलवार रात टीआरसी फुटबाल स्टेडियम में फ्लडलाइट्स सुविधा का उदघाटन किया। इसके बाद मैदान पर फुटबाल खिलाड़ी उतरे। सिर्फ श्रीनगर से ही नहीं, आसपास के शहरों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में फुटबाल प्रेमी अपने अंदर के डर को बाहर निकाल कर स्टेडियम के भीतर प्रदर्शन मैच देखने के लिए पहुंचे थे।

श्रीनगर में टीआरसी टर्फ फुटबाल स्टेडियम में फुटबाल मैच का लुत्फ उठाते दर्शक। जागरण

ऐतिहासिक रहा लम्हा : मैच देखने पहुंचे फुटबाल प्रेमी फैयाज अहमद का कहना था कि यह उनके जैसे लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और खुशी का लम्हा है। ऐसे में वह इसका गवाह बनने से खुद को नहीं रोक पाए। फैयाज ने कहा कि उनकी पत्नी ने हालात का हवाला देते हुए, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। यह एक शुरुआत हो रही है, ऐसे में हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। इस तरह की सुविधाएं और भी होनी चाहिए। दर्शक दीर्घा में अख्तर हुसैन ने कहा कि यहां सिर्फ फुटबाल का मैच नहीं हो रहा है, हमारा सपना साकार हुआ है। यह दुनिया के फुटबॉलरों को यहां आकर खेलने का न्योता है।

मैच शुरू होने तक खचाखच भर गया था स्टेडियम : राज्य के खेल सचिव आयुक्त सरमद हफीज का कहना था कि हमें पहले लगा कि यहां जो हालात हैं, उसमें मैच देखने के लिए कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन 15 हजार की क्षमता वाला यह स्टेडियम मैच शुरू होते ही भर गया। इससे यहां के लोगों में फुटबाल से लगाव को समझा जा सकता है। इससे यह भी कह सकते हैं कि आम कश्मीरी जो हिंसा और डर के कारण शाम होते ही घर की चहारदीवारी में सिमट जाता है, अब वह बैखौफ होकर खुलकर अपनी जिंदगी जीने के लिए घर से बाहर निकलने को तैयार हो रहा है। यह कश्मीर में बदलते हालात का सुबूत है। इसे सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के साथ भी जोड़ कर देखा जाना चाहिए।

कश्मीर के युवाओं में है फुटबाल के लिए जुनून : सलाहकार

राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार का कहना था कि जब वह मैदान में आए तो उनको लगा कि यह महज उदघाटन की एक रस्म भर होगी, लेकिन जब उन्होंने वहां फुटबाल प्रेमियों की भीड़ देखी, मैच को लेकर जुनून देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों में फुटबाल को लेकर जुनून है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खेल को अपने जुनून को पालें और इसमें अपने भविष्य संवारें। उनका कहना था कि कश्मीर के युवा खेल के जरिए अपना और राज्य का भविष्य बदल सकते हैं।

पति के साथ खाकी निकर में दिखीं प्रियंका चोपड़ा, जमकर हुई ट्रोल

नई दिल्ली, आइएएनएस: आयेदिन सुर्खियों में बनी रहने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिलहाल अपनी ड्रेस को लेकर चर्चा में हैं। पति निक जोनास के साथ न्यूयॉर्क के होटल से ब्लैक टॉप और खाकी निकर पहने बाहर निकलते दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंतरराष्ट्रीय ब्रांड अंबेसडर तक बता डाला।

प्रियंका चोपड़ा को भले ही खाकी रंग की निकर पहनने पर ट्रोल किया जा रहा हो, लेकिन उन्होंने काले रंग के जूते भी पहन रखे हैं। यह भी संघ के गणवेश का एक हिस्सा है। प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा कि आखिरकार प्रियंका संघ में शामिल हो ही गईं।

एक अन्य यूजर ने प्रियंका की ही दो तस्वीरों की तुलना की है। एक वह जब प्रियंका ने कहा था कि वे भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। जबकि दूसरी जिसमें वह खाकी शार्ट पहने नजर आ रही हैं।

120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं जम्मू-कश्मीर में राज्य कैंसर संस्थान के लिए। लिनीयर एक्सलरेटर, पेट स्कैन, ब्रैकीथेरेपी, 4डी सीटी सिम्युलेटर के साथ-साथ पैथोलॉजी लैब को भी इस योजना के तहत लिया जाएगा।

पांचवें दिन गर्मी और लू से बिहार में 38 और की जान गई

आफत ▶ तापमान में गिरावट के बाद भी नहीं थमा मौतों का कहर

अब तक बिहार में लू से 329 की मौत, अस्पतालों में 300 से ज्यादा मरीज हैं भर्ती

जागरण टीम, पटना

बिहार के विभिन्न जिलों में भीषण गर्मी और लू से बुधवार को 38 लोगों की मौत हो गई। गया में 11, सासाराम में 4, औरंगाबाद में 5, नवादा में 3, खगड़िया मे 5 और वैशाली, बेगूसराय, बिहारशरीफ, जहानाबाद व बक्सर में 10 की जान गई। सूबे में अब तक 329 की मौत हो चुकी है। इसमें शनिवार को 60, रविवार को 118, सोमवार को 66 और मंगलवार को 47 की जान गई।

सिर्फ गया और आसपास के जिलों में शनिवार से अभी तक 227 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में तीन सौ भी ज्यादा मरीज अभी भी भर्ती हैं। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पांच दिनों में 203 मरीज भर्ती हुए।

औरंगाबाद, नवादा और सासाराम के विभिन्न अस्पतालों में भी दो सौ से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। बुधवार को गया और सासाराम कें बादल छाए रहने और बूंदाबांदी से तापमान में थोड़ी गिरावट आई।

मगध-शाहाबाद में 227 मौत नई आपदा के मिल रहे संकेत

अश्विनी, गया : बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों पर एईएस का कहर अभी थमा भी नहीं है कि मगध क्षेत्र में लू से बड़ी संख्या में हो रही मौत एक बहुत बड़ी आपदा बनकर सामने आ गई। संभवतः यह पहली घटना है, जब गया में लू के कारण निषेधाज्ञा जारी करने की नौबत आई। बाद में दूसरे जिलों में भी। लू से कहर की शुरुआत 15 जून को औरंगाबाद से हुई और इसने देखते-देखते गया-नवादा ही नहीं, शाहाबाद को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस पूरे जोन में 19 जून तक 211 लोगों की जान सिर्फ पांच दिनों में चली गई है। पर्यावरण विशेषज्ञ से लेकर डॉक्टर और बड़े-बुजुर्ग यही बता रहे कि ऐसी भयंकर आपदा पहली बार आई है। मेडिकल साइंस इसे हीट वेव यानी लू ही मान रहा है। क्या एईएस की तरह इस क्षेत्र में हीट स्ट्रोक के किसी नए कहर की शुरुआत तो नहीं, यह रिसर्च का विषय है।

बिहार के दूसरे इलाकों में भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, पर मगध क्षेत्र में जिस तरह से आपदा की स्थिति पैदा हुई है, वह भविष्य के प्रति एक खतरनाक संकेत है। इतना ही नहीं, इलाका विशेष से आबादी के पलायन की नौबत से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसे प्रारंभिक संकेतों से समझा जा सकता है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार चौधरी बताते हैं कि जलस्तर सामान्य तौर पर पांच से दस फीट नीचे जा चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में दो से तीन सौ फीट बोरिंग के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. सच्चिदानंद प्रेमी बताते हैं कि पहले भी एपी कॉलोनी में जलसंकट के कारण लोग दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं। अब नए क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। 1960 के दशक में भयंकर गर्मी के समय भी यह स्थिति पैदा नहीं हुई थी। क्या यह पर्यावरण में बहुत बड़े बदलाव का संकेत तो नहीं, मगध विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर नलिन कुमार कहते हैं नमी में बहुत बदलाव देखा जा रहा। हर साल वृक्ष काटे जा रहे, पर उस अनुपात में पौधरोपण नहीं हो रहा। कह सकते हैं कि अब हीट ब्लास्ट की स्थिति बन गई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में एईएस पीड़ित बच्चे के पास परिजन। एएनआइ

एईएस से इस साल सबसे अधिक मौत, 2012 के बाद भयावह स्थिति

जासं, मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर में एईएस ने 2012 में 120 बच्चों की मौत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एसकेएमसीएच में बुधवार की सुबह पांच और बच्चों की मौत हो गई। अब तक इस बीमारी से सिर्फ मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में 125 बच्चों की मौत हो चुकी है। विभिन्न अस्पतालों में अब तक 473 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। 2012 में 336 को भर्ती कराया गया था। इधर, पीड़ितों के आने का सिलसिला भी थम नहीं रहा। एसकेएमसीएच में 22 से ज्यादा नए मरीजों को भर्ती किया गया। जबकि, आठ बच्चे केजरीवाल अस्पताल में लाए गए हैं। 2012 में बीमारी ने भयावह रूप लिया। तब 120 बच्चों की मौत हो गई थी।

राजस्थान में भी अलर्ट: बिहार में जानलेवा बने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सड्रोम को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग व सरकारी और निजी अस्पतालों को इस बुखार से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

एईएस से निपटने के इंतजाम पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ शीर्ष कोर्ट जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई को हुआ राजी

▶ इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर मुजफ्फरपुर भेजने की मांग की है

सुप्रीम कोर्ट बिहार में चमकी बुखार यानी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के कहर से बच्चों को बचाने और तत्काल विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठित कर प्रभावित इलाके में भेजने की मांग पर जल्द सुनवाई को राजी हो गया है। इलाज के पर्याप्त इंतजाम करने की मांग वाली जनहित याचिका पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। एईएस से बच्चों की हो रही मौतों के मामले में यह जनहित याचिका बिहार के रहने वाले वकील मनोहर प्रताप ने दाखिल की है। बिहार में अबतक इस बीमारी से सौ से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश कालीन पीठ ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग स्वीकार कर लिया। याचिका में चमकी बुखार की विकरालता और उसे काबू करने में राज्य सरकार की नाकामी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उसे तत्काल बिहार के मुजफ्फरपुर व अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा केंद्र और बिहार सरकार को 500 आइसीयू ऐसे 100 मोबाइल आइसीयू स्थापित करने का निर्देश देने को कहा गया है जो कि विशेषज्ञों से लैस हों जिससे दूर दराज के इलाकों में प्रभावितों को इलाज मुहैया कराया जा सके। साथ ही बिहार सरकार को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख एक आदेश जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के निजी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करने को कहा जाए। याचिका में सिर्फ बिहार और केंद्र सरकार के लिए ही निर्देश नहीं मांगे गए हैं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस रोग को रोकने और इससे निपटने के पर्याप्त इंतजाम करने का आदेश देने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वह जागरूकता के लिए पर्याप्त प्रचार करें।

बिन पानी दुबला हो रहा दशहरी आम

अजय श्रीवास्तव, लखनऊ

▶ मलिहाबाद में गिरते जलस्तर का असर आम पर भी दिख रहा

▶ फलपट्टी में आम के वजन और आकार में आई गिरावट

अपने आकार और स्वाद के लिए मशहूर मलिहाबादी दशहरी दुबला होने लगा है। जानकार इसके पीछे गिरते जलस्तर को वजह मान रहे हैं। इससे सिर्फ दशहरी की ही दशा नहीं खराब है बल्कि आम की सभी किस्मों पर इसका असर दिख रहा है। फलपट्टी में आम के वजन और आकार में लगातार गिरावट आ रही है।

लखनऊ के मलिहाबाद में साल दर साल जलस्तर लगातार गिर रहा है। यहां अभी 180 फीट की गहराई पर पानी मिल रहा है। ऐसे में आम को मुश्किल से पानी मिल पा रहा है। इसके चलते एक किलोग्राम वजन तक होने वाला दशहरी चार सौ ग्राम के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पद्मश्री से अलंकृत बागबान कलीम उल्ला यह बताते हुए चिंता जताते हैं कि ऐसा ही रहा तो दशहरी चखने को भी मुश्किल से मिलेगी। उनके मुताबिक 10 वर्ष पहले तक लंगड़ा का वजन तीन पौव (साढ़े सात सौ ग्राम तक) होता था लेकिन कुछ साल में यह तीन से चार सौ ग्राम पर ठहर गया है। इसी तरह 350 ग्राम तक होने वाला लखनऊवा सफेदा अब 250 ग्राम से ज्यादा वजन नहीं पा रहा। यही हाल सफेदा जौहरी का भी है।

पद्मश्री कलीम उल्ला, आम उत्पादक। जागरण

कम बारिश से पेड़ों को पर्याप्त पानी न मिलने, कीड़े की संख्या में वृद्धि होने और पेड़ों की धुलाई एक से बढ़कर पांच से छह बार होने के साथ ही बढ़ते प्रदूषण ने भी आम की सेहत पर असर डाला है।

डॉ. असमत, शायर और आम उत्पादक

1965 में 52 फीट पर पानी मिलता था। तब बौर एक हाथ तक के होते थे, अब इसे बित्ते से नाप सकते हैं। अब 180 फीट पर पानी मिल पा रहा है। इससे आम छोटा होने के साथ जल्द सूख भी जा रहा है।

-पद्मश्री कलीम उल्ला, आम उत्पादक

कोलकाता में फोर्ट विलियम के अंदर किशोरी से दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, कोलकाता : अति सुरक्षित जोन माने जाने वाले फोर्ट विलियम के अंदर रहने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है।

सूत्रों के अनुसार फोर्ट विलियम में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंदर ही एक मकान में परिवार के साथ रहता है। गत 15 जून की शाम करीब 6 से 8 बजे के बीच कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ बाजार गया हुआ था, जबकि उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। आरोप है कि पड़ोसी का रिश्तेदार सागर मल्लिक नामक युवक घर में दाखिल हो गया और जबरन किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वह भाग निकला। माता-पिता के घर लौटने पर किशोरी ने घटना से अवगत कराया। पीड़िता के पिता ने आरोपित युवक के खिलाफ मैदान थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।

उत्तर प्रदेश में दो सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत, 50 घायल

जेएनएन, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में दो सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। पहली घटना सम्भल में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर लहरावन गांव के पास मंगलवार रात करीब डेढ़ हुई, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से कैंटर में टक्कर मार दी। इससे कैंटर पलट गया और उसमें सवार एक ही गांव के पांच लोगों सहित आठ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में दस लोग घायल भी हुए हैं। दूसरी घटना फतेहपुर जिले में सठिगवां गांव के पास बुधवार दोपहर हुई, जहां बस और ट्र की आमने-सामने भिड़ंत में बस सवार पिता-पुत्र समेत नौ लोगों की मौत हो गई और 40 यात्री घायल हो गए।

फतेहपुर के चांदपुर थानाक्षेत्र के सठिगवां गांव निवासी प्राइवेट बस चालक रामसजीवन फतेहपुर शहर से सवारियां लेकर जहानाबाद जा रहा था। सठिगवां गांव के पास सामने तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक से बस की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में बस सहित नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से 40 घायलों को एलएलआर हॉस्पिटल (हैलट) कानपुर व स्थानीय जिला चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

उधर सम्भल जिले के लहरावन गांव निवासी राम भरोसे की बेटी ज्योति का लग्न लेकर परिवार के लोग मंगलवार को बदायूं के थाना उघैती के ग्राम चाचीपुर गए थे। लग्न चढ़ाकर सभी लोग कैंटर से रात में गांव लौट रहे थे। मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर लहरावन के पास पहुंचते ही सामने से आ रही पिकअप ने कैंटर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पलट गईं। घटना के बाद सात लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना में दस लोग घायल भी हुए हैं।

बोरवेल में जान गवांने वाले फतेहवीर के नाम पर होगा सड़क का नाम

जासं, चंडीगढ़/संगरूर: संगरूर के गांव भगवानपुरा में बोरवेल में फंस कर जान गंवाने वाले फतेहवीर सिंह के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। स्थानीय लोगों और मृतक बच्चे के परिवार ने सुनाम शेरों कैंचियां से शेरों लोंगोवाल जाने वाली सड़क का नाम 'फतेहवीर सिंह' रोड रखने की मांग की थी।

इसे एक विशेष केस के तौर पर लेते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले फतेहवीर की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। लोक निर्माण मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने मृतक बच्चे के परिवार के साथ मुलाकात की। परिवार के साथ हमदर्दी जताते हुए उन्होंने मृतक बच्चे के परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। मंत्री ने बताया कि परिवार की विनती को स्वीकार करते हुए बच्चे की असामयिक मौत को देखते हुए बिछड़ी आत्मा को सत्कार देने के लिए राज्य सरकार ने इस सड़क का नाम फतेहवीर के नाम पर रखने के लिए सहमति जताई है।

पीसीएस जे का साक्षात्कार कल से

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (पीसीएस जे) 2018 का साक्षात्कार 21 जून शुक्रवार से शुरू होगा। उप्र लोकसेवा आयोग में 17 जुलाई तक चलने वाले साक्षात्कार की तैयारी पूरी हो गई हैं। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पत्र व अन्य जानकारी यूपीपीएससी की वेबसाइट ह्वश्चश्वह्यष्.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर अपलोड किया गया है। यूपीपीएससी ने पीसीएस-जे 2018 मुख्य परीक्षा 30 व 31 जनवरी व एक फरवरी 2019 को प्रयागराज, लखनऊ के केंद्रों पर कराई थी। परीक्षा में कुल 5795 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का परिणाम 13 जून को घोषित किया गया, जिसमें 1847 अभ्यर्थी सफल हुए। इस भर्ती परीक्षा में कुल 610 रिक्तियां हैं। इसमें अनारक्षित श्रेणी की 306, अनुसूचित जाति की 128, अनुसूचित जनजाति की 12 व अन्य पिछड़ा वर्ग की 164 रिक्तियां घोषित हैं। भर्ती में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत डीएफएफ श्रेणी की 12, दिव्यांग श्रेणी की 24 व महिला श्रेणी की 122 रिक्तियां सम्मिलित हैं।

अगले माह अंतिम परिणाम : पीसीएस-जे 2018 का साक्षात्कार पूरा होते ही अगले माह दूसरे पखवारे में यूपीपीएससी अंतिम परिणाम जारी करेगा और न्यायिक सेवा को 610 नए अफसर मिल सकेंगे।

पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स से छेड़छाड़ की घटना की जांच करेगी कमेटी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ सोमवार रात उशोषी सेनगुप्ता के साथ हुई थी अभद्रता और कार पर पथराव

▶ कोर्ट ने आरोपितों को 21 जून तक पुलिस रिमांड में भेजा

कोलकाता में सरेराह 2010 की मिस इंडिया यूनिवर्स उशोषी सेनगुप्ता के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होते ही पुलिस की निष्क्रियता ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद मामले के तूल पकड़ने पर कोलकाता पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा ने जांच कमेटी गठित कर दी। रिपोर्ट में यदि घटना के वक्त ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता पाई जाती है तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 154 धारा में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस मामले में गिरफ्तार सात आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपितों 21 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है।

यह है मामला : सोमवार रात करीब पौने बारह बजे मैदान थाने से कुछ ही फासले पर एक स्कूटी ने पूर्व मिस इंडिया उशोषी सेनगुप्ता की कार में टक्कर मार दी। आरोप है कि मौके पर जुटे बाइक सवार 10-15 और मनचलों ने कार चालक को बाहर खींचकर मारपीट की गई। कार से उतर कर उशोषी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो मनचलों ने उनके साथ अभद्रता की। उशोषी ने वहां की स्थानीय पुलिस से मदद मांगी तो अन्य क्षेत्र का मामला बताकर उन्हें टरका दिया गया। इसके बाद वह अपनी सहेली को लेक गार्डेन छोड़ने पहुंची तो वहां पर भी चार-पांच बाइक सवारों ने कार पर पथराव के साथ उशोषी को बाहर खींचकर छेड़छाड़ की। चीख पुकार सुन आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपित फरार हो गए थे। इसके बाद किसी तरह पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पहले कार्रवाई कर सकती थी पुलिस : उषोशी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : मैंने कभी सोचा नहीं था कोलकाता जैसे महानगर में मेरी जैसी महिला को रात में मदद मांगने पर पुलिस का ऐसा बर्ताव झेलना पड़ेगा। वाकई में इस घटना महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। उषोशी सेनगुप्ता ने सरेराह अपने साथ हुई छेड़छाड़ और बदसलूकी की घटना को लेकर पुलिस की निष्क्रियता पर अपनी व्यथा प्रकट की। कोलकाता पुलिस के इस रवैये की कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोशल मीडिया पर घटना के वायरल होने से पहले यदि आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो पुलिस का मान बढ़ता। उन्होंने पूछा की जब मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। कहा कि बड़ी मेहनत कर मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं और सुरक्षा के लिहाज से काम के लिए कोलकाता को ही चुना था।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

वायरल नंबर योगी आदित्यनाथ का नहीं, जीआरपी का है

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, एजेंसी: सोशल मीडिया में कुछ समय से एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें एक मोबाइल नंबर के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। नंबर है 9454404444। विश्वास न्यूज की टीम की पड़ताल में यह दावा फर्जी साबित हुआ। हमारी जांच में पता चला कि यह नंबर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) का हेल्पलाइन वाट्सएप नंबर है। इस नंबर को 16 नवंबर 2016 में लांच किया गया था।

पड़ताल: विश्वास न्यूज की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में सेव किया। इसके बाद WhatsApp पर नंबर को ओपन किया। यहां से हम सच्चाई के करीब पहुंच गए। इस नंबर के अबाउट में लिखा हुआ है कि यह राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) उप्र का वॉट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। इतना ही नहीं, डिस्प्ले इमेज में भी 9454404444 नंबर को देखा जा सकता है। यहां साफतौर पर लिखा है कि जीआरपी वॉट्सएप नंबर। अपराध व भ्रष्टाचार रोकने हेतु फोटो, ऑडियो/वीडियो क्लिप भेजें।

इसके बाद हमने जीआरपी के कंट्रोल रूम के नंबर 945444-02544 पर संपर्क किया। यहां हमारी बात अनूप कुमार से हुई। उन्होंने बताया कि जिस नंबर को योगी आदित्यनाथ का बताकर वायरल किया जा रहा है, वह जीआरपी का नंबर है। इस नंबर को इसलिए लांच किया गया था कि कोई भी यात्री अपनी समस्या को जीआरपी को सीधे भेज सके। इसके बाद विश्वास टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए गूगल पर गई। कई कीवर्ड टाइप करने के बाद हमने Inextlive वेबसाइट पर एक खबर मिली। 17 नवंबर 2016 को अपलोड की गई खबर की हेडिंग थी, अब जीआरपी भी वाट्सएप से सुनेगी फरियाद।

खबर में बताया गया कि 'जीआरपी' की ओर से हेल्पलाइन वॉट्सएप नंबर 9454404444 जारी किया गया। ये नंबर पूरे प्रदेश में एक्टिव रहेगा और शिकायतों पर एक्शन लिया जाएगा।

वॉट्सएप नंबर 9454404444 पर पूरे प्रदेश से शिकायत भेजी जा सकती है। नए नंबर को लोग अपने स्मार्ट फोन में सेव कर किसी भी घटना-दुर्घटना या समस्या की शिकायत मैसेज या फोटो के साथ भेज सकते हैं। अंत में हमने वायरल मैसेज करने वाले फेसबुक अकाउंट की सोशल स्कैनिंग की। हमें पता चला यह यूजर एक खास विचारधारा से प्रभावित पोस्ट करता है।

क्या है वायरल पोस्ट में

Manukrishnna Amardas Udasinnirwann नाम के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट को शेयर करते हुए दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ ने दिया अपना नंबर 9454404444। अगर कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर सीधा वाट्सएप करें। 3 घंटे के अंदर होगी कार्रवाई। यह मैसेज पिछले कई सालों से लगातार वायरल हो रहा है। कभी इसे वॉट्सएप पर वायरल किया जाता है तो कभी फेसबुक पर।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 293

शोध

सीएसआइआर-एनआइएसटीएडीएस की नवनियुक्त महिला निदेशक डॉ. रंजना अग्रवाल कर रहीं शोध, डीएनए के जरिये कैंसर का होगा इलाज

कैंसर के इलाज में नहीं मरेंगे शरीर के नॉर्मल सेल

पंकज आत्रेय, कुरुक्षेत्र

कैंसर की बढ़ती समस्या ने देश के मेडिकल साइंस के आगे एक चुनौती खड़ी कर दी है। इस बीमारी के इलाज में शरीर के दूसरे हिस्सों को होने वाले नुकसान ने चिंता ज्यादा बढ़ा रखी है। ऐसे में अब कैंसर के इलाज के दौरान शरीर के नॉर्मल सेल को नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (सीएसआइआर-एनआइएसटीएडीएस) की नवनियुक्त महिला निदेशक एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग की प्रोफेसर डॉ. रंजना अग्रवाल इसी पर शोध में जुटी हैं। इसके प्रारंभिक परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे हैं।

दरअसल, डॉ. रंजना डीएनए का प्रयोग करके ही सिर्फ कैंसर सेल्स को खत्म करने की तकनीक पर काम रही हैं। फोटोडायइनेमिक थ्योरी पर काम करते हुए डीएनए से कंपाउंड बनाकर यह संभव हो सकता है। डीएनए से निर्मित योगिकों को कैंसर कोशिकाओं के पास शरीर में प्रवेश कराया जाएगा और जब उन पर पराबैंगनी विकिरण डाला जाएगा तो सिर्फ कैंसर के ही सेल खत्म होंगे।

दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में डॉ. रंजना अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण रिसर्च को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान शरीर पर जो असर पड़ता है, वह इस बीमारी से भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। मसलन, कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाना, हृदय और किडनी पर असर पड़ना और शरीर के नॉर्मल सेल का इलाज के दौरान मर जाना। डीएनए से वह एक ऐसी तकनीक इजाद कर रही हैं, जिससे सिर्फ कैंसर के सेल्स ही खत्म हों। उनके साथ लगते दूसरे स्वस्थ सेल्स को नुकसान न हो। ऐसा भी नहीं है कि इसमें मानव शरीर का ही डीएनए इस्तेमाल होगा। व्हेल और गाय के बछड़े के डीएनए कंपाउंड बनाए जा सकते हैं।

बता दें कि डॉ. रंजना अग्रवाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीएससी, एमएससी तथा पीएचडी की डिग्री उत्तीर्ण करने के बाद कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड से एरिथ्रोमाइसिन बायोसिंथेसिस पर पोस्ट डॉक्टरल शोध किया है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिएस्ट जैसी कई प्रसिद्ध यूरोपीय प्रयोगशालाओं में शोध कार्य किया। वह अमेरिका, स्पेन और आयरलैंड के वैज्ञानिकों के साथ सक्रिय सहयोग से शोध कार्य कर रही हैं।

हरियाणा में देश का 30 फीसदी कैंसर

डॉ. रंजना अग्रवाल ने अपनी स्टडी के आधार पर बताया कि देश भर में कैंसर के जितने केस आ रहे हैं, उसका 30 प्रतिशत सिर्फ हरियाणा में हैं। इतने बड़े स्तर पर कैंसर बढ़ना निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही, आने वाले समय में यह और बढ़ेगा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे इलाज की खोज हो, जिसमें शरीर के साथ-साथ प्रकृति का भी नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि ग्रीन सिंथेसिस तकनीक पर वह डीएनए के जरिये कैंसर का इलाज तलाश रही हैं। सस्ता इलाज हो, इसके लिए अक्षय ऊर्जा से यह प्रयोग करने की कवायद है। हम इसी प्रयास में लगे हैं कि कैंसर से होने वाली मौतें कम कैसे हों। भूमिगत जल, तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, खाद्य प्रदूषण, पेस्टीसाइड और पराली जलाने के कारण हमारे यहां कैंसर की समस्या ज्यादा बढ़ी है।

कुंभ एक्सप्रेस में गंदगी के बीच बन रहा था खाना

जागरण संवाददाता, लखनऊ : ट्रेनों के रसोई यान में गंदगी के बीच खाना बनाकर यात्रियों को परोसा जा रहा है। बुधवार को जब कुंभ एक्सप्रेस में रेलवे ने छापा मारा तो रसोई यान में हर तरफ गंदगी मिली। निर्धारित दर से अधिक वसूली मिलने पर खानपान आपूर्ति का लाइसेंस लेने वाली फर्म पर जुर्माना लगाया गया। ट्रेन संख्या 12370 कुंभ एक्सप्रेस हरिद्वार से हावड़ा जा रही थी। यह ट्रेन सुबह 8:25 बजे लखनऊ से हावड़ा के लिए रवाना हुई। सहायक वाणिज्य प्रबंधक एसएस यादव के नेतृत्व में टीम ने यात्रियों से खान-पान के बारे में पूछताछ की।

यात्रियों ने बताया कि उनको सामान महंगी दर पर बेचा गया। सामान बेचने वाले रसोई यान के कर्मचारियों ने वर्दी भी नहीं पहनी थी। इसके बाद सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने रसोई यान की जांच की। यहां गंदगी के बीच खाना बनते पाया गया। रेलवे ने अप्रैल 2017 में नई खान-पान नीति लागू की थी। इसके तहत महत्वपूर्ण रेल खंडों के बड़े स्टेशनों पर आधुनिक बेस किचन बनाकर वहां तैयार खाना ही यात्रियों को बेचा जाना था। टाइम लाइन तय होने के बावजूद बेस किचन बनाने की योजना परवान नहीं चढ़ सकी है।

मां को सताने वाले बेटे को छोड़ना होगा घर, हर माह देने होंगे 50 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, कोडरमा

▶ घरेलू हिंसा के मामले में झारखंड के कोडरमा अदालत का आदेश

▶ बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर मां ने ली थी न्यायालय की शरण

घरेलू हिंसा के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए झारखंड स्थित कोडरमा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, ईला कांडपाल की अदालत ने एक वृद्ध माता को चिकित्सीय खर्च के रूप में 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश उसके पुत्र को दिया है। साथ ही वृद्धा को बेदखल कर वहां रह रहे पुत्र व पौत्र को घर से निकलने का आदेश दिया है।

मामला शहर के नामचीन व्यवसायी और समाजसेवी रहे स्व. प्रीतम सिंह कालरा के परिवार से जुड़ा है। प्रीतम सिंह कालरा की पत्नी 78 वर्षीय राजरानी ने अपने बड़े पुत्र कुलबीर सिंह कालरा व पौत्र गौतम सिंह कालरा पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय में दायर याचिका में उन्होंने कहा था कि कुलबीर सिंह कालरा व गौतम सिंह कालरा उनसे अलग शहर में किराए के मकान में रहते थे।

कुछ वर्ष पहले मेरे पति वृद्धावस्था के कारण कई बीमारियों से ग्रसित हो गए तो बड़े बेटे कुलबीर सिंह कालरा को पत्नी व बच्चों के साथ अपने आवास में रहने व स्वास्थ्य तथा व्यवसाय की देखभाल करने को कहा। इसके बाद कुलबीर का पूरा परिवार साथ रहने लगा व कालरा दंपती की संपत्ति व व्यवसाय की देखभाल करने लगा।

मार्च 2017 में उनके पति प्रीतम सिंह कालरा की मौत हो गई। इसके बाद कुलबीर सिंह कालरा ने उनकी देखभाल करनी छोड़ दी और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। इतना ही नहीं कुलबीर ने उनके घर पर कब्जा जमा लिया और जेवरात आदि छीन लिए। उनके खाते से करीब 20 लाख रुपये की निकासी भी अलग-अलग तिथियों में कुलबीर ने कर ली।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 20 जून 2019

दैनिक जागरण
प्रकृति सबसे बड़ी रचयिता है

व्यर्थ का बहिष्कार

यह अच्छा नहीं हुआ कि एक साथ चुनाव कराने के मसले पर प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में कांग्रेस समेत आठ राजनीतिक दलों ने भाग लेना भी उचित नहीं समझा। समझना कठिन है कि इन दलों के जो नेता यह कहते हुए दिख रहे हैं कि इस या उस कारण एक साथ चुनाव कराना ठीक नहीं उन्होंने अपनी बात उक्त बैठक में कहने की जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या यह दिखाने के लिए कि वे प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक का भी बहिष्कार कर सकते हैं? आखिर इस नतीजे पर क्यों न पहुंचा जाए कि ये राजनीतिक दल केवल विरोध के लिए विरोध दर्ज कराने की मानसिकता से ग्रस्त हैं? आखिर ऐसे दलों से यह अपेक्षा कैसे की जाए कि वे राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर आम सहमति की राजनीति के पक्षधर हैं? ध्यान रहे कि यही दल रह-रहकर यह शोर मचाते हैं कि मोदी सरकार सहमति की राजनीति पर यकीन नहीं रखती। सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार नकारात्मक राजनीति का प्रमाण ही नहीं, इस बात का सूचक भी है कि इस लोकसभा में भी विरोध की खातिर विरोध की राजनीति जारी रहने वाली है। सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाने वाले दल चाहे जो तर्क दें, वे इससे अनजान नहीं हो सकते कि बार-बार होने वाले चुनाव देश और खुद उनके संसाधन की बर्बादी का कारण बनते हैं। आखिर यह कितना उचित है कि करीब ढाई महीने लंबी चुनाव प्रक्रिया से मुक्त होते ही हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी होने लगी है? इन राज्यों के चुनावों के बाद कुछ और राज्यों में चुनाव की तैयारी होने लगेगी।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे दल अपने संकीर्ण स्वार्थों के आगे देश हित की चिंता करने के लिए तैयार नहीं। आम चुनाव के अतिरिक्त रह-रहकर होते रहने वाले विधानसभा चुनावों के कारण समय और संसाधन की जो बर्बादी होती है वह एक तरह से राष्ट्रीय क्षति होती है। यह क्षति इस कारण होती है, क्योंकि पक्ष-विपक्ष बार-बार के चुनावों के कारण शासन-प्रशासन को बेहतर बनाने और जन समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। आज यदि हमारा देश अनेक विकासशील देशों से पीछे है तो शायद इसका एक कारण रह-रहकर होने वाले चुनावों में समय और धन की बर्बादी भी है। कल्पना करें कि अगर 1967 के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हो रहे होते तो देश का कितना पैसा और वक्त बचा होता? एक साथ चुनाव के विरोध में दी जा रही दलीलों का ज्यादा मतलब इसलिए नहीं, क्योंकि आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। आखिर जो पहले संभव था वह अब क्यों नहीं हो सकता? सवाल यह भी है कि जब हाल के लोकसभा चुनावों के साथ ओडिशा, आंध्र, सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो फिर बाकी राज्यों के क्यों नहीं हो सकते? यह दलील भी खोखली ही अधिक है कि एक साथ चुनावों से क्षेत्रीय दल घाटे में रहेंगे, क्योंकि ओडिशा और आंध्र में क्षेत्रीय दल ही सरकार बनाने में सफल रहे हैं।

पुनर्वास नीति में आस्था

झारखंड में कभी खौफ का पर्याय रहा माओवाद शनैः शनैः दम तोड़ रहा है। नक्सली विचारधारा भी पश्चाताप की आग में पिघलने लगी है। सरकार की पुनर्वास नीति भी उनको मुख्यधारा की ओर मोड़ने में कारगर हो रही है। इसकी बानगी सोमवार को दुमका में दिखी जब राज्य के हार्डकोर नक्सलियों में शुमार पीसी दी, किरण टुडू, सिद्धो मरांडी समेत आधा दर्जन माओवादियों ने हथियार डाल दिए। इनमें कई पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में शामिल थे। बाकायदा सरकार की पुनर्वास नीति में आस्था जताते हुए दुमका एसपी वाईएस रमेश के समक्ष छह नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। संताल परगना के डीआइजी राजकुमार लकड़ा ने इस दिन को दुमका के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला बताया। वहीं एसपी ने कहा कि हार्डकोर का सरेंडर करना बताता है कि पुलिस अगर सख्त है तो संवेदनशील भी। और ऐसा है भी। नक्सल आंदोलन को ध्वस्त करने की दिशा में यह सरकार की बड़ी सफलता है। यह सच्चाई है कि माओवादी यदि मुख्यधारा में लौट आते हैं तो कई इलाके जहां विकास नहीं पहुंच सका है, वे भी दमक उठेंगे। माओवादियों को मुख्यधारा में लाने का श्रेय निश्चित ही प्रशासन को दिया जाएगा। पुलिस का मानवीय चेहरा इस मामले में सामने आया। जिन सुरक्षाबलों के खिलाफ नक्सलियों ने हथियार उठाया उन्होंने ही पीसी दी का इलाज करवाया। नक्सलियों ने अपनी जो दास्तां सुनाई उससे साफ होता है कि गरीबी, व्यवस्था के प्रति आक्रोश और अपनों की अनदेखी के कारण वे राह भटक गए। ये हुक्मरानों और नीति नियंताओं को भी आगाह करती है और उनकी जिम्मेदारी बढ़ा देती है। रोजगार के मामले में झारखंड की स्थिति बेहद खराब है। संताल से लेकर कोयलांचल और अन्य इलाकों में पलायन बड़ी समस्या बन चुका है। हर हाथ को काम देने के लिए बेशक सरकार अनेक योजनाएं ला रही है, मगर उन खामियों को दूर करना होगा जिनके कारण गरीब को इसका लाभ ही नहीं मिल पाता। पिछड़े इलाकों में अगर विकास योजनाओं का लाभ लोगों को मिले तो निश्चित तौर पर कोई मासूम ग्रामीणों को भटका नहीं पाएगा।

मुस्लिम विमर्श में बदलाव के संकेत

डॉ. एके वर्मा

आज जरूरत इसकी है कि समाज को बांटने वाले मुस्लिम, दलित, पिछड़ा आदि अनेकानेक विमर्शों को भारतीयता के फ्रेमवर्क में चलाया जाए

भारत में मुस्लिम-विमर्श को हमेशा हिंदू-मुस्लिम और सेक्युलर-सांप्रदायिक चश्मे से देखा गया है। संभवतः इसलिए कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाजपा को सांप्रदायिक ठहराया जाए और अन्य दल 'स्वघोषित' सेक्युलरवादी बताए जाएं ताकि मुसलमानों को लामबंद कर उनके वोट पर एकाधिकार किया जा सके। इसीलिए कट्टर और सांप्रदायिक मुस्लिम भी सेक्युलर जमात में शरीक हो जाते हैं और सेक्युलर पार्टियों की आड़ में मुस्लिम सांप्रदायिकता को अंजाम देते हैं। कांग्रेस सहित मुलायम और अखिलेश यादव की सपा, मायावती की बसपा, अजीत सिंह की रालोद, लालू प्रसाद यादव की राजद, ममता बनर्जी की तृणमूल और नीतीश कुमार की जदयू कभी भी मुस्लिमों पर अंगुली उठाना पसंद नहीं करतीं। अन्य क्षेत्रीय दलों जैसे आंध्र में वाइएसआर कांग्रेस, तेलुगु देसम पार्टी, केरल में यूडीएफ और एलडीएफ, तमिलनाडु में द्रमुक एवं अन्नाद्रमुक का और तेलंगाना में टीआरएस का यही हाल है। इस तरह की राजनीति से देश, मुस्लिम समाज और इन दलों का ही नुकसान हुआ है। इस राजनीति से समाज में गंगा-जमुनी संस्कृति को पनपने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि इसने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया और प्रत्येक सांप्रदायिक विवाद में हिंदुओं और भाजपा को ही दोषी ठहराया।

हमारे नेता कभी यह साहस नहीं कर सके कि मुस्लिम समाज की गलतियों को भी इंगित करें। इससे सांप्रदायिक किस्म के मुसलमानों में यह भाव घर कर गया कि वे कुछ भी करें, सेक्युलर पार्टियां उन्हें कुछ नहीं कहेंगी। परिणामस्वरूप हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार गलत होने लगा जिससे हिंदू-मुस्लिम रिश्तों में कटुता आई। दूसरे हिंदुओं में यह भाव पैदा हुआ कि भाजपा को छोड़ उनकी तरफदारी करने वाला कोई दल नहीं। हिंदू समाज से पिछड़ों और दलितों को निकाल दें तो केवल 19 फीसद सवर्ण कहे जाने वाले लोग बचते हैं। इसीलिए सेक्युलर दल सदैव प्रयत्नशील रहे कि पिछड़ों और दलितों को हिंदू समाज से काट दो तो हिंदू अपने आप समाप्त हो जाएगा। देश के विभाजन का दर्द आज तक सालता है। संविधान बनाने वालों ने भी इसीलिए मुस्लिमों हेतु विशेष मौलिक अधिकारों की व्यवस्था बनाई और जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के माध्यम से विशेष प्रावधान किया, लेकिन इससे मुस्लिमों की समस्याएं बढ़ी हीं। वे हमेशा अपने को कटा-कटा, असुरक्षित और अल्पसंख्यक समझते रहे जबकि हिंदू समाज ने उन्हें अपने में समाहित करने की कोशिश की। मुसलमानों में उच्च-जाति अर्थात अशरफ मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से संपन्न रहे। इसका लाभ उठाकर उन्होंने राजनीति में पैठ बना ली और अपनी पार्टी के इशारों पर पिछड़े और दलित मुस्लिमों अर्थात अजलाफ और अर्जाल मुस्लिमों या पसमांदा मुसलमानों को गोलबंद कर अपनी पार्टी के लिए वोट-बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। इसके लिए वे हमेशा उन्हें हिंदुओं और खासकर भाजपा का भय दिखाते जिससे वे उनके वोट-बैंक के रूप में बने रहें।

अवधेश राजपूत

विश्व में हिंदू समाज निहायत अल्पसंख्यक समाज है और फिर भी उसके कुछ अपने ही लोग हिंदू होने को जैसे सांप्रदायिकता का पर्याय बनाने पर तुले हैं। यह हिंदुओं को परेशान करता है। नरेंद्र मोदी ने 2014 से इस पूरे विमर्श की दिशा बदल दी जब उन्होंने 130 करोड़ भारतवासियों से 'मन की बात' द्वारा प्रति माह बातचीत शुरू की और सुशासन एवं विकास पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। स्वतंत्रता के बाद से अब तक मुस्लिम और भाजपा (पहले जनसंघ) एक-दूसरे से दूर रहे, लेकिन मोदी ने मुसलमानों के प्रति कोई अल्पसंख्यकवादी या सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। उनका फोकस 130 करोड़ देशवासियों पर ही रहा। उनका मानना है कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक बताकर ठगा गया और उनके वोट हथियाए गए। मोदी ने पहली ही पारी में सरकार का फोकस जात-पांत और बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक के बजाय ऐसे विकास पर रखा जो सभी को लाभ पहुंचाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विकास योजनाएं कागज पर न होकर जमीन पर दिखाई दें। इससे मुस्लिम समाज को लाभ मिला और वह भी एक ऐसी पार्टी की सरकार से जिसे वे अमूमन वोट देने से कतराते रहे। इसी के साथ मोदी ने मुस्लिम समाज में तत्काल तीन तलाक पर कानूनी पहल की जो कोशिश की, उससे मुस्लिम महिलाओं के एक बड़े वर्ग में आशा की किरण जगी। यह सत्य है कि मुसलमानों में तीन-तलाक के मामले बहुत कम हैं, लेकिन यह जरूर है कि मुस्लिम महिलाओं पर उसकी तलवार हमेशा लटकती रहती है। तत्काल तीन तलाक से संबंधित महिला के परिवार की कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं।

आज कोई भी मुस्लिम परिवार तलाक की त्रासदी नहीं झेल सकता। यही कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में जहां देश के आठ फीसद मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया वहीं 2019 के चुनावों में 14 प्रतिशत मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। इससे भाजपा अकेले दम पर देश में 300 सीटों का आंकड़ा पार कर गई। सेक्युलर पार्टियों के लिए यह बेचैनी का सबब जरूर है, लेकिन इसे समावेशी राजनीति की ओर भाजपा के बढ़ते कदम भी कहा जा सकता है। दूसरी पारी की शुरुआत में ही मोदी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मुस्लिम समाज का दिल जीत लिया। उन्होंने देश में 5.77 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की 'जीआइएस-मैपिंग' कराने का निर्णय लिया ताकि उनकी पहचान करने और उनसे अतिक्रमण हटाने में मदद मिले। इन संपत्तियों की 'जिओ-टैगिंग' और 'डिजिटलीकरण' से उनके मालिकाना हक में पारदर्शिता आएगी। ऐसी जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बहु-उपयोगी हॉल, सद्भाव-मंडप आदि बनेंगे। मदरसे के शिक्षकों को विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी का भला होगा तथा मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का मोदी का सपना साकार हो सकेगा। मुस्लिम समाज ने इस पहल की प्रशंसा की है।

पीएम मोदी की मुस्लिम समाज से केवल इतनी ही अपेक्षा है कि वे देश के अन्य नागरिकों की तरह ही रहें और अल्पसंख्यक-सिंड्रोम से बाहर निकलें। आखिर मुस्लिम समाज को हिंदुओं से क्यों द्वेष होना चाहिए? क्या कभी मुस्लिम समाज से हिंदुओं की बेहतरी के लिए कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए? 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद लाहौर में एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान देकर लौटने के बाद मुझे यही लगा कि भारतीय मुस्लिमों को पाकिस्तानी दुष्प्रचार में न पड़कर वहां की जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो आज भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। आज जरूरत इसकी है कि समाज को बांटने वाले मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, महिला आदि विमर्शों को भारतीयता के फ्रेमवर्क में चलाया जाए जिससे इन विमर्शों का स्वरूप रचनात्मक और सकारात्मक हो सके। इससे ही देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में मदद मिलेगी। राजनीति के मोदी-मॉडल ने इस ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

सबको पेयजल पहुंचाने की चुनौती

रमेश कुमार दुबे

यह विडंबना ही है कि चांद पर उपग्रह भेजने वाले देश की 82 फीसद ग्रामीण आबादी साफ पानी के लिए तरस रही है

आजादी के बाद से ही बिजली-पानी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़े गए, लेकिन आम आदमी को बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं अपेक्षा के अनुरूप उपलब्ध नहीं हो पाईं। 16वीं लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 1000 दिनों के भीतर अंधेरे में डूबे 18,452 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा जिसे तय समय से पहले हासिल कर लिया गया। इसके बाद हर घर को रोशन करने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की गई। इसे भी अभूतपूर्व कामयाबी मिली। इसी तरह का अभियान शौचालय बनवाने के लिए चलाया गया। 2014 में जहां 33 फीसद परिवारों तक शौचालय सुविधा थी वहीं 2019 में यह अनुपात बढ़कर 99 फीसद तक पहुंच गया। जिस देश में योजनाओं की लेटलतीफी का रिकॉर्ड रहा हो वहां ऐसी उपलब्धि किसी क्रांति से कम नहीं है।

बिजली आपूर्ति और शौचालय निर्माण को मिली अभूतपूर्व कामयाबी से उत्साहित भाजपा ने 17वीं लोकसभा के चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में वादा किया कि सत्ता में वापसी पर जल प्रबंधन के लिए नए मंत्रालय का गठन करेंगे। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादे को अमली जामा पहनाते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ-साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया। मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक में ही 2024 तक देश के हर घर तक 'नल से जल' पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर दिया है। जिस देश में 82 फीसद ग्रामीण परिवारों की साफ पेयजल तक पहुंच न हो वहां पांच साल के अंदर 14 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाना असंभव नहीं तो मुश्किल काम जरूर है। इसका कारण है कि देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की स्थिति बेहद गंभीर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 22 फीसद ग्रामीण परिवारों को पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर और इससे अधिक दूर पैदल चलना पड़ता है। इनमें से अधिकतर बोझ महिलाओं को ढोना पड़ता है। गांवों में 15 फीसद परिवार बिना ढके कुओं पर निर्भर हैं तो अन्य लोग दूसरे अपरिष्कृत पेयजल संसाधनों जैसे नदी, झरने, तालाबों आदि पर निर्भर रहते हैं। महज 18 फीसद परिवारों के पास ही पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल की सुविधा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में जलापूर्ति की स्थिति बेहद खराब है जहां पाइपलाइन से आपूर्ति पांच प्रतिशत से भी कम है। अभी देश के एकमात्र राज्य सिक्किम के 99 फीसद घरों में नलों से जलापूर्ति की जाती है। इसके बाद गुजरात का स्थान है जहां 75 फीसद लोगों को पाइपलाइन से पेयजल मिलता है। जलापूर्ति की ऐसी स्थिति के बावजूद कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि का भी उपयोग नहीं कर पाती हैं।

नीति आयोग ने 2018 में अपने दृष्टिकोण पत्र में बताया था कि 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। हर साल दो लाख लोग साफ पानी न मिलने से होने वाली बीमारियों के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। अनुमान है कि 2030 तक देश में पानी की मांग आज की तुलना में दो गुनी हो जाएगी। यदि इसे पूरा नहीं किया गया तो इससे सकल घरेलू उत्पाद में छह प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। सबसे चिंता की बात यह है कि देश में 70 प्रतिशत जल भंडार प्रदूषित हो चुके हैं। इसका कारण केंद्रीय भूजल बोर्ड की भीमकाय परियोजनाएं हैं जिन्हें 1970 के दशक में भौगोलिक परिस्थितियों की उपेक्षा करके लागू किया गया जिनसे भूजल का तेजी से दोहन हुआ। यह विडंबना ही है कि जो देश चांद पर उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका हो वहां की 82 फीसद ग्रामीण आबादी साफ पानी के लिए तरस रही है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद गांवों में पेयजल पहुंचाने की योजनाएं नहीं बनीं। कई योजनाएं बनीं और धन का आवंटन भी हुआ, लेकिन जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार के चलते नतीजे ढाक के तीन पात वाले रहे।

ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए भारत सरकार ने पहला ठोस प्रयास 1986 में किया जब राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई। आगे चलकर इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन 40 लीटर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता न मिलने पर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक-प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते इसे भी सफलता नहीं मिली। 2014 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को पुनर्गठित करते हुए इसे परिणामोन्मुखी और प्रतिस्पर्धी बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां 2013-14 में गांवों में पाइपलाइन के जरिये पानी पहुंचाने की वृद्धि दर 12 फीसद थी वह 2017-18 में बढ़कर 17 फीसद हो गई। इस कार्यक्रम के तहत फरवरी 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता योजना शुरू की गई। इसके तहत 2020 तक आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 बस्तियों को साफ पानी देने का लक्ष्य है। इसके अलावा 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्षों के लिए विश्व बैंक के सहयोग से भूजल प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की लागत से अटल भूजल योजना लागू की गई। इसमें उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जहां भूजल का अतिदोहन किया गया है। राजनीतिक-प्रशासनिक प्रतिबद्धता और सतत निगरानी से हर घर तक नल से जल पहुंचाने में सरकार भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन इन नलों से जलापूर्ति होती रहे इसके लिए अलग से प्रयास करने होंगे। गौरतलब है कि देश में औसत 117 सेंटीमीटर बारिश होती है जिसमें महज छह प्रतिशत का भंडारण हो पाता है। इसके अलावा कई तरह की भौगोलिक, तकनीकी और आर्थिक कठिनाइयां आएंगी जैसे ग्रामीण इलाकों में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से मोटर की खराबी, पाइपलाइन का रखरखाव, पानी का लीकेज। इसे देखते हुए नल से जल को पूरा करने के लिए सरकार ने लचीला दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया है। इसके तहत भूजल और सतह के जल, दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा जो क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सबसे बढ़कर इस योजना में आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार जलदूतों की नियुक्ति करेगी।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परमात्मा

हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बलहीन को परमात्मा नहीं मिलते। तो क्या जो लोग संसार में बलहीन हैं, उन्हें परमात्मा नहीं मिलते? वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी-सी गड़बड़ी है। बल क्या है? बल का अर्थ है एनर्जी। प्राकृतिक शक्ति जब जीव के लिए कार्य करती है, तब उस शक्ति को बल कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बल का अर्थ दूसरा है। जो अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का जितना अंश उपयोग करता है, वह उतना ही अधिक बलवान है, उतना ही अधिक शक्तिशाली है।

एक कहानी भी है। समुद्र पर पुल बनाते समय जब हनुमान जी पहाड़ उठाकर लाए थे, तब गिलहरी भी रोड़ा लाई थी, वह तो पहाड़ ला नहीं सकी। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कार्य छोटा था। हो सकता है कि उसका कार्य हनुमान जी के कार्य से बड़ा हो। अतः आध्यात्मिक शक्ति या मानसिक शक्ति या शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई बलवान या निर्बल नहीं होता। इस संदर्भ में विचार करना है कि जिसके पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति है, उसका वह कहां तक उपयोग करता है।

यहां जितने लोग हैं, उनमें कोई भी बलहीन नहीं है। जो शख्स अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं करता है, वह बलहीन है, वह परमपुरुष को नहीं पा सकता। आप लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत तो कर रहे हो, अतः आप परमपुरुष बन सकते हैं। साधना प्रमादमुक्त यानी दोषमुक्त होनी चाहिए। साधना जहां प्रमादमुक्त होती है और जहां बल है, वहां सफलता की गारंटी है। जिन लोगों की साधना प्रमादमुक्त है, वे सफल सफल होंगे। आप लोग परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहते हैं, जन्म-मरण से मुक्त होना चाहते हैं तो वह भी इसी जन्म में संभव है। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग इसी जीवन में अपना काम कर लें। दूसरे जन्म के लिए काम छोड़ना समय नष्ट करना है। हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि आप लोगों का कीमती समय नष्ट हो। हम चाहते हैं, इसी जन्म में आप अपना काम कर लें। इसी जन्म में काम पूरा कर लेने की इच्छा होगी तो इसी जन्म में काम पूरा हो जाएगा। इससे अगले जन्म के लिए कुछ सद्कर्म संचित हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जय की चिंता तुम्हें नहीं करनी है जय तो तुम्हारी जेब में है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

राजनीति में धनबल का बढ़ता बोलबाला

रिजवान अंसारी

राजनीति में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर तभी मिल सकेगा जब चुनाव में पैसे का खेल बंद होगा

एक गैर लाभकारी शोध संस्था 'सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज' के अध्ययन में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक हालिया लोकसभा चुनाव में 55-60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। इतनी बड़ी रकम सुनने में किसी तिलिस्म से कम नहीं लगती और इस चकाचौंध में लोगों के जायज मुद्दे हमेशा दबते चले जाते हैं। सवाल है कि आगे की राह क्या हो? दरअसल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राजनीति में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर मिले। यह तभी संभव है जब चुनाव में पैसे का खेल बंद होगा। इससे सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल पाएगा। लिहाजा देश के विकास में विभिन्न प्रकार की सोच को जगह मिल सकेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश की राजनीति में एक ही वर्ग अर्थात धनी वर्ग का ही बोलबाला रहेगा और देश की अधिकांश आबादी राजनीति से वंचित रह जाएगी। जाहिर है इससे राजनीति का विकास कतई नहीं होगा, बल्कि देश की राजनीतिक शुचिता पतन की ओर अग्रसर हो जाएगी।

पिछले साल ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा 16वीं लोकसभा के सांसदों पर किए गए अध्ययन ने भी चौंकाया था। जिन 521 सांसदों पर अध्ययन किया गया था उनमें से 430 सांसद करोड़पति थे। 32 सांसद तो ऐसे थे जिनके पास 50 करोड़ रुपये तक की संपत्ति थी। 16वीं लोकसभा सदस्यों की औसत संपत्ति 14.72 करोड़ रुपये थी। 17वीं लोकसभा ने तो पिछली लोकसभा के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एडीआर के मुताबिक नई लोकसभा में 475 सांसद करोड़पति हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव ने तो सबको हैरान कर दिया है। इसमें जीते 94 फीसद विधायक करोड़पति हैं। जाहिर है भारतीय राजनीति पर धनकुबेरों का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। समझना होगा कि असमानता चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक, इसे पाटने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लिहाजा यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पैसों के खेल पर अंकुश लगाने पर जोर दे और साफ-सुथरी चुनावी प्रक्रिया की संकल्पना लेकर आगे बढ़े।

गौर करें तो इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगा। उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च किसी व्यवसाय में निवेश से कम नहीं लगता। चुनाव में लाखों-करोड़ों रुपये का खर्च उम्मीदवारों को महत्वाकांक्षी बना देता है और उस खर्च को वे हर हालत में वापस पाना चाहते हैं। इसके लिए वे कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लिहाजा यह सोच उन्हें चुनाव नतीजों से पहले ही भ्रष्ट बना देती है। पैसे के खेल पर अंकुश लगा कर अगर चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरी बनाई जाए तो इससे भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर चुनाव लड़ने से जनसेवा की भावना को भी बढ़ावा मिल सकेगा। लिहाजा राजनीतिक शुचिता पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकेगा। बहरहाल इस दिशा में हमें संजीदगी से सोचना ही होगा, अन्यथा धन अर्जित करना भारतीय राजनीति के लिए नासूर बन जाएगा और संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना तक हमारी पहुंच दूर की कौड़ी साबित होगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अतार्किक विरोध की मानसिकता

नकारात्मक राजनीति के नए संकेत शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजीव सचान ने अतार्किक विरोध की जिस विपक्षी राजनीति को रेखांकित किया है, वह सदन के अंदर या बाहर सत्ता पक्ष का नीतिगत विरोध करने के बजाय केवल विरोध के लिए विरोध करने की विकृत मानसिकता है, जिससे बचा जाना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक जमाना था जब कुछ सुलझे हुए वरिष्ठ सांसद लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की भूमिका को नीतिगत विरोध के रूप में तार्किक अंदाज में निभाते थे। सत्ता पक्ष उनकी बात को न केवल ध्यान से सुनता था, अपितु उस पर अमल भी करता था। ऐसे विपक्षी सांसद राष्ट्रहितैषी मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष के साथ रचनात्मक सहयोग करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। अपने संसदीय जीवन में अधिकांश समय तक विपक्ष की भूमिका में रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से अधिक एक सुलझे हुए विपक्षी नेता के रूप में इसीलिए याद किए जाते हैं, क्योंकि वे सत्ता पक्ष का नीतिगत और तार्किक विरोध करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रचनात्मक सहयोग करने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन आज विपक्ष की तस्वीर इससे उलट है, जिसमें प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को अतार्किक रूप से 'चोर' बताने में ही अपनी काबिलियत मानने लगे। यद्यपि देश की जनता को विपक्ष की यह नकारात्मक राजनीति रास नहीं आई। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को अपनी पराजय से यह सबक लेने की जरूरत है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को अब यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

वर्षा जल का सरंक्षण

आज विश्व पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। भविष्यवाणी की जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? क्या वास्तव में प्राकृतिक जल हमारे पास नहीं है? अगर नहीं है तो बारिश के दिनों में ये बाढ़ से तबाही क्यों मचती है? इसका मतलब हमारे पास पानी की कमी नहीं है, बल्कि हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। क्या आज के वैज्ञानिक उपलब्ध अथाह जल को उपयोग लायक बनाने का उपाय नहीं खोज पा रहे हैं? सभी को पता है कि वर्षा का जल नदी नालों द्वारा समुद्र में जाकर अनुपयोगी हो जाता है। क्या हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों के पास इस अपार जन उपयोगी जल शक्ति को संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं है? क्या हम बाढ़ आने वाली नदियों के समानांतर नहरें, नाले आदि बनाकर इस बह जाने वाले पानी को नियंत्रित नहीं कर सकते? जल संरक्षण हम डैम बनाकर भी तो करते हैं। जब हम जमीन के नीचे मेट्रो रेल बना रहे हैं, हजारों किलोमीटर लंबी गैस एवं तेल की पाइप लाइन जंगल, पहाड़ एवं समुद्र लांघ कर ला रहे हैं और चांद पर आवासीय कॉलोनी बसाने की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर हम इस बह जाने वाले पानी को संरक्षित क्यों नहीं कर सकते हैं। जमीन के नीचे जलाशय बनाने से उपजाऊ जमीन भी खराब नहीं होगी। यह संग्रहित जल को खेती एवं पीने योग्य बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रयास से भूजल स्तर भी बढ़ेगा। इससे जल क्रीड़ा पर्यटन भी विकसित हो सकता है। पंपों में सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है।

devsinghal1953@gmail.com

इलेक्ट्रिक वाहन

नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के विक्रय का प्रस्ताव दिया है। इसमें छोटी-बड़ी सभी गाड़ियां शामिल हैं। ऐसा करने से कच्चे तेल के आयात पर होने वाले खर्च पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहन, भविष्य की मांग और वर्तमान की जरूरत है। इस प्रस्ताव पर अमल होना ही चाहिए, ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो। रोजगार और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहनों से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है।

sonimohit895@gmail.com

संसद में नारेबाजी

संसद में धार्मिक आधार पर नारेबाजी घोर निंदनीय है। सांसद जो कुछ भी आचरण करते हैं उसका संदेश पूरे देश में जाता है। सांसदों का काम देश की ज्वलंत समस्याओं को उठाना और उनका समाधान कराना है, वहां नारेबाजी करना नहीं।

श्रीनिवास यादव, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

91,968 मामले एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के भारत में 2011 से लेकर अब तक सामने आ चुके हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। इनमें से 11,254 बच्चे मौत के मुंह में समा गए हैं।

आजकल

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

इन बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार

बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की हो रही मौत पर देश में हाहाकार मचना स्वाभाविक है। प्रश्न है कि जांच से शरीर के अंदर की समस्याओं की पूरी जानकारी होने तथा उनका उपचार स्पष्ट होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु क्यों हो रही है? इसका एक ही उत्तर है, व्यवस्था की आपराधिक अनदेखी। वास्तव में प्रदेश सरकार विशेषकर इसका स्वास्थ्य महकमा सतर्क और तैयार होता तो यह बीमारी महात्रासदी में कतई परिणत नहीं होती

बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की हो रही मौत पर देश में हाहाकार मचना स्वाभाविक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहला, अभी तक के किसी रिसर्च में लीची से इसका संबंध नहीं पाया गया है। इसलिए लीची खाने से बीमारी होने की बात बिल्कुल निराधार है। दूसरे, कुछ वर्ग या जाति के बच्चों का बीमारी से गस्त होने का विश्लेषण भी गलत है। एक भौगोलिक क्षेत्र में इस बीमारी का प्रकोप है और वह जाति या वर्ग को पहचान कर ग्रसित नहीं करती। तीसरे, इस बीमारी को मेडिकल भाषा में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम या एईएस अवश्य कहा गया है, लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि यह अभी तक की मान्य इंसेफलाइटिस नहीं है। उसकी तरह के कुछ लक्षण हैं। यानी यह अलग किस्म की बीमारी है जिसे स्थानीय भाषा में चमकी कहा जाता है। चौथे, यह कहना गलत है कि इस बीमारी का कारण समझने के लिए अनुसंधान नहीं हुए। नई दिल्ली की नेशनल काउंसिल ऑफ डिजीज कंट्रोल और पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम ने कई साल बीमारी के समय वहां जाकर काम किया। बीमार बच्चों के सैंपल लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मच्छर, जानवर एवं कीट-पतंगों पर भी अध्ययन किया, लेकिन यह पता नहीं लग सका कि बीमारी का कारण क्या है? विदेश की संस्था को बुलाकर भी अनुसंधान कराया गया और वह भी असफल रही। चूंकि आप बीमारी का कारण नहीं समझ पाए इसलिए इसे कोई निश्चित नाम दिया भी नहीं जा सकता।

हालांकि बीमारी का कारण पता न चलने का अर्थ यह नहीं है कि इसका उपचार भी उलझा हुआ है। बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जानते हैं कि इसका इलाज कठिन नहीं है। पैथोलॉजी रिपोर्ट के अध्ययन में सभी बच्चों में समान समस्याएं पाई गई हैं। सभी बच्चों में लीवर, किडनी और फेफड़ों में संक्रमण पाया गया। मूल बात है खून से सूगर का काफी कम हो जाना। बच्चों में ग्लूकोज लेवल का सबसे न्यूनतम स्तर 20-35 देखा गया है। सोडियम की कमी भी पाई गई है। प्रश्न है कि पैथोलॉजी से शरीर के अंदर की समस्याओं की पूरी जानकारी होने तथा उनका उपचार स्पष्ट होने के बावजूद इतनी संख्या में बच्चों की मृत्यु क्यों हुई? इसका एक ही उत्तर है, व्यवस्था की आपराधिक अनदेखी। वास्तव में प्रदेश सरकार विशेषकर इसका स्वास्थ्य महकमा सतर्क और तैयार होता तो यह महात्रासदी में कतई परिणत नहीं होती। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का एक प्रमुख शहर है जहां सरकारी और निजी अस्पताल एवं डॉक्टर पर्याप्त संख्या में हैं। किंतु उन सबकी परिणामकारी उपयोगिता तभी संभव है जब स्वास्थ्य विभाग सतर्क होकर बीमारी से निपटने के लिए जो मानवीय एवं मेडिकल संसाधन चाहिए वह समय पूर्व उपलब्ध कराए एवं सक्रिय रहे।

ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 21 मई को बच्चे की चमकी से मौत की पहली सूचना आई। उसके बाद बच्चे मरते रहे। स्थानीय मीडिया बीमार बच्चों के दम तोड़ते, अस्पतालों की भयावह कुव्यवस्था एवं डॉक्टरों, नर्सों से लेकर दवा तक के अभाव की खबरें देता रहा, लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगी। लगा ही नहीं कि प्रदेश सरकार एवं विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय को इससे कोई लेना-देना भी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री 14 जून को कुछ घंटे के लिए वहां गए। उनका बयान था कि जो मानक प्रणाली है उसके तहत इलाज किया जा रहा है। एंबुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। उनका बयान सुनकर उन सब लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ जो यह उम्मीद कर रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री सारी कमियों का विवरण देते हुए उसे दूर करने का कदम उठाएंगे और जैसी आवश्यकता थी वहां अपने अधिकारियों के साथ कैंप करेंगे। किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ घंटे का दौरा करके वापस चले गए। उनके आने के दिन तक 80 से ज्यादा बच्चे सही इलाज न मिलने के कारण मौत के मुंह में समा चुके थे। उनके रहते भी बच्चे मर रहे थे। उनके जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। उसके बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वे भी गए। केंद्रीय स्वाथ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. अश्विनी चौबे भी गए। बावजूद यदि बच्चे मरते रहे, व्यवस्था बदली ही नहीं तो फिर ये वहां गए क्यों थे? 100 बेड का आइसीयू बनाएंगे, रिसर्च करवाएंगे, कुछ डॉक्टर भेजेंगे...यही बयान आया।

यह बात समझ से परे थी कि जो बीमारी स्वास्थ्य आपातकाल की मांग कर रही हो उसके साथ मंत्री और विभाग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अस्पतालों की समस्याएं क्या थीं? आइसीयू या पीआइसीयू की कमी और उसका मानक स्तर पर न होना ऐसा था जिसे रातोंरात नहीं बदला जा सकता था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हो सकता था। विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और दवा का अभाव मौत का कारण था और इन कमियों को कुछ घंटे में दूर किया जा सकता था। केंद्र और राज्य, दोनों के पास इतनी क्षमता थी कि आपातकाल मानकर डॉक्टरों, नर्सों को दवाइयों के साथ वहां पहुंचाया जा सकता था। इसमें स्वास्थ्य के अलावा आपदा से जुड़े सभी विभागों को लगाने की आवश्यता थी और है।

जरा सोचिए, अस्पताल के नलों से पीने का पानी नहीं आ रहा था। यह टेलीविजन दिखा रहे थे, लेकिन किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि कम से कम अपने सामने पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इससे बड़ी आपराधिक अनदेखी और क्या हो सकती है? इसके बाद यह बताने की आवश्यता नहीं कि उन मृत बच्चों के लिए जिम्मेवार कौन हैं?

यह बीमारी कोई पहली बार सामने नहीं आई है। यहां उन आंकड़ों को गिनाना जरूरी नहीं है। हर वर्ष कम या ज्यादा संख्या में बच्चे चमकी से ग्रस्त होते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं कुछ मार्गनिर्देश तय किए हुए हैं। इनमें सबसे पहला है, जन जागरूकता। इसके लिए पर्चे बने हैं, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बोर्ड लगे हैं। यह स्वास्थ्य विभाग का दायित्व था कि मार्च-अप्रैल में आशा कार्यकर्ता, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी सबकी बैठक लेकर जन जागरूकता का अभियान चलाए। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरंभिक इलाज के संसाधन पहुंचाए तथा वहां के डॉक्टरों को निर्देश के साथ सचेत करे। उसके बाद जिला के मुख्य अस्पतालों की स्थितियों का मूल्यांकन कर जो स्थानीय स्तर पर संभव है वह पूर्वोपाय किया जाए, जो नहीं है उनकी मांग प्रदेश सरकार से की जाए। इसमें प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की भी भूमिका थी। जाहिर है, विभाग अगर पहले के अनुभव के आधार पर अपनी जिम्मेदारी का पालन करता तो काफी हद तक इतनी बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था। नीतीश सरकार की इसके लिए निश्चित रूप से आलोचना होगी कि इतने लंबे शासन में पहले से बने हुए अस्पतालों का इतना उन्नयन नहीं किया जा सका कि वे आपातस्थिति से निपटने में सक्षम हों।

व्यवस्था की अनदेखी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

बिहार में चमकी बुखार ने पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेतिया, मोतिहारी, वैशाली, छपरा, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण क्षेत्रों में कहर ढाया हुआ है। किंतु इसका प्रभाव मुजफ्फरपुर और इसके इर्द-गिर्द इलाकों में ज्यादा है। यह बुखार 6 माह के बच्चे से लेकर 15 वर्ष के किशोरों तक को अपनी जानलेवा गिरफ्त में ले लेता है। यह कुपोषित बालकों को जल्द अपनी चपेट में ले लेता है। इसने सबसे ज्यादा कहर बालिकाओं पर बरपाया है। अब तक मरने वाले बच्चों में 85 बच्चियां हैं।

यह बीमारी संक्रमण के चलते शरीर में फैलती है। शुरुआत में यह मस्तिष्क में सूजन लाने के साथ दिमाग के ऊतकों पर हमला बोलती है। इस कारण प्रतिरक्षात्मक तंत्र प्रभावित हो जाता है। इन दुष्प्रभावों के असरकारी होते ही सिर में दर्द के साथ तेज बुखार के लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। जब समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता और बुखार चढ़ा ही रहता है तो मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है और शरीर कांपने लगता है। चमकी का प्रकोप मई-जून की चिलचिलाती धूप में ही अक्सर देखा जाता है। इस दौरान तेज धूप और गर्मी बच्चों का पसीना निकाल देती है। नतीजतन शरीर में पानी की कमी आ जाती है। इस वजह से डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, थकान, भूख में कमी, बेहोशी और लकवा के लक्षण महसूस होने लगते हैं, जो चमकी बुखार के स्पष्ट संकेत हैं। ये लक्षण सीधे-सीधे स्नायु-तंत्र और तंत्रिका-तंत्र को प्रभावित करते हैं। गर्मी के साथ मानसून पूर्व बारिश हो जाए तो मौसम में नमी आ जाती है। गर्मी और नमी का यह विचित्र संयोग ऐसी स्थिति है जो एईएस के फैलने की गति बढ़ा देती है। चमकी बुखार एक संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। इसलिए इस रोग के लक्षण सामने आ जाएं, तब उस बच्चे के मल-मूत्र, थूक, लार और छींक जैसे तरल पदार्थों से अन्य बच्चों को दूर रखना चाहिए।

चमकी ने बिहार में पहली बार 1994 में कहर ढाया था। तब भी चिकित्सा विशेषज्ञों और सरकार ने गंदगी, दूषित जल, भूख और खाली पेट लीची खाना इस बीमारी की वजह बताई थी। चमकी बुखार की आमद भारत में ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जद में दुनिया के 24 देश हैं। इन देशों के तीन करोड़ बच्चों पर इस महामारी का खतरा मंडरता रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 से लेकर अब तक चमकी और जापानी बुखार यानी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के 91,968 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 11,254 बच्चे मौत के मुंह में समा गए हैं। इनमें से 90 फीसद पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे रहे हैं। भारत के 20 राज्यों के 178 जिलों में इस बीमारी का प्रकोप लगभग हर साल बच्चों पर मौत का कहर बनकर टूटता है। डब्ल्यूएचओ इन दोनों बुखारों की वजह क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर को मानता है। इस कारण जिन 24 देशों में यह बुखार कहर ढाता है, उनमें हर साल 13,600 से लेकर 20,400 बच्चों की मौतें हो जाती हैं। डब्ल्यूएचओ ने एईएस को रोगों का एक ऐसा समूह घोषित किया हुआ है, जिनमें कई रोगों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, लिहाजा चिकित्सकों को मुख्य बीमारी चमकी या जापानी बुखार को समझने में कठिनाई होती है। जापानी बुखार को पहली बार जापान में 1871 में खोजा गया था। इसलिए इसका नाम जापानी बुखार पड़ा। डब्ल्यूएचओ एईएस अर्थात चमकी बुखार के लिए जिस वायरस को कारक मानता है, उनमें हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, निपाह वायरस, जीका वायरस, चंडीपुरा वायरस के अलावा खसरा, डेंगू के वायरस भी शामिल हैं। साफ है बीमारी को अनुभवी डॉक्टर ही पकड़ सकते हैं।

2014 जब डॉ. हर्षवर्धन पहली बार केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तब भी मुजफ्फरपुर में चमकी का प्रकोप महामारी के रूप में फैला था। तब वे इसी अस्पताल में पहुंचे थे और वायरोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा की थी। इस बार रोगियों को देखने के लिए डॉ. हर्षवर्धन फिर इसी अस्पताल में पहुंचे। अब वे प्रयोगशाला के साथ शोध संस्थान खोलने की भी घोषणा कर आए हैं, देखें इस पर अमल कब तक हो पाता है? ये शोध संस्थान खुलने के बाद परिणाम सार्थक ही देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल हाल ही में चिकित्सकों की बेहद अहम संस्था एसोसिएशन ऑफ डिप्लोमैट नेशनल बोर्ड ने खुलासा किया है कि देश में कुल 576 चिकित्सा संस्थानों में से 332 ने एक भी शोध-पत्र प्रकाशित नहीं किया है, जबकि नए अनुसंधान एवं अध्ययन नवाचार के आधार होते हैं। गोया आधे से ज्यादा चिकित्सा महाविद्यालयों में यदि अनुसंधान हो ही नहीं रहे हैं तो नई बीमारियों के लक्षण और उनके शरीर में पैदा होने के कारणों का कैसे पता चलेगा? बहरहाल चिकित्सा क्षेत्र के पूरे ढांचे को सुधारने की जरूरत है, केवल नई संस्थाएं खोलने और संसाधन देने भर से इस क्षेत्र में सुधार होने वाला नहीं है?

खरी-खरी

आधुनिक यक्ष का संदेश

डॉ. पिलकेंद्र अरोरा

मेघ! इस बार तुम जिस दिशा से चाहो, उस दिशा से राज्य में प्रवेश करना! कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, रात्रि में कतई प्रवेश न करना! वहां अब रात्रि में अंधकार ही अंधकार रहता है। पर तुम डरना मत। कुछ ही देर में राज्य विद्युत से पुनः प्रकाशित हो जाएगा। अंधकार और प्रकाश के बीच की इस स्थिति को भोले मानुष 'कटौती' कहकर धिक्कारते हैं। अंधकार में तुम्हें वहां मोमबत्ती की रोशनियां दिखाई पड़ेंगी, पर तुम भूल से यह मत समझ लेना कि राज्य वापस आदिम युग में लौट गया है! ये रोशनी कैंडल मार्च की है। अब वहां मासूमों के साथ हुई बर्बर घटना के बाद कैंडल मार्च निकालने की एक रस्म होती है। मासूमों को नमन कर तुम आगे बढ़ जाना। दिन में यदि तुम्हें सड़कों पर ढोर चराते नए चेहरे दिखें तो कतई चौंकना मत! ये राज्य की युवा शक्ति है, जो आजकल बैंड-बाजा बजाकर राज्य के नवनिर्माण में अपना मौलिक योगदान देती है। उनका एकमात्र अपराध है, उनका शिक्षित होना!

आगे तुम्हें पेड़ों पर लटके मनुष्य दिखाई देंगे, पर तुम गलती से यह मत समझना कि अब राज्य में मनुष्यों के पेड़ लगने लगे हैं! वे बेचारे तो फंदों पर लटके गरीब किसान हैं, जो कर्जमाफी के छल-छलावों के बाद मजबूर हुए और इस जालिम जमाने से कूच कर गए। तुम उन धरती-पुत्रों को सादर नमन करना। आगे, तुम्हें कई आलीशान बंगलों के पोर्चों में पड़ा घरेलू सामान दिखेगा। आश्चर्य मत करना। यह महंगा विलासी सामान राज्य के उन दरबारियों का है, जिनका बार-बार, इतनी बार तबादला हुआ है कि वे कन्फूजिया गए हैं कि सामान को बंगले में सेट करें या नहीं! क्या पता कल कोई नया ऑर्डर निकल जाए! उन त्रिशंकुओं को प्रणाम कर तुम आगे बढ़ना।

मेघ, इस बार राज्य में कई जनपदों में मनुष्य-समूह श्वेत वस्त्रों में बैठे दिखेंगे। ये न समझना कि ये दृश्य किसी शोकसभा या उठावने के हैं। दरअसल ये मार्मिक दृश्य समीक्षा एवं चिंतन बैठकों के हैं। पिछले दिनों कुछ गणों पर ऐसा भारी वज्रपात हुआ कि उनके कमल-मुख मुरझा गए और वे स्वयं को अनाथ समझने लगे हैं। वे यह मानने को तैयार नहीं कि 'जो हुआ सो हुआ'! तुम उन पीड़ित आत्माओं की शांति के लिए महाकाल नगरी जाकर बाबा से प्रार्थना करना और मेरा ये गुप्त संदेश अलकापुरी में विरहाग्नि में जल रही मेरी प्रियतमा को देना। हे यक्ष! मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा।

ट्वीट-ट्वीट

महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाला देश इतनी लचर स्वास्थ्य सेवाएं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्रियों से जवाब तलब करना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए वे पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं करते?

तवलीन सिंह@tavleen_singh

वर्ष 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। हे राम! तब लोग क्या कबूतरखानों में रहेंगे। खाने और पानी की भारी किल्लत होगी। ट्रैफिक जाम। प्रदूषण और तमाम आफतें। फिर भी किसी को जनसंख्या नियंत्रण की परवाह नहीं।

प्रकाश सिंह@singh_prakash

विश्व कप से शिखर धवन का बाहर होना दिल तोड़ने वाला है। वह कमाल का खेल दिखा रहे थे। अब रिषभ पंत टीम में हैं जिनके बारे में तमाम लोग मानते रहे कि उन्हें पहले से ही इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था।

अयाज मेमन@cricketwallah

जम्मू-कश्मीर डायरी

चुनौतियों से भरी अमरनाथ यात्रा

अभिमन्यु शर्मा
संपादक, जम्मू-कश्मीर

बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा यात्रा शुरू होने में अब मात्र नौ दिन ही शेष हैं। राज्यपाल प्रशासन का पूरा प्रयास है कि यात्रा में अधिक से अधिक लोग भाग लें। इसके लिए प्रशासन इन दिनों सुरक्षा से लेकर हर प्रकार के प्रबंध कर रहा है, परंतु कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में बढ़ी आतंकी घटनाओं ने राज्यपाल प्रशासन की चुनौती को बढ़ा दिया है। पिछले एक सप्ताह में ही सेना एवं सुरक्षाबलों के एक मेजर, एक इंस्पेक्टर समेत कुल दस जवान शहीद हो गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के केपी रोड पर हुए आतंकी हमले में केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल के पांच जवान और एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। सुरक्षाबलों ने भी अल उमर मुजाहिदीन संगठन के एक आतंकी को ढेर किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के अच्छाबल में सेना का मेजर शहीद हो गया। इसी जिले के बिजबेहाड़ा में हुए आतंकी हमले में भी एक जवान शहीद हुआ। एक अन्य घटना में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आईईडी धमाके में भी सेना के दो जवान शहीद हो गए। यह सही है कि इन हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को भी सुरक्षाबलों ने मार गिराया, लेकिन जिस तरह से दक्षिण कश्मीर के इन जिलों में आतंकवादियों ने बाबा अमरनाथ की यात्रा से ठीक पहले अपनी गतिविधियों को तेज किया है, उसका असर कहीं न कहीं यात्रा पर भी पड़ने की आशंका बनी रहती है। यह वही क्षेत्र है जहां से अमरनाथ यात्रा भी होकर गुजरती है। आतंकवादियों का पूरा प्रयास रहता है कि अमरनाथ यात्रा में खलल डाला जाए। केंद्र सरकार एवं राज्यपाल प्रशासन को भी स्थिति की गंभीरता का अनुमान है। यही कारण है कि देश के गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूरी जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह के लिए यह यात्रा इस साल की पहली बड़ी चुनौती होगी। वहीं केंद्र में अतिरिक्त सचिव गृह ज्ञानेश कुमार दो बार राज्य में आकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर चुके हैं। राज्यपाल स्वयं भी कई बार बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कुछ दिन पूर्व वह यात्रा के प्रबंधों का हवाई सर्वेक्षण भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार एवं राज्यपाल प्रशासन यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी ढील नहीं रखना चाहते हैं। यात्रा के आधार शिविर यात्री निवास जम्मू से लेकर बाबा बर्फानी के भवन तक सेना, सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती की जा रही है। आधार शिविर यात्री निवास में अभी से ही सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। चालीस हजार से अधिक जवानों के कंधों पर यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिला रहे हैं कि उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। राज्य के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर भवन तक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बेखौफ होकर यात्रा में भाग लेने के लिए आएं। अब देखना यह है कि एक जुलाई से शुरू हो रही इस यात्रा में इस बार देश के विभिन्न भागों से कितनी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए आते हैं। अभी तक सवा लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा में भाग लेने के लिए एडवांस पंजीकरण करवा चुके हैं। पंजीकरण अभी भी जारी है। वहीं यात्रा मार्ग पर लंगर लगाने वालों ने भी पहुंचना शुरू कर दिया है।

पूर्ण रूप में दर्शन देंगे बाबा बर्फानी : बाबा बर्फानी के दर्शनों का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए इस बार अच्छी खबर है। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस साल बड़े आकार में प्रकट हैं। इस साल सर्दियों में कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। यहां तापमान में काफी गिरावट होने के कारण मौसम काफी ज्यादा ठंडा रहता है। इसी कारण न सिर्फ अमरनाथ में शिवलिंग का आकार बढ़ा है, बल्कि उम्मीद है कि इस बार यात्रा के दौरान गुफा में शिवलिंग अंत तक मौजूद रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से यात्रा संपन्न होने से पहले ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पिछले साल मौसम खराब होने के कारण यात्रा काफी बाधित रही थी। इसके बाद कुछ दिनों में ही बाबा बर्फानी भी अंतर्ध्यान हो गए थे।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप बढ़ने में प्रशासन का लचर रवैया जिम्मेदार है?

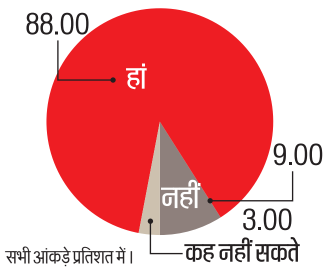

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर करने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

करना कहां विरोध है और कहां दें साथ,
समझेंगे जब ये फरक तब उभरेगा 'हाथ',
तब उभरेगा 'हाथ' कौन इनको समझाए,
नासमझों के साथ खोपड़ी कौन खपाए!
हो यदि एक चुनाव भला इससे क्या डरना,
पर कुछ लोग विरोध कर रहे जिनको करना।

– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका

ओम बिरला को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य उत्तरदायित्व सदन का कार्य शांति एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना होता है

राहुल लाल
स्वतंत्र टिप्पणीकार

लोकसभा अध्यक्ष का पद संसदीय शासन प्रणाली में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में जहां पर भी संसदीय पद्धति की सरकार है, वहां संसद के निम्न सदन के स्पीकर को विशेष महत्व और दर्जा प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्य यथाशीघ्र अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। इस संदर्भ में बुधवार को लोकसभा में राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका निर्विरोध चुना जाना मूलतः भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत ही करेगा। लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य उत्तरदायित्व सदन का कार्य शांति एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना है।

निम्न सदन के अध्यक्ष का पद ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में विकास के लंबे और गहन संघर्ष के परिणामस्वरूप बना। ब्रिटेन में जब हाउस ऑफ कॉमंस विधि का निर्माण करने वाला निकाय न होकर याचिका प्रस्तुत करने वाला निकाय हुआ करता था तो अध्यक्ष का मुख्य कार्य वाद-विवाद के अंत में दोनों पक्षों के तर्कों का निष्कर्ष निकालना और सदन के विचार 'क्राउन' के समक्ष प्रस्तुत करना हुआ करता था। इस प्रकार वह सम्राट के समक्ष हाउस ऑफ कॉमंस का प्रवक्ता या स्पीकर हुआ करता था। यही कारण है कि आज भी इस पद को स्पीकर कहा जाता है। जैसे-जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमंस की शक्तियों में वृद्धि हुई, स्पीकर के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हुई। वहां स्पीकर की निष्पक्षता तथा सम्मान पर विशेष बल दिया गया। यही कारण है कि जब ब्रिटेन में कोई स्पीकर बन जाता है तो वह पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे देता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में एक शानदार परंपरा के द्वारा स्पीकर को काफी सम्मान भी प्रदान किया जाता है। अगले चुनावों में स्पीकर भी तटस्थ रूप में निर्दलीय ही आम चुनाव लड़ते हैं, उनके समक्ष कोई भी दल सम्मान में उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है अर्थात स्पीकर आम चुनाव भी निर्विरोध जीतते हैं।

स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकसभा अध्यक्ष के पद के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। यह उद्देश्य कई प्रकार से सुनिश्चित होता है। इस क्रम में उनका स्थान वरीयता सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद आता है। उनका स्थान, सिवाय प्रधानमंत्री के, मंत्रिमंडल के अन्य सब मंत्रियों से ऊंचा है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन-भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित है। अर्थात उसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। उनके आचरण पर सिवाय मूल प्रस्ताव के चर्चा संभव नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देते हैं, किंतु बराबर मत होने की दशा में उनका निर्णायक मत होता है। पहली बार मत न देने के कारण उनकी निष्पक्ष स्थिति होती है। स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार इसलिए प्रदान किया गया है, जिससे वह गतिरोध को समाप्त कर सके। स्पष्ट है कि समान मत होने की स्थिति में स्पीकर अपना निर्णायक मत देते हैं तो ऐसा सदा सुस्थापित संसदीय सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार किया जाता है।

उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत के बाद ओम बिरला राजस्थान के दूसरे ऐसे नेता हैं, जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। ओम बिरला के व्यक्तित्व की बात करें तो वह इतने सहज और सरल हैं कि सबके लिए उनके दरवाजे खुले हैं।

लोकसभा में जिस प्रकार विपक्ष की शक्ति घटी है, ऐसे में ओम बिरला के जिम्मेदारी में और भी वृद्धि हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि विपक्ष भले ही संख्या में कम है, परंतु उनकी एक-एक आवाज हमारे लिए बहुमूल्य है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र की मूल आत्मा पर प्रकाश डाल रहे थे। संसदीय लोकतंत्र में सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष की महत्ता भी स्वयंसिद्ध है। इस तरह अब इस कमजोर विपक्ष की भी सकारात्मक मजबूत प्रतिध्वनि लोकतंत्र में सुनाई दे, इसकी जिम्मेदारी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर ही है।

लोकसभा अध्यक्ष के पास लोकसभा के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रक्रिया और नियमों का निर्वहन करने की अंतिम शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या सदन में व्यवस्था बनाए रखने में लोकसभा अध्यक्ष का आचरण न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। इसके साथ ही कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस पर भी अंतिम निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। सदन के भीतर संसदीय मामलों में भी लोकसभा अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम होता है। जिन मामलों के बारे में नियमों में विशेष रूप से उपबंध न किया गया हो, उनके संबंध में निर्देश देने की शक्तियां अध्यक्ष को प्राप्त हैं। इस बात का निर्णय भी स्पीकर ही करते हैं कि क्या विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना से संबंधित किसी विषय में प्रथम दृष्टतया मामला बनता है या किसी सदस्य के आचरण का मामला जांच-पड़ताल के लिए किसी समिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

लोकसभा की सब संसदीय समितियां स्पीकर के द्वारा ही गठित की जाती हैं। वे उन्हीं के नियंत्रण और निदेशाधीन कार्य करती हैं। लोकसभा से संबद्ध सभी समितियों के सभापति उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कार्यमंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति सीधे उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती हैं।

स्पष्ट है कि संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में स्पीकर की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की है। इसका कारण यह है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष न तो अपना संबंध राजनीतिक दलों से ब्रिटेन की तरह तोड़ लेता है और न ही पद ग्रहण के बाद अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव के अध्यक्ष की तरह अपने दल के लिए पक्षपात करता है। स्वतंत्र भारत में विभिन्न लोकसभा अध्यक्षों ने अपने नवीन परंपराओं से इस पद को और भी महत्वपूर्ण बनाया है। उम्मीद है कि ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष के आगामी काल में लोकसभा की कार्यवाहियों में गतिशीलता एवं सजीवता देखने को मिलेगी।

मांग बढ़ने से सोना, चांदी में उछाल

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोना मामूली 20 रुपये उछलकर 33,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक चांदी भी 130 रुपये उछलकर 38,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सराफा कारोबारियों ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के द्वारा खरीदारी बढ़ाए जाने से चांदी की कीमत बढ़ी है। न्यूयॉर्क में सोने में 1,343 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 15.01 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। (प्रेट्र)

विदेशी कंपनियों को बी-टु-बी के बहाने भी मल्टी ब्रांड रिटेल में कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कंपनियां लुभावनी कीमत रखकर कारोबार करती हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
—पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री

सेंसेक्स	39,112.74	66.40	निफ्टी	11,691.45	0.05	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 33,740	₹20	चांदी प्रति किलोग्राम	₹38,350	₹130
$ डॉलर	₹69.68	₹69.68	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 61.38							

भारत के ऊर्जा बाजार को लेकर अमेरिका व रूस में होड़

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- रूस ने अपने सुदूर पूर्वी क्षेत्र के तेल व गैस क्षेत्र के लिए भारत को किया आमंत्रित
- ईरान प्रतिबंध के बाद भारत को ज्यादा से ज्यादा क्रूड बेचने की अमेरिका की तैयारी

प्रतीकात्मक

अमेरिका और रूस के बीच भारत को सिर्फ हथियार बेचने की ही होड़ नहीं है बल्कि इन दोनो देशों के बीच भारत को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा स्रोतों को बेचने को लेकर भी प्रतिस्पर्द्धा चल रही है। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए अमेरिका जहां अपने क्रूड और शेल गैस के लिए यहां बड़ा बाजार देख रहा है, वहीं रूस अपने पूर्वी हिस्से के तेल व गैस क्षेत्र में भारत को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की पेशकश कर रहा है। बुधवार को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी पी त्रुतनेव की मुलाकात में रूस के पूर्वी हिस्से में तेल व गैस फील्ड्स में सहयोग को लेकर काफी विस्तार से बात हुई है। जबकि इस महीने के अंत तक भारत आने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोंपियो के साथ ऊर्जा सहयोग पर बातचीत काफी अहम रहेगी।

ईरान पर प्रतिबंध लागू होने के बाद भारतीय तेल कंपनियों ने अमेरिका से ज्यादा क्रूड खरीदने की शुरुआत कर भी दी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी आइओसी ने इस साल अमेरिकी कंपनियों से 46 लाख टन क्रूड की खरीदने का समझौता कर लिया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका से और ज्यादा क्रूड खरीदा जा सकता है। अमेरिका लगातार भारत को अपने एनर्जी बाजार को उदार बनाने का दबाव बना रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के शेल बाजार में 4 अरब डॉलर का निवेश किया है और अब अमेरिका चाहता है कि उस गैस का निर्यात भारत को ही किया जाए। दोनों देश इसके लिए लंबी रणनीति पर काम कर रहे हैं। पोंपियो की आगामी नई दिल्ली यात्रा के दौरान ऊर्जा सहयोग एक बड़ा मुद्दा रहेगा।

रूस अमेरिका से पुराना भारत का ऊर्जा सहयोगी देश है और वह इस बात को बखूबी समझ रहा है कि किस तरह से अमेरिका व भारत के बीच सहयोग बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों बिश्केक (किर्गिस्तान) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने ऊर्जा सहयोग का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया। उन्होंने भारतीय कंपनियों को अपने सुदूर पूर्वी क्षेत्र में स्थित तेल व गैस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। रूस की तेजी इस बात से समझी जा सकती है कि उस बैठक के कुछ ही दिनों बाद 19 जून, 2019 को उन्होंने उप प्रधानमंत्री (सुदूर पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिनिधि) को भारत भेजा। उप पीएम त्रुतनेव की बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, पेट्रोलियम मंत्री प्रधान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से मुलाकात हुई। बैठक में रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र से भारत तक ऊर्जा उत्पादों को किस तरह से लाया जाए, इस पर खास तौर पर चर्चा हुई है। सनद रहे कि भारत व रूस के बीच इस बारे में गैस पाइपलाइन बिछाने के विकल्प पर भी पहले से बातचीत चल रही है। पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने संकेत दिया है कि अब समुद्री मार्ग से भी इन उत्पादों को रूस से भारत के पूर्वी तट तक लाया जा सकता है।

अमेरिका व रूस में यह होड़ इसलिए है कि भारत अपनी जरूरत का 83 फीसद क्रूड व गैस आयात से पूरी करता है। आने वाले दिनों में यह और बढ़ने की उम्मीद है। वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में एक लाख करोड़ डॉलर का निवेश होगा। वर्ष 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी बाजार बनने की क्षमता रखता है।

'एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल' पर लग सकता है जीएसटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

जीएसटी काउंसिल शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल' (ईएनए) को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 21 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। काउंसिल में अगर इस प्रस्ताव पर आम राय बनी तो ईएनए पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जा सकता है।

सूत्रों का कहना है कि ईएनए का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए होता है। फिलहाल 'मानव उपभोग के लिए अल्कोहल' (शराब) जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन औद्योगिक अल्कोहल पर जीएसटी लगता है। हालांकि ईएनए के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि इस पर कई राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। ईएनए का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए तथा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में होता है। इसलिए केंद्र की दलील है कि ईएनए पर जीएसटी लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने इस मुद्दे पर कानूनी राय ली है और विशेषज्ञों का कहना है कि ईएनए शराब नहीं हैं, इसलिए इस पर जीएसटी लगाया जा सकता है। 'मानव उपभोग के लिए अल्कोहल' जीएसटी के दायरे से बाहर है और संविधान संशोधन में इसका स्पष्ट उल्लेख है। शराब पर राज्य सरकारें वैट और आबकारी शुल्क वसूल रहे हैं और खासा राजस्व उन्हें इससे मिल रहा है। इसलिए कई राज्यों को ईएनए पर जीएसटी लगाने को लेकर ऐतराज भी है।

राज्यों की चिंता यह है कि अगर ईएनए पर जीएसटी लग जाता है तो यह शराब को भी जीएसटी के दायरे में लाने का आधार बन सकता है। हालांकि शराब पर जीएसटी लगाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता भी पड़ेगी। बहरहाल इतना तय है कि ईएनए पर अगर जीएसटी लगता है तो यह शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में एक कदम होगा।

पीएम-ईएसी ने सुब्रमण्यम के दावे को खारिज किया

- कहा, सुब्रमण्यम ने सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को किया पूरी तरह नजरंदाज
- सरकारी एजेंसियों के बजाय निजी एजेंसियों के आंकड़ों पर किया भरोसा

प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने 2011-12 के बाद देश के जीडीपी को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाने की बात कही थी। परिषद का कहना है कि सुब्रमण्यम ने जीडीपी का अनुमान लगाते वक्त सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया और सरकारी संस्थान सीएसओ के बजाय एक निजी एजेंसी सीएमआइई पर भरोसा किया।

परिषद ने एक पेपर जारी कर कहा कि भारत की जीडीपी गणना की विधि एक जिम्मेदार प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के नाते वैश्विक मानकों के अनुरूप है। यह पेपर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय और सदस्य राथिन राय, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, चरण सिंह और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने लिखा है। परिषद ने पिछले हफ्ते ही एक बयान जारी कर कहा था कि आने वाले दिनों में सुब्रमण्यम के दावे का वह बिंदुवार जवाब देगी। उल्लेखनीय है कि सुब्रमण्यम ने अपने शोधपत्र में दावा किया था कि जीडीपी की गणना की विधि बदलने के बाद 2011-12 से 2016-17 तक देश की विकास दर को वास्तविकता से ढाई फीसद अधिक दिखाया गया। सुब्रमण्यम अक्टूबर 2014 से लेकर चार साल तक वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपने पेपर में कहा है कि सुब्रमण्यम ने भारत की जटिल अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। उन्होंने 17 हाई फ्रीक्वेंसी इंडीकेटर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन जीडीपी में 60 फीसद योगदान करने वाले सेवा क्षेत्र और 18 फीसद योगदान करने वाले कृषि क्षेत्र को पूरी तरह टाल दिया। इतना ही नहीं उन्होंने 17 हाई फ्रीक्वेंसी इंडीकेटर्स के आंकड़े निजी एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी से लिए जो खुद आंकड़े संग्रहित करने के बजाय अन्य स्रोतों से सूचना जुटाती है। अगर कोई व्यक्ति सुब्रमण्यम के पेपर को पढ़ेगा तो उसे स्पष्ट पता चल जाएगा कि उन्होंने सरकारी संस्था सीएसओ (सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस) पर अविश्वास किया, जबकि निजी एजेंसी सीएमआइई पर भरोसा जताया। ऐसी स्थिति में भारत को इतने लंबे समय तक सेवा देने वाले सरकारी संस्थान पर भरोसा न करना निष्पक्ष शिक्षाविद को शोभा नहीं देता है।

परिषद का कहना है कि सुब्रमण्यम ने अपने पेपर में टैक्स के आंकड़ों को भी पूरी तरह नजरंदाज कर दिया। सुब्रमण्यम ने यह कहकर टैक्स के आंकड़ों का इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया कि वर्ष 2011 के बाद डाइरेक्ट व इनडाइरेक्ट टैक्स में व्यापक बदलाव आए हैं, जिससे टैक्स जीडीपी संबंध बदल गया है। इससे जीडीपी की गणना करने के लिए यह इंडीकेटर उपयुक्त नहीं है। वास्तविकता यह है कि टैक्स के आंकड़े किसी सर्वे के जरिये नहीं बल्कि सरकारी तंत्र के जरिये जुटाए जाते हैं। ऐसे में यह विकास दर को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण इंडीकेटर हो सकते हैं। जहां तक टैक्स कानूनों में बदलाव की बात है तो एक जुलाई 2017 से पहले कोई बदलाव हुआ ही नहीं है।

मिनी एसयूवी ट्राइबर के जरिए बिक्री दोगुनी करेगी रेनों

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कंपनी ने एसयूवी 'ट्राइबर' की भारत में की ग्लोबल लांचिंग
- अगले महीने से बिक्री होगी शुरू, बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली में बुधवार को रेनों ने अपनी नई मिनी एसयूवी (चार मीटर से कम श्रेणी) ट्राइबर लांच की। इसकी बिक्री अगले महीने से शुरु होगी। प्रेट्र

देश के कार बाजार में भले ही मंदी छाई हुई है, लेकिन ग्लोबल कार कंपनियों की निगाहों में अभी इस बाजार की चमक कम नहीं हुई है। भारतीय बाजार में पिछले एक दशक से पैठ बनाने की कोशिश में जुटी रेनों ने एक बार फिर बड़ा दांव लगाया है। बुधवार को रेनों ने अपनी नई मिनी एसयूवी (चार मीटर से कम श्रेणी) ट्राइबर की ग्लोबल लांचिंग भारत में की है। पिछले महीने हुंडई की वेन्यू के बाद यह घरेलू बाजार में लांच की जाने वाली दूसरी एसयूवी है। इसकी बिक्री अगले महीने से शुरु होगी। कंपनी ने वर्ष 2022 तक अपनी बिक्री को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्राइबर की सफलता बेहद जरूरी होगी।

ट्राइबर को मीडिया के सामने पेश करते हुए रेनों समूह के सीईओ थिएरी बोल्लोरे ने कहा कि भारत अभी भी हमारी कंपनी के लिए एक नया बाजार है, क्योंकि वर्ष 2008 से ही हम यहां हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को अब समझने लगे हैं। वर्ष 2022 तक हम बिक्री को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ट्राइबर इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। पहली बार हम इस मॉडल को भारतीय बाजार में लांच कर रहे हैं, यहां से बड़े पैमाने पर निर्यात भी करने की योजना है। रेनों को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे जरूरत के मुताबिक पांच सवारियां या सात सवारियां इस्तेमाल कर सकती हैं। कंपनी अभी भारत में सालाना एक लाख वाहनों की बिक्री कर रही है, दोगुना करने के लिए इसे एक लाख कारों की बिक्री और करनी होगी।

ट्राइबर में 1.0 लीटर के तीन सिलेंडर वाले इंजन हैं, जिसे भारतीय बाजार के लिए तैयार किया गया है। इसकी एक खासियत यह है कि घुमावदार सड़कों पर भी यह समान पावर देती है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस और कार के अंदर ज्यादा जगह देने के लिए डिजाइन पर खास ध्यान दिया गया है। सनद रहे कि रेनों अभी तक भारत में आठ मॉडल लांच कर चुकी है, लेकिन डस्टर और क्विड को छोड़ कर अन्य दूसरे मॉडल बाजार पर कोई खास असर नहीं छोड़ सके हैं। इन दोनों की बिक्री पर भी पिछले एक वर्ष के दौरान कार बाजार की मंदी का असर दिख रहा है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी तीन फीसद के आस पास है। वैसे रेनों के आला अधिकारियों का मानना है कि भारतीय कार बाजार में मंदी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है।

जेट की बैंक्रप्सी प्रक्रिया में पायलट्स, इंजीनियर्स भी बनना चाहते पक्षकार

मांग
- नीदरलैंड की दो लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी जेट के विरुद्ध एनसीएलटी पहुंची
- एनसीएलटी गुरुवार से शुरू करेगा जेट एयरवेज के विरुद्ध बैंक्रप्सी मामले की सुनवाई

मुंबई, प्रेट्र : संकटग्रस्त विमानन कंपनी जेट एयरवेज के पायलट्स और इंजीनियरों के संघों और नीदरलैंड की दो लॉजिस्टिक्स आपूर्तिकताओं ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से मांग की कि बैंक्रप्सी सुनवाई में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। एनसीएलटी जेट एयरवेज के बैंक्रप्सी मामले की सुनवाई गुरुवार से शुरू करेगा। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले 26 बैंकों के कंसोर्टियम ने मंगलवार को एनसीएलटी की मुंबई पीठ के सामने विमानन कंपनी पर बैंक्रप्सी प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी। बैंकों का कंपनी पर 8,500 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।

17 अप्रैल को विमानों का परिचालन औपचारिक रूप से बंद कर चुकी कंपनी के पायलट्स और इंजीनियर्स के संघों ने बैंक्रप्सी मामले में उन्हें पक्ष बनाए जाने की मांग की है। वहीं, नीदरलैंड की दो लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने इंटरवेंसन याचिका दाखिल करने के लिए ट्रिब्यूनल की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि जेट एयरवेज की दो आपूर्तिकर्ता कंपनियों ने नीदरलैंड में मार्च के अंत में जेट एयरवेज के एक यात्री विमान को जब्त कर लिया था। दोनों आपूर्तिकर्ताओं के नाम फिलहाल सामने नहीं आए हैं।

वीपी सिंह और रविकुमार दुरईसामी की पीठ ने इन याचिकाओं की सुनवाई भी गुरुवार को ही निश्चित कर दी। इस बीच गुरुवार को ट्रिब्यूनल जेट एयरवेज के दो परिचालन कर्जदाताओं की याचिकाओं की भी सुनवाई करेगा। इन दोनों परिचालन कर्जदाताओं में शमन व्हील्स और गग्गर एंटरप्राइजेज शामिल हैं। शमन व्हील्स ने विमानन कंपनी पर 8.74 करोड़ रुपये और गग्गर एंटरप्राइजेज ने 53 लाख रुपये का दावा किया है। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले 10 जून को विमानन कंपनी के विरुद्ध बैंक्रप्सी याचिका दाखिल की थी।

मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं मिलेगी विदेशी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सरकार ने दूर की व्यापारियों की चिंता, वाणिज्य मंत्री ने दिया आश्वासन

प्रतीकात्मक

व्यापारियों की आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने साफ कहा है कि मल्टी-ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जो कंपनियां लुभावनी कीमतें (प्रीडेटरी प्राइसिंग) रखकर कारोबार करती हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री मंत्री पीयूष गोयल ने किराना स्टोर और खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में यह बात कही। गोयल ने बैठक में शामिल सभी कारोबारियों से पांच दिन के भीतर ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर सुझाव भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआइआइटी के पास आने वाले सुझावों को संज्ञान में लेने के बाद ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों को उनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस और मुद्रा योजना का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि बीटूबी के बहाने भी मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई कंपनी लुभावनी कीमतें रखकर कारोबार करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआइटी) ने एक बयान जारी कर कहा है कि देश में ई-कॉमर्स कारोबार को नए सिरे से खड़ा करने और ई-कॉमर्स नीति को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। सरकार ने एक मजबूत कदम उठाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है और नीति को उसके सही अर्थों में लागू करने पर सरकार पहल कर रही है। हालांकि नीति के अनुपालन की निगरानी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि किसी भी नियामक तंत्र की अनुपस्थिति में सरकार को देश में काम करने वाले ई-कॉमर्स पोर्टल्स की वास्तविक संख्या के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी प्राधिकरण के साथ उनका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। संगठन ने मांग की कि ई-बाजार के रूप में काम करने वाले वाणिज्य पोर्टलों का भारत में अनिवार्य रूप से एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही ई-कॉमर्स के मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

सुस्ती

सेंसेक्स 66 .40 अंकों की तेजी के साथ 39,112 .74 पर बंद, निफ्टी 0 .05 अंक की गिरावट के साथ 11,691 .45 पर स्थिर

फेडरल रिजर्व का फैसला आने से पहले बाजार में मंद कारोबार

मुंबई, प्रेट्र : अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर पर फैसला आने से पहले निवेशकों ने बाजार में प्रवेश करने से परहेज किया। मंद कारोबार के बीच बीएसई का सेंसेक्स 66.40 अंकों की तेजी के साथ 39,112.74 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 0.05 अंक की गिरावट के साथ 11,691.45 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में टाटा स्टील में सर्वाधिक 4.60 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर यस बैंक में सर्वाधिक 5.54 फीसद गिरावट रही। सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के रियल्टी सेक्टर में सर्वाधिक 1.20 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर हेल्थकेयर में सर्वाधिक 1.29 फीसद गिरावट रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.69 फीसद और स्मॉलकैप में 1.37 फीसद गिरावट रही।

बीएसई पर संकटग्रस्त विमानन कंपनी जेट एयरवेज 18.17 फीसद लुढ़का। जैन इरिगेशन में 28.10 फीसद, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में 15.36 फीसद, रिलायंस कैपिटल में 14.95 फीसद, रिलायंस होम फाइनेंस में 9.62 फीसद, वक्रांगी में 13.59 फीसद, जयप्रकाश एसोसिएट्स में 9.80 फीसद, लक्ष्मी विलास बैंक में 9.36 फीसद और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 8.91 फीसद गिरावट रही।

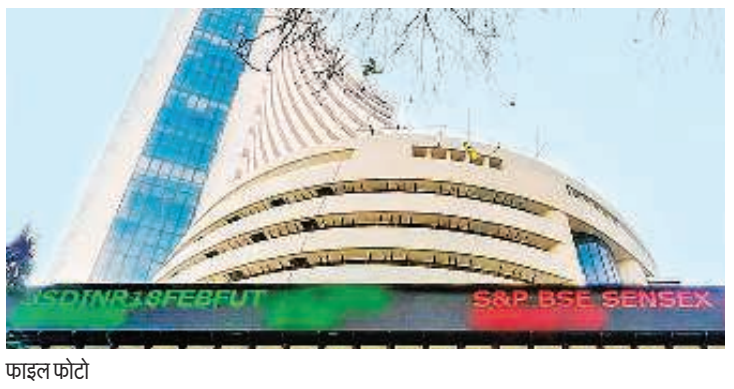

फाइल फोटो

बीएसई पर आइआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर में 9.95 फीसद गिरावट रही। एनएचएआइ से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के लिए कंपनी को मिले ठेके की अवधि अगस्त में खत्म हो रही है। बाजार में चर्चा है कि एनएचएआइ इसके बाद इस परियोजना के लिए नए ऑपरेटर की तलाश में है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 7.26 फीसद गिरावट रही। ट्रेंट 4.81 फीसद उछला। कंपनी ने कहा है कि कारोबारी विस्तार के लिए वह चालू वित्त वर्ष में 1,550 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में एवीपी इक्विटी रिसर्च के फंडामेंटल रिसर्च (इन्वेस्टमेंट सर्विसेज) के प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा निकट अवधि में ब्याज दर घटाए जाने की उम्मीद और अगले सप्ताह अमेरिका-चीन वार्ता की चर्चा से शुरुआती कारोबार में बाजार में अच्छी-खासी तेजी देखी गई। लेकिन सरकारी बैंकों, वाहन, फार्मा और आइटी शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ बंद हुआ।

एशिया के अन्य बाजारों में हैंगसेंग में 2.56 फीसद, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.96 फीसद, निक्केई में 1.72 फीसद और कोस्पी में 1.24 फीसद तेजी रही। यूरापीय बाजारों के शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुझान देखा गया।

इंडियामार्ट लाएगी आइपीओ

नई दिल्ली : कारोबारी उत्पाद और सेवाओं की ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी इंडियामार्ट इंटरमेश अपने शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट करने के लिए सोमवार को अपना प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) पेश करेगी। इश्यू बुधवार को बंद होगा। कंपनी ने 970-973 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है। इस निर्गम के तहत 48,87,862 तक शेयर बेचे जाएंगे। ऑफर के तहत कंपनी करीब 475 करोड़ रुपये जुटा सकती है।

एचडीएफसी ने अपोलो म्यूनिख हेल्थ का किया अधिग्रहण

मुंबई, प्रेट्र : गिरवी पर कर्ज देने वाली कंपनी एचडीएफसी ने बुधवार को कहा कि उसने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है। खरीदी गई कंपनी का विलय वह अपनी सहायक इकाई एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस में करेगी। एचडीएफसी ने यह अधिग्रहण अपोलो हॉस्पीटल्स समूह से 1,347 करोड़ रुपये में किया है।

प्रतीकात्मक

एचडीएफसी 1,336 करोड़ रुपये में अपोलो हॉस्पीटल्स समूह से 50.8 फीसद हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा 10.84 करोड़ रुपये में वह कर्मचारियों से 0.4 फीसद हिस्सेदारी खरीदेगी। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि जर्मनी की इंश्योरेंस कंपनी म्यूनिख हेल्थ संयुक्त उपक्रम को समाप्त करने के लिए अपोलो हॉस्पीटल्स एंटरप्राइज और अपोलो एनर्जी को 294 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। पारेख ने कहा कि विलय के बाद बनने वाली कंपनी की बाजार हिस्सेदारी गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 6.4 फीसद की होगी। नई कंपनी के पास 308 शाखाएं होंगी और उसके पास 10,807 करोड़ रुपये का कारोबार होगा। एचडीएफसी एर्गो और अपोलो म्यूनिख की विशेषज्ञताओं के विलय से बेहतर उत्पाद इनोवेशन सामने आएगा। उत्पादों का वितरण बढ़ेगा और सर्विसिंग की क्षमता बेहतर होगी। सौदा अगले महीने पूरी हो जाने की उम्मीद है और विलय के बाद सभी कर्मचारियों को बरकरार रखा जाएगा। अधिग्रहण के लिए हालांकि नेशनल हाउसिंग बैंक, इरडा व भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से रेग्युलेटरी मंजूरी लेने की जरूरत होगी। अपोलो म्यूनिख और एचडीएफसी एर्गो का विलय करने के लिए भी शेयरधारकों, एनसीएलटी और इरडा से मंजूरी लेने की जरूरत होगी।

12 लोगों की मौत हो गई चीन के शिचुआन प्रांत में भूकंप से। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता छह मापी गई। इससे सबसे ज्यादा नुकसान चांगनिंग काउंटी के यिबिन शहर में हुआ है। भूकंप का केंद्र धरती के 16 किलोमीटर अंदर था।

फ्लोरिडा में रैली कर ट्रंप ने शुरू किया चुनावी अभियान

राष्ट्रपति चुनाव ▸ अमेरिका को महान बनाए रखने का दिया नारा, विपक्ष और मीडिया पर बोला हमला

न्यूयॉर्क टाइम्स से

सरकार की थपथपाई पीठ, नए एजेंडे या नीति का नहीं किया कोई जिक्र

ऑरलैंडो : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में बड़ी रैली कर 2020 में होने वाले चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। ऑरलैंडो शहर में इस रैली में जुटी हजारों की भीड़ के सामने 73 वर्षीय ट्रंप ने कीप अमेरिका ग्रेट यानी अमेरिका को महान बनाए रखने का नारा दिया। रैली में अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने मीडिया और विपक्ष को फिर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अगले साल का चुनाव उन लोगों का फैसला करेगा जिन्होंने गैर-अमेरिकियों की तरह व्यवहार किया और हमारे महान लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की।

इस रैली में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' लिखी कैप पहने हुए थे। ट्रंप ने इस दौरान अपने प्रशासन की उपलब्धियां गिनाईं। कर कटौती और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने किसी नए एजेंडे या नीति का जिक्र नहीं किया।

विरोधियों पर बरसे : विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाना बनाते हुए ट्रंप ने कहा, 'विपक्षी हमारे देश के मूल्यों से घृणा करते हैं। वह सरकार में आना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को तिरस्कृत मानते हैं।' उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन की खिल्ली उड़ाई। बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हैं।

अपने खिलाफ हुई जांच की आलोचना की : ट्रंप ने रूस से साठगांठ के मामले में अपने खिलाफ हुई जांच की आलोचना भी की। उन्होंने कहा, 'विशेष काउंसलर रॉबर्ट मुलर और उनके साथ मिले डेमोक्रेट जबरदस्ती मुझे फंसाना चाहते थे। लेकिन जांच के बाद उन्हें मुझे दोषमुक्त घोषित करना ही पड़ा।'

फिर उठाया अवैध आप्रवासियों का मुद्दा : 2016 के चुनाव की तरह इस बार भी अवैध आप्रवासी ट्रंप के अभियान का प्रमुख मुद्दा हैं। रैली में ट्रंप ने मेक्सिको से आने वाले अवैध आप्रवासियों को अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या बताया। इस समस्या को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना की। ट्रंप ने कहा, 'विपक्ष मेक्सिको सीमा पर दीवार नहीं बनने दे रहा, यह निंदनीय है।'

फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में रैली के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप। रायटर

घरेलू हिंसा में घिरे शानहान ने छोड़ा पद, मार्क एस्पर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया कार्यवाहक रक्षा मंत्री

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शानहान (56) ने इस्तीफा दे दिया है। अपने खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला सामने आने के बाद शानहान ने यह निर्णय लिया। बतौर रक्षा मंत्री उनकी नियुक्ति पर मुहर के लिए जल्द ही सीनेट में सुनवाई होनी थी। जेम्स मैटिस के अचानक इस्तीफे के बाद गत जनवरी में उन्हें कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया गया था। शानहान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क एस्पर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाए जाने की घोषणा की है। वह सोमवार को कार्यभार संभालेंगे। शानहान ने कहा है कि निजी कारणों से उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। वह नहीं चाहते कि उनके बच्चों के जख्म दोबारा ताजा हो। अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि संघीय जांच एजेंसी एफबीआइ शानहान और उनकी पूर्व पत्नी के बीच घरेलू हिंसा से जुड़े नौ साल पुराने मामले की जांच कर रही है। दोनों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए थे। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि शानहान के नाबालिग बेटे ने 2011 में कथित तौर पर अपनी मां पर बेसबॉल बैट से हमला किया था।

पाक को मिलने वाले कर्ज पर अमेरिका का रुख सख्त

▸ कहा-सशर्त हो आइएमएफ की मदद, दिए जाने हैं छह अरब डॉलर

वाशिंगटन, प्रेट्र : आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से वित्तीय मदद के रूप में मिलने वाले कर्ज पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को सशर्त आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। ट्रंप प्रशासन को आशंका है कि पाकिस्तान इस आर्थिक मदद का उपयोग चीन के कर्ज को चुकाने में कर सकता है।

पाकिस्तान ने पिछले माह छह अरब डॉलर (करीब 42 हजार करोड़ रुपये) के बेलआउट पैकेज के लिए आइएमएफ से करार किया था। पाकिस्तान का कहना है कि इस कर्ज से वह अपना वित्तीय संकट दूर करने और धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों की वरिष्ठ अधिकारी एलिस जी वेल्स ने कहा, 'हमारा मानना है कि पाकिस्तान के लिए आइएमएफ की सशर्त मदद उचित होगी। हमने अपने सख्त रुख के बारे में अवगत करा दिया है।' उन्होंने पिछले हफ्ते विदेश मामलों की एक संसदीय समिति के समक्ष यह जवाब दिया। सांसद ब्रैड शरमन ने आइएमएफ पैकेज को लेकर उनसे सवाल किया था।

डॉ शकील को लेकर बाधा खड़ी करने से इन्कार : वेल्स ने इस बात से इन्कार किया पाकिस्तान की जेल में बंद डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई को लेकर अमेरिका आइएमएफ पैकेज में बाधा खड़ी कर सकता है। शकील पर आरोप है कि उन्होंने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को खोज निकालने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए की मदद की थी। वेल्स ने कहा कि शकील को बंदी बनाया जाना अनुचित है।

95 फीसद कम हुई अमेरिकी मदद: सांसद शरमन ने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद में 95 फीसद की गिरावट आई है।

पाकिस्तान पुलिस की ज्यादती के खिलाफ किया प्रदर्शन

लंदन, एएनआइ : पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में पुलिस ज्यादती के खिलाफ लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने कश्मीरी प्रवासियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान, गुलाम कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर खान और राष्ट्रपति मसूद खान के खिलाफ नारे भी लगाए।

न्यूज गैलरी

श्रीलंका ने लांच किया अपना पहला सेटेलाइट

कोलंबो : श्रीलंका ने स्वदेश निर्मित अपना पहला सेटेलाइट रावन-1 बीते सोमवार को लांच किया। एक किलो वजनी इस सेटेलाइट को जापान की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लांच किया गया। इसे श्रीलंका के दो इंजीनियरों ने तैयार किया था। इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है। (प्रेट्र)

पाक के सबसे वजनी व्यक्ति को सेना ने अस्पताल में कराया भर्ती

लाहौर : पाकिस्तान के सबसे वजनी व्यक्ति को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 55 साल के नूरुल हसन का वजन 330 किलोग्राम है। चलने-फिरने में असमर्थ पंजाब प्रांत के सादिकाबाद जिले में रहने वाले हसन को लाहौर के सेना अस्पताल में हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। (प्रेट्र)

ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में इच्छामृत्यु का कानून लागू

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बुधवार से इच्छामृत्यु का कानून लागू हो गया। लंबे समय से बीमार और असहनीय पीड़ा से गुजर रहे मरीजों के लिए बना इच्छामृत्यु का यह कानून पहली बार ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है। (प्रेट्र)

यूएस में भारतीय बच्ची की संदिग्ध मौत की जांच कराने की मांग

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में एक दक्षिण एशियाई संगठन ने मेक्सिको सीमा के पास भारतीय बच्ची की मौत के मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर नामक इस संगठन ने आरोप लगाया है कि सीमा के सैन्यीकरण और शरणार्थियों को सीमा पार करने से रोकने की वजह से वहां हालात अमानवीय हो गए हैं, जिनकी वजह से ऐसी हृदयविदारक घटनाएं सामने आती हैं।

पिछले हफ्ते एरिजोना प्रांत के ल्यूकविले शहर से 27 किलोमीटर दूर सात साल की गुरप्रीत कौर का शव मिला था। वह अपनी मां और दो अन्य लोगों के साथ पैदल यात्रा कर रही थी। मानव तस्करों ने उन्हें सीमा पर छोड़कर अमेरिका में दाखिल होने को कहा था। रास्ते में गुरप्रीत की मां उसे साथ में चल रही दूसरी महिला के पास छोड़कर पानी की तलाश में गई थी। इसी दौरान प्यास से छटपटाकर गुरप्रीत ने दम तोड़ दिया था। दक्षिण एशियाई संगठन की निदेशक लक्ष्मी श्रीधरन ने कहा, 'गुरप्रीत की मौत बेहद दुखद घटना है।

जब तक शरणार्थियों के लिए कोई नया सिस्टम नहीं बनता तब तक हमें इस तरह कई और मौतें देखनी पड़ सकती हैं।' गुरप्रीत की मौत की जांच और उसकी मां का पता लगाने के लिए संगठन ने सीमा सुरक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है।

ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ से बाहर हुए राब ने की बोरिस जॉनसन की तारीफ

▸ कहा - ब्रेक्जिट की तय रणनीति पर आगे बढ़ने में सिर्फ बोरिस सक्षम

▸ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बीच दूसरे दौर के मतदान में भी जॉनसन सबसे आगे

लंदन, एएफपी : टेरीजा मे के पद छोड़ने के बाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे चल रहे बोरिस जॉनसन को अपने प्रतिद्वंद्वी से तारीफ मिली है। दूसरे दौर के मतदान में बाहर होने के बाद बुधवार को पूर्व मंत्री डोमिनिक राब ने उनकी प्रशंसा की है। राब ने कहा कि बोरिस इकलौते उम्मीदवार हैं जो तय योजना के अनुरूप 31 अक्टूबर को ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग (ब्रेक्जिट) कर सकते हैं।

कंजर्वेटिव पार्टी के छह नेता प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, जिनके बीच मंगलवार को दूसरे दौर का मतदान हुआ। इसमें पार्टी के सभी 313 सांसदों ने हिस्सा लिया। मतदान में बोरिस जॉनसन को सबसे ज्यादा 126 मत मिले। विदेश सचिव जेरेमी हंट को 46 और पर्यावरण मंत्री माइकल गोव को 41 वोट मिले। 37 वोट के साथ अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री रोरी स्टीवर्ट चौथे स्थान पर रहे। गृह मंत्री साजिद जाविद पांचवें स्थान पर आए।

उन्हें 33 मत मिले। 30 मत के साथ डोमिनिक राब दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि दौड़ में बने रहने के लिए कम से 33 सांसदों का समर्थन जरूरी था। मतदान के नतीजे के बाद बचे पांच उम्मीदवारों ने मंगलवार की शाम एक सार्वजनिक बहस में भी हिस्सा लिया, जिसका सीधा प्रसारण करीब 53 लाख लोगों ने देखा। अभी मतदान के और दौर चलेंगे। गुरुवार को अंतिम दो उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद अंतिम फैसले के लिए पार्टी के 1,60,000 जमीनी कार्यकर्ताओं से पोस्टल बैलेट मंगाए जाएंगे। विजेता का फैसला 22 जुलाई तक होने की उम्मीद है।

बोरिस जॉनसन। फाइल

बहस में शामिल भारतवंशी इमाम पर छिड़ा विवाद

प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के लिए बीबीसी की तरफ से आयोजित सार्वजनिक बहस में शामिल भारतवंशी इमाम पर विवाद छिड़ गया है। इमाम अब्दुल्ला पटेल को ब्रिटिश जनता के प्रतिनिधि सदस्यों के पैनल में रखा गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों से ब्रिटेन में इस्लाम विरोधी धारणा से निपटने के कदमों को लेकर सवाल पूछा था। बहस में बोरिस जॉनसन ने अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी, जिसमें उन्होंने बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं की तुलना 'लेटर बॉक्स' और 'बैंक लुटेरों' से की थी। हालांकि बुधवार को माहौल इमाम अब्दुल्ला के खिलाफ हो गया। ट्विटर पर उनके कई यहूदी विरोधी ट्वीट सामने आए हैं। उनके चयन को लेकर बीबीसी पर भी सवाल उठ रहा है। हालांकि बीबीसी प्रवक्ता का कहना है कि अगर उसे इमाम के इस तरह के विचारों की जानकारी होती, तो उन्हें पैनल में नहीं चुना जाता।

अमेरिका शिक्षकों में असंतोष

दक्षिण अमेरिकी देश होंडुरास की राजधानी तेगुसीगल्पा में बुधवार को हजारों की संख्या में शिक्षक, डॉक्टर एवं छात्र सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की सुधारवादी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ हैं। ब्राजील में भी शिक्षा बजट में कटौती को लेकर शिक्षक आंदोलनरत हैं। एएफपी

62 करोड़ के लालच में किशोरी ने कर दी सहेली की हत्या

लॉस एंजिलिस, एएफपी : ऑनलाइन चैटिंग में हत्या के लिए बड़ी रकम देने के वादे पर अमेरिका में एक किशोरी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली की हत्या कर दी। अलास्का में रहने वाली 18 साल की डेनाली ब्रेहमर को इंडियाना में रहने वाले 21 साल के डेरिन शिलमिलर ने किसी की हत्या के लिए 90 लाख डॉलर (करीब 62 करोड़ रुपये) देने का वादा किया था। बड़ी रकम के लालच में डेनाली ने गत दो जून को अपने एक अन्य नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर 19 साल की सिंथिया हॉफमैन की बेरहमी से हत्या कर दी।

जांचकर्ताओं के अनुसार, डेनाली और उसका 16 साल का दोस्त कायडेन मैकइंटोश इस अपराध के लिए सिंथिया को थंडरबर्ड झरने के पास सुनसान रास्ते पर ले गए और पीछे से सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उन्होंने सिंथिया का शव नदी में फेंक दिया। सुबूत के तौर पर उन्होंने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और उसे शिलमिलर को भेजा भी था। जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस को उनके फोन से यौन हिंसा के वीडियो भी मिले हैं। हत्या और हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में तीनों को 99 साल तक की सजा हो सकती है।

खशोगी हत्याकांड में सऊदी प्रिंस के खिलाफ पुख्ता सुबूत

▸ संरा की मानवाधिकार विशेषज्ञ को मिले मुहम्मद की सीधी संलिप्तता के साक्ष्य

▸ अक्टूबर 2018 में तुर्की स्थित सऊदी के दूतावास में की गई थी पत्रकार की हत्या

जिनेवा, एएफपी : पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में सऊदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिले हैं। यह बात संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करने वाली मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कही है। इस जांच निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने मुहम्मद की विदेशी संपत्तियों की जब्ती की मांग की है। सऊदी अरब ने इस जांच रिपोर्ट को आधारहीन करार दिया है। कहा है- इस मामले के सभी आरोपितों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। खशोगी की अक्टूबर 2018 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में उस समय हत्या हुई थी जब वह अपने वीजा संबंधी दस्तावेज पेश करने गए थे।

सऊदी अरब के नागरिक खशोगी अपने देश की शाही सत्ता के तौर-तरीकों के आलोचक थे और तुर्की में रहकर अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लेख लिखते थे। इसके चलते सऊदी अरब की शाही सत्ता खासतौर पर युवराज मुहम्मद पत्रकार खशोगी से नाराज चल रहे थे। अंतरराष्ट्रीय दबाव में सऊदी अरब ने मामले की जांच कराई लेकिन युवराज को आरोपों से बरी कर दिया। सऊदी जांच में 11 उच्च अधिकारियों पर हत्या और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कर बंद कमरे में सुनवाई चल रही है। संयुक्त राष्ट्र की दूत एग्नेस कालामार्ड के अनुसार जो सुबूत मिले हैं उनसे संकेत मिल रहा है कि खशोगी हत्याकांड में युवराज की सीधी भूमिका थी।

सऊदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान की फाइल फोटो। रायटर

ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने स्पर्म डोनर को वैधानिक पिता करार दिया

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट ने एक बच्ची से जुड़े मामले में स्पर्म डोनर को उसका वैधानिक पिता करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साथ नहीं रहने के बावजूद स्पर्म देने वाला व्यक्ति बच्ची की शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय मदद से जुड़े निर्णय लेने का हकदार है। इस बच्ची के जन्म प्रमाणपत्र पर भी स्पर्म डोनर का नाम पिता के तौर पर दर्ज है।

▸ कहा-व्यक्ति बच्ची की शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय मदद से जुड़े निर्णय लेने का हकदार है

वर्ष 2006 में इस व्यक्ति ने अपने समलैंगिक दोस्त के आग्रह पर उसे पितृत्व सुख देने के लिए अपना स्पर्म दान किया था। दोस्त के घर पैदा हुई बच्ची से वह जन्म से ही मिलता-जुलता रहा। वर्ष 2015 में परेशानी तब शुरू हुई जब बच्ची की मां ने अपनी समलैंगिक पार्टनर के साथ न्यूजीलैंड में बसने की योजना बनाई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है जिसने स्पर्म डोनर को बच्ची का पिता मानने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बच्ची को ऑस्ट्रेलिया में ही रहना चाहिए जिससे उसका पिता उससे मिल सके।

मलेशियाई विमान गिराने के लिए तीन रूसियों समेत चार जिम्मेदार

▸ नीदरलैंड्स की अदालत में चलेगा हत्या का मुकदमा

▸ पांच साल पहले मिसाइल हमले में मारे गए थे 298 लोग

हेग, रायटर/एएफपी : पांच साल पहले यूक्रेन के आकाश में मलेशिया के यात्री विमान को मार गिराने के मामले में तीन रूसी और एक यूक्रेन का नागरिक हत्या के आरोपी बनाए गए हैं। नीदरलैंड्स की अगुआई में हुई अंतरराष्ट्रीय जांच में इन चार लोगों को आरोपित किया गया है। इन सभी पर नीदरलैंड्स की कोर्ट में मार्च 2020 से मुकदमा चलेगा। मिसाइल हमले का शिकार हुआ विमान एम्सटर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था, उसके ज्यादातर यात्री नीदरलैंड्स के थे। हमले में चालक दल के सदस्यों समेत विमान में सवार सभी 298 लोग मारे गए थे।

जांचकर्ताओं ने पाया है कि मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच 17 पर रूसी बीयूके मिसाइल दागी गई थी। बोइंग 777 विमान पर यह मिसाइल रूसी सेना के कुर्क स्थित ठिकाने से छोड़ी गई थी। जांच के निष्कर्ष को सार्वजनिक करते हुए नीदरलैंड्स के चीफ प्रोसीक्यूटर फ्रेंड वेस्टरबेक ने कहा, जरूरी नहीं कि आरोपितों में से किसी ने मिसाइल छोड़ने का बटन दबाया हो लेकिन यह निश्चित है कि इन चारों की अपराध में प्रमुख भूमिका थी। जांच में रूस के सहयोग न दिए जाने से मिसाइल छोड़ने वाले का नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमले के लिए जिम्मेदार ठहराए गए सर्गेई डुबिंस्की, ओलेग पुलातोव और इगोर गिरकिन (सभी रूसी) तथा यूक्रेन के लियोनिद खारचेंको के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। इससे पहले बुधवार को प्रतिक्रिया में इगोर गिरकिन ने कहा कि यूक्रेन के रूस समर्थित विद्रोही हमले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। गिरकिन रूसी खुफिया एजेंसी का पूर्व कर्नल है और उसे कट्टर रूसी राष्ट्रवादी माना जाता है। जबकि डुबिंस्की हमले के समय सैन्य खुफिया विभाग का प्रमुख था।

पुतिन ने बताया था दुर्घटना : किसी तरह की जांच में शामिल होने से इन्कार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल भर पहले कहा था कि एमएच 17 का क्रैश होना दर्दनाक हादसा था। इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस पर आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। यह रूस को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है।

अमेरिकी सांसद ने कहा, भारत को जीएसपी में लाएं

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक शीर्ष सांसद ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर से भारत को सामान्य तरजीही व्यवस्था (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफेरेंस-जीएसपी) में बहाल करने का अनुरोध किया जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था।

ट्रंप ने महत्वपूर्ण जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील देश के तौर पर भारत के ओहदे को खत्म कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि भारत ने अमेरिका को आश्वस्त नहीं किया था कि वह कि उसके बाजारों को न्यायसंगत और उचित पहुंच मुहैया कराएगा। यह निलंबन पांच जून से प्रभाव में आया।सीनेटर रॉबर्ट मेनेंदेज ने कांग्रेस के समक्ष सुनवाई के दौरान लाइटहाइजर से कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम भारत के साथ अपने मसलों को हल कर सकते हैं ताकि उन्हें जीएसपी में बहाल किया जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर मैं व्यापारिक साझेदार हूं तो मैं भविष्य की कुछ संभावनाएं चाहता हूं और जब मैं आपके साथ समझौता करता हूं तो आप मुझ पर किसी चीज के लिए कर लगाना शुरू कर देते हो जिसका कारोबार से कुछ लेना-देना नहीं होता। यह अप्रत्याशित है।

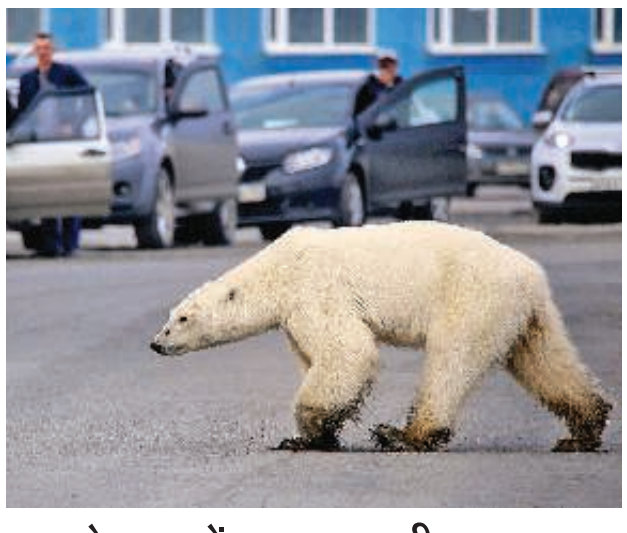

रूस के शहर में घुस आया ध्रुवीय भालू

रूस के औद्योगिक शहर नॉरिल्स्क में एक ध्रुवीय भालू के घुस आने से सड़क पर यातायात थम गया। मुख्य रूप से बर्फीले आर्कटिक में यह ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक में बड़े पैमाने पर बर्फ पिघल रही है। ऐसे में कई भालू अपने प्राकृतिक आवासों को छोड़कर सैकड़ों किमी दूर शहरी इलाकों में घुस आए हैं। इससे शहरों में अजीब किस्म का भय और आतंक का माहौल है। एएफपी

ढाका में पावर प्लांट साइट पर विवाद में चीनी युवक की मौत

ढाका, एएफपी : बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उस वक्त स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, जब एक पावर प्लांट के परियोजना स्थल पर चीन और बांग्लादेश के श्रमिक भिड़ गए। इस घटना में चीन के एक श्रमिक की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। मामला उस समय भड़क उठा जब एक बांग्लादेशी की मौत के बाद वहां मौजूद चीन के लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासक राम चंद्रदास ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

दरअसल, चीन की सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अरबों डालर का निवेश कर रखा है। ज्यादातर निवेश बिजली, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में किया गया है। इसी सिलसिले में ढाका से 200 किमी दूर चीन की वित्तीय मदद से 1320 मेगावाट के एक पावर प्लांट का निर्माण चल रहा है। परियोजना स्थल पर कुल 6000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 2000 चीन के नागरिक हैं। निर्माण के दौरान एक बांग्लादेशी कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि चीन के कर्मचारी इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे थे। इससे गुस्साए सैकड़ों बांग्लादेशी और चीन के कर्मचारी आमने-सामने आ गए। झड़प में दोनों तरफ के दर्जनों लोग घायल हुए।

चेन्नई एयरपोर्ट पर नकली टिकट के साथ चीनी गिरफ्तार

चेन्नई, प्रेट्र : चीन के एक 19 साल के युवक को चेन्नई एयरपोर्ट पर नकली टिकट के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त युवक को सीआइएसएफ ने उस समय पकड़ा जब वह हांगकांग की रहने वाली गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद बाहर आ रहा था। इससे पूर्व वह उसी टिकट पर एयरपोर्ट में दाखिल हो गया था।

शरीफ ने रिपोर्ट सौंपने की इजाजत के लिए दायर की याचिका

इस्लामाबाद, प्रेट्र : जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अतिरिक्त मेडिकल रिपोर्ट सौंपने की इजाजत मांगी है। दरअसल, अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मेडिकल आधार पर उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी है।

'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार की खबर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के 69 वर्षीय सुप्रीमो के वकील ने याचिका दायर कर एक विदेशी डॉक्टर से प्राप्त सत्यापित मेडिकल रिपोर्ट सौंपने की इजाजत मांगी है। याचिका में कहा गया है कि अतिरिक्त रिकार्ड मुहैया करने के लिए इजाजत दी जानी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख कर इस बात का जिक्र किया था कि मेडिकल रिपोर्ट में उनकी हालत नाजुक बताई गई है । शरीफ 24 दिसंबर 2018 से लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल कैद की सजा काट रहे हैं।

जयशंकर ने की रूस के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात

▸ पीएम नरेंद्र मोदी की व्लाडीवोस्टक यात्रा पर दोनों नेताओं ने की चर्चा

▸ पेट्रोलियम मंत्री के साथ ऊर्जा सहयोग पर की बातचीत

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत दौरे पर आए रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी ट्रुटनेव से मुलाकात की। बुधवार को हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने पूर्वी आर्थिक मंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी वर्ष बाद में होने वाली व्लाडिवोस्टक यात्रा और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। रूस के उप प्रधानमंत्री ने बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

बुधवार को हुई मुलाकात से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने भारत-रूस संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पूर्वी आर्थिक मंच के लिए प्रधानमंत्री मोदी की व्लाडिवोस्टक यात्रा के बारे में चर्चा की। ट्रुटनेव की अगुवाई में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 15 से 19 जून तक भारत की यात्रा पर आया था।

इस दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के साथ बातचीत की। उन्होंने एक गोल-मेज चर्चा में भी भाग लिया जिसमें विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय और रूसी विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। अपनी यात्रा के दौरान ट्रुटनेव मुंबई भी गए जहां उन्होंने भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत की।

ये भी जानिए

चोटिल भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की जगह भारत की विश्व कप टीम में शामिल युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत ने सिर्फ नौ वनडे मैच खेले हैं। इसमें उनके नाम 93 रन दर्ज हैं।

शमी का फिट होना मेरी बड़ी उपलब्धि : शंकर बासु

अभिषेक त्रिपाठी, साउथैंप्टन

भारतीय कप्तान विराट कोहली मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में शामिल होते हैं, निश्चित रूप से उनकी फिटनेस को देखकर कोई भी कोच खुश होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे अच्छी फिटनेस वाली टीम के रूप में देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारतीय टीम के 'स्ट्रेंथ एवं कंडिशनिंग' कोच शंकर बासु को। बासु ने भारतीय टीम की फिटनेस पर काफी काम किया है और उनका मानना है कि उनके टीम से जुड़ने के बाद मुहम्मद शमी का चोटों से मुक्त रहकर फिट रहना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।

भारतीय टीम के 'स्ट्रेंथ एवं कंडिशनिंग' कोच ने कहा, जाधव भी फिटनेस को लेकर सचेत हुए

50 वर्षीय बासु इस बात से संतुष्ट हैं कि चोटों से मुक्त शमी और केदार जाधव भी अब फिटनेस के प्रति सचेत हो गए हैं, जो पहले कोई उचित फिटनेस ट्रेनिंग नहीं करते थे। बासु ने कहा, 'कोई भी कोच विराट को देखकर खुश होगा। उनकी सबसे बड़ी चीज यही है कि वह साल के प्रत्येक दिन किसी भी व्यायाम को करने को तैयार रहते हैं। वह अपने शरीर को जानते हैं और अगर वह ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके अपनी दिनचर्या के संबंध में सौ सवाल होंगे। जब उन्हें जवाब मिल जाएंगे तो वह गंभीरता से उनका पालन करते हैं। शमी पिछले सत्र में चोट की वजह से एक भी टेस्ट मैच में बाहर नहीं हुए हैं।'

भारत के इस पूर्व जूनियर धावक से जब पूछा गया कि वह इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद, आप ऐसा कह सकते हो। उन्होंने कहा, 'सोचो, वह (शमी) पिछले साल फिटनेस टेस्ट में विफल रहे थे और उनकी निजी जिंदगी में भी कुछ मुद्दे रहे थे। वापसी करने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। मैंने शमी को कहा था कि 20 दिन के लिए कड़ी ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आपको लगातार ट्रेनिंग करनी होती है। अब ट्रेनिंग उसकी जीवनशैली बन चुकी है। अब उनकी तेजी देखो, जो पांच मैचों की सीरीज के अंतिम टेस्ट के दिन भी कम नहीं होती। बुमराह जब टीम में आए तो वह फिट लोगों में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छी नींद ली, अच्छा आहार और कड़ी मेहनत करके फिट हो गए।'

भारतीय टीम के मैनेजर सुनील सुब्रह्मण्यम और स्ट्रेंथ एवं कंडिशनिंग कोच शंकर बासु (दायें)। जागरण

सभी के प्रशिक्षण के साथ-साथ खाना भी अलग-अलग है और यह एक मिथक है कि इस टीम का प्रत्येक खिलाड़ी कोहली की तरह भुना हुआ खाता है। बासु ने कहा, 'विराट और डीके अच्छी तरह से वेटलिफ्टिंग करते हैं, लेकिन बुमराह और राहुल प्लीमेट्रिक अभ्यास करते हैं जिसमें कूदना शामिल है। इससे पावर और गति बढ़ाने में मदद मिलती है। सभी के शरीर अलग हैं और दिनचर्या भी अलग हैं।' हालांकि बासु को विजय शंकर के ज्यादा चावल खाने से परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, 'आपको यह समझने की जरूरत है कि शंकर एक अच्छे एथलीट हैं। वह दक्षिण भारत से हैं और उनका कुछ प्रकार के खाने से लगाव है। आप उन्हें इससे दूर नहीं कर सकते। आप हार्दिक पांड्या को देखें, वह हाथी भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वह पतले ही दिखेंगे।' महेंद्र सिंह धौनी की फिटनेस को लेकर बासु ने कहा, 'धौनी अच्छे से जानते हैं कि उनका शरीर अभी फिट है। यदि हम अच्छी पावर के बारे में बात करते हैं तो मैं इसमें धौनी, रिषभ पंत और पवन नेगी के नाम लूंगा क्योंकि ये तीन पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। पंत में अविश्वसनीय पावर है।' बासु ने 1987 में टोक्यो में एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने करियर के बारे में कहा, 'आनंद नटराजन (पूर्व 100 मीटर राष्ट्रीय चैंपियन) और मैं एक साथ पढ़े थे। मैं सीनियर स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। मेरा सबसे बड़ा फायदा पिछले 25 वर्षों में गलतियों से सीखना है।'

जब बासु को भारतीय टीम की नौकरी की पेशकश की गई तो उनके मन में स्पष्ट था कि सभी फिटनेस संस्कृति में बदलाव चाहते हैं और इस दौरान, कोचिंग स्टाफ का समर्थन शानदार रहा। उन्होंने कहा, 'भरत अरुण (गेंदबाजी कोच) मेरे दोस्त हैं और जब मैं उन्हें बोलता हूं कि गेंदबाज एक विशिष्ट संख्या में गेंदबाजी करेंगे तो वह इस बात को मान लेते हैं और संजय बांगर को कुछ बोलता हूं तो वह भी समर्थन करते हैं। हर कोई अब फिटनेस का आनंद ले रहा है। मैंने सोचा कि मुझे एक बार में एक काम करना है। मैं इस आधुनिक क्रिकेट में अलग तरह का प्रशिक्षण लेकर आया। यह सब स्पीड और पावर है।

भारत को झटका, धवन विश्व कप से बाहर

भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल हुए रिषभ पंत, भुवनेश्वर के अगले सात-आठ दिन में फिट होने की संभावना

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी ● साउथैंप्टन

दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हराकर सातवें आसमान में उड़ रही भारतीय क्रिकेट टीम को ओपनर शिखर धवन के विश्व कप से बाहर हो जाने से बड़ा झटका लगा है। धवन को नौ जून को ओवल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में चोट लगी थी और उसके बाद वह पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। पैट कमिंस की गेंद उनके बायें दस्ताने पर लगी थी। हालांकि, चोट के बावजूद धवन ने उस मैच में सैकड़ा लगाया था। भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम में होने वाला मुकाबला बारिश के कारण रद हो गया था।

टीम प्रबंधन को उम्मीद थी कि धवन दो सप्ताह में ठीक हो जाएंगे, लेकिन बुधवार को टीम मैनेजर सुनील सुब्रह्मण्यम ने प्रेस कांफ्रेंस करके इस ओपनर के टीम से बाहर होने की घोषणा कर दी। उन्होंने साथ ही बताया कि कवर के तौर पर यहां बुलाए गए विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को अंतिम-15 में शामिल करने के लिए आइसीसी से कहा गया है। दैनिक जागरण को मिली जानकारी के अनुसार आइसीसी ने बीसीसीआइ के निवेदन को मान लिया है। रिषभ ने साउथैंप्टन में बुधवार को टीम के साथ अभ्यास भी किया। अब भारतीय टीम को शनिवार को हैंपशायर क्रिकेट मैदान में अफगानिस्तान से भिड़ना है। हार से बेजार अफगानिस्तान टीम पहले से ही परेशान है, इसलिए उसे हराने में टीम इंडिया को कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है।

टीम प्रबंधन ने दिया काफी मौका : 33 वर्षीय धवन के अंगूठे में चोट लगने के बाद भारत-न्यूजीलैंड मैच से पहले उनका स्कैन कराया गया था और उसके बाद उनके अंगूठे और अंगुली के बीच में हेयरलाइन फ्रैक्चर का पता चला था। भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच संजय बांगर ने इससे पहले कहा था कि उन पर नजर रखी जा रही है और 27 जून को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मैच के बाद उन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी कहा था कि शिखर धवन विश्व कप के आखिरी चरण तक फिट हो जाएंगे। विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में उनकी दरकार होगी, लेकिन बुधवार को भारतीय टीम के अभ्यास के बाद प्रेस कांफ्रेंस में टीम के मैनेजर ने बताया कि उनकी चोट में सुधार नहीं हुआ है और यह बायें हाथ का सलामी बल्लेबाज 15 जुलाई तक ठीक नहीं हो पाएगा।

मालूम हो कि विश्व कप का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाना है। वहीं, जब टीम मैनेजर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हुए दायें हाथ के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन पर नजर रखी जा रही है और वह टीम में बने हुए हैं। वहीं, टीम इंडिया के एक सूत्र ने कहा कि भुवी अगले सात-आठ दिन में गेंदबाजी करने लगेंगे।

विश्व कप के लिए अहम थे धवन

साउथैंप्टन : धवन ओपनर के तौर पर भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित भी कर दी थी। उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग में उतरे थे और उन्होंने भी अर्धशतक लगाया था। आने वाले मैचों में भी वही रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। धवन के रहने से उनका और रोहित का बायें-दायें हाथ के बल्लेबाज का संयोजन बनता है जो गेंदबाजों को परेशान करता है, जबकि रोहित और राहुल दोनों ही दायें हाथ के ओपनर हैं। पिछले आइसीसी टूर्नामेंटों में धवन भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए हैं। साल 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी जिसमें धवन भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर थे। उन्होंने पांच पारियों में 90.75 के औसत से 363 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए विश्व कप में धवन ने भारत के लिए सबसे अधिक रन बटोरे थे। उन्होंने आठ मैचों में 51.50 के औसत से 412 रन बनाए थे। इस विश्व कप में भी उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक जड़ा था। उनके बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा थे, जिन्होंने 330 रन बनाए थे।

पंत की लॉटरी लगी

साउथैंप्टन : धवन का जाना भले ही प्रशंसकों को दुख दे गया हो, लेकिन इससे युवा रिषभ पंत की लॉटरी लग गई है। अब उन्हें खुद को साबित करना होगा। चयनकर्ताओं ने पंत को शानदार फॉर्म के बावजूद टीम में नहीं चुना था। सुनील गावस्कर ने भी पंत को टीम में शामिल करने का समर्थन किया और कहा था कि अगर धवन बाहर हो गए तो दिल्ली का यह खिलाड़ी टीम में शामिल होने का हकदार है। पंत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट दौरे के दौरान शतक जड़े थे। आइपीएल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। पंत भारत-पाकिस्तान मैच से पहले ही मैनचेस्टर में धवन के कवर के तौर पर पहुंच गए थे। हालांकि, पिछले मैच में धवन की जगह विजय शंकर को अंतिम एकादश में शामिल किया गया था और वह मध्य क्रम में उतरे थे। वह बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी कर लेते हैं और उन्होंने दो विकेट भी लिए थे। ऐसे में रिषभ पंत के लिए अंतिम एकादश में जगह बनान इतना आसान नहीं होगा।

117 रन की पारी खेली थी शिखर धवन ने इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस पारी के दौरान वह चोटिल हुए थे

125 रन बनाए धवन ने इस विश्व कप में खेले दो मैचों में। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ आठ रन बना सके थे

537 रन बनाए हैं भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने विश्व कप में अब तक खेले 10 मैचों में 53.70 की औसत से। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 94.21 का रहा है

विराट कोहली ने की गेंदबाजी

साउथैंप्टन : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अभ्यास सत्र के दौरान गेंदबाजी में भी हाथ आजमाए। घरेलू क्रिकेट में पार्ट टाइम गेंदबाज रहे विराट ने बुधवार को बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हार्दिक पांड्या को कुछ गेंदें फेंकीं। इसके बाद वह बल्लेबाजी का अभ्यास करने लगे। कोहली ने 77 टेस्ट मैचों की नौ पारियों में गेंदबाजी की है जिसमें उन्होंने 163 गेंदों पर 76 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उन्होंने 230 वनडे की 48 पारियों में 641 गेंदों पर 665 रन दिए। इस दौरान उन्होंने चार विकेट भी हासिल किए। वह 109 प्रथम श्रेणी मैचों में तीन विकेट ले चुके हैं।

शमी खेलेंगे अगला मैच : भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार को होने वाले मुकाबले में मुहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। भारत इन तीन गेंदबाजों के साथ ही इंग्लैंड आया है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विजय शंकर उनका साथ देंगे। विराट ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में बुमराह और भुवी के साथ उतरने का फैसला किया था क्योंकि इंग्लैंड में बादलों के कारण स्विंग गेंदबाजों को काफी फायदा मिलता है। भुवी इन परिस्थितियों का अच्छा फायदा उठाते रहे हैं।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ● एपी

बहुत भावुक होकर मुझे यह घोषणा करनी पड़ रही है कि मैं अब 2019 विश्व कप का हिस्सा नहीं रह पाऊंगा। मैं इस विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता था, लेकिन मेरा अंगूठा समय पर ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे बाहर होना पड़ रहा है। अब मुझे वापस लौटना होगा और आगे की तैयार करनी होगी। मुझे भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी टीम के लिए शानदार खेल दिखाएंगे और इस विश्व कप को जीतेंगे। साथी खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों और पूरे देश ने जो मेरे प्रति प्यार दिखाया और प्रार्थनाएं कीं उसके लिए आप सभी का आभार। जय हिंद।

शिखर धवन, भारतीय ओपनर

03 शतक कुल मिलाकर विश्व कप में बनाए हैं धवन ने। उन्होंने 2015 में हुए पिछले विश्व कप में दो शतक जड़े थे

हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इस समय भुवनेश्वर की देखरेख कर रहे हैं और हम बहुत जल्द उनकी स्थिति जान लेंगे।

शंकर बासु, स्ट्रेंथ एवं कंडिशनिंग कोच, भारत

विश्व कप अंक तालिका

	देश	मैच	जीते	हारे	ड्रॉ	अंक	नेट रनरेट
	इंग्लैंड	5	4	1	0	8	1.862
	ऑस्ट्रेलिया	5	4	1	0	8	0.812
	न्यूजीलैंड	4	3	0	1	7	2.163
	भारत	4	3	0	1	7	1.029
	बांग्लादेश	5	2	2	1	5	-0.270
	श्रीलंका	5	1	2	2	4	-1.778
	वेस्टइंडीज	5	1	3	1	3	0.272
	द. अफ्रीका	5	1	3	1	3	-0.208
	पाकिस्तान	5	1	3	1	3	-1.933
	अफगानिस्तान	5	0	5	0	0	-2.089

बांग्लादेश को फील्डिंग में सुधार करना होगा

सुनील गावस्कर

कलम से

बांग्लादेश शानदार फॉर्म में है। वे कुछ बेहद शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाले शाकिब अल हसन को देखना सच में अद्भुत है। वह दो शतक के साथ एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि यह टीम किसी भी लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। उन्होंने कई ओवर बाकी रहते हुए 300 से ज्यादा के लक्ष्य को हासिल किया। वो भी अपने प्रमुख बल्लेबाज तमीम इकबाल और हमेशा फॉर्म में रहने वाले मुश्फिकुर के योगदान के बिना। यह देखना और भी अच्छा रहा कि अन्य खिलाड़ी भी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। शाकिब विकेट भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी चिंता का विषय है। मजबूत बल्लेबाजी क्रम वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम निश्चित तौर पर कमजोर क्षेत्र पर हमला करेगी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने फिर से अपनी फॉर्म हासिल कर ली है। मिशेल स्टार्क अपनी गति और सटीकता से आखिरी ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे हुए हैं। कमिंस और रिचर्डसन भी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। जांपा और मैक्सवेल भी सही लाइन पर गेंदबाजी कर तेज गेंदबाजों को राहत दे रहे हैं। यह देखना रोचक होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश स्पिनर से गेंदबाजी की शुरुआत कराता है या नहीं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को अच्छे से खेलते हैं और बांग्लादेश इस क्षेत्र में पावर प्ले और अंतिम ओवरों में कमजोर ही साबित हुआ है। उनकी फील्डिंग में भी थोड़े सुधार की जरूरत है, खासतौर से बाउंड्री पर। एक गेंदबाज के लिए सबसे हताशा की बात यही होती है, जब फील्डर बाउंड्री पर उसकी गेंद को नहीं रोक पाता है। इससे वह अचानक से दबाव में आ जाता है। कूदने या फिसलने में अभ्यास के साथ ही सुधार होता है और इसके लिए जज्बा भी चाहिए। मगर हाल में बहुत से खिलाड़ी ऐसा करते हुए खुद को चोटिल करवा चुके हैं।

BKT

रेसे वेन डेर के अर्धशतक से न्यूजीलैंड को दिया 242 रनों का लक्ष्य, कीवी टीम ने दिया शानदार जवाब

डुसेन ने दक्षिण अफ्रीका की ढहती पारी को संभाला

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : मध्य क्रम के बल्लेबाज रेसे वेन डेर डुसेन एक बार फिर अपनी टीम दक्षिण अफ्रीका को संकट की घड़ी से बाहर निकालने में सफल रहे। 30 वर्षीय दायें हाथ के बल्लेबाज ने बुधवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उपयोगी अर्धशतक लगाकर टीम को खराब स्थिति से बाहर निकालकर चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। डुसेन के अलावा अनुभवी बल्लेबाज हाशिम अमला ने अर्धशतक लगाया और विश्व कप के मैच में न्यूजीलैंड के सामने 242 रनों का लक्ष्य रखा। डुसेन ने नाबाद 67 रनों की पारी खेली, जबकि अमला ने 55 रनों का योगदान दिया। उनकी पारियों से दक्षिण अफ्रीकी टीम 49 ओवर में छह विकेट पर 241 रन बना पाई। डुसेन ने अपनी नाबाद पारी में 64 गेंदों में दो चौके और तीन छक्के लगाए। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने 27 ओवर में चार विकेट पर 109 रन बनाए थे। जेम्स नीशाम 12 और कप्तान केन विलियमसन 49 रन पर नाबाद थे।

जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने खबर लिखे जाने तक 37 ओवर में पांच विकेट पर 169 रन बना लिए थे। कप्तान केन विलियमसन ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 74 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि उनका साथ कोलिन डि ग्रैंडहोम 21 रन बनाकर दे रहे थे। विलियमसन ने अपनी पारी में 104 गेंदों का सामना किया। अभी भी न्यूजीलैंड को लक्ष्य हासिल करने के लिए 72 गेंदों में 73 रनों की जरूरत थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। मॉरिस के अलावा तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा और एंदिले फेलुकवायो ने निभाया। दोनों गेंदबाजों ने एक-एक विकेट लिया। विलियमसन के अलावा सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने भी 35 रनों की पारी खेली।

दक्षिण अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी इस विश्व कप में संघर्ष कर रही है और डुसेन इससे पहले भी इस टूर्नामेंट में कई मौकों पर टीम की लाज बचा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था और उस मैच में टीम सिर्फ 207 रनों पर ढेर हो गई थी और उस मैच में भी डुसेन ने 50 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 41 रनों की उपयोगी पारी खेली। वह इस टूर्नामेंट में अभी तक दो अर्धशतक लगा चुके हैं।

मैच में हल्की बारिश और मैदान गीला होने की वजह से टॉस होने में करीब डेढ़ घंटे की देरी हुई। इसके साथ ही ओवरों की संख्या में कटौती की गई और मैच 49-49 ओवरों का कर दिया गया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने अंतिम एकादश में लुंगी नगिदी को शामिल किया, जो चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे।

दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही और टीम के खाते में नौ रह ही जुड़े थे कि सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (05) को तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (1/63) ने बोल्ड कर दिया। डिकॉक अपनी आइपीएल की शानदार फॉर्म को इस टूर्नामेंट में जारी नहीं रख पाए और ज्यादातर मौकों पर उन्होंने टीम को निराश किया है। इसके बाद 13.6 ओवर में लॉकी फग्यूर्सन (3/59) ने कीवी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। फर्ग्यूसन ने कप्तान फाफ डुप्लेसिस (23) को चलता किया। दूसरे विकेट के लिए फाफ और अमला के बीच 50 रन की अर्धशतकीय साझेदारी हुई। फाफ के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए एडेन मार्करैम ने अमला के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन मिशेल सेंटनर (1/45) ने इस जोड़ी को तोड़ा और अमला को चलता किया। हाशिम अमला ने 83 गेंदों में 55 रन की धीमी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके लगाए। तीसरे विकेट के लिए अमला और मार्करैम के बीच 52 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी हुई। 32.3 ओवर में दक्षिण अफ्रीका को मार्करैम (38) के रूप में चौथा झटका लगा। कोलिन डि ग्रैंडहोम (1/33) ने उन्हें मुनरो के हाथों कैच आउट कराकर पेवलियन भेजा। इसके बाद फर्ग्यूसन ने डेविड मिलर (36) के रूप में अफ्रीकी टीम को पांचवां झटका दिया। मिलर ने उन्हें बोल्ट को हाथों के कैच आउट कराया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ला उठाते रेसे वेन डेर डुसेन ● एएफपी

स्कोर बोर्ड

टॉस : न्यूजीलैंड (गेंदबाजी)

दक्षिण अफ्रीका 241/6 (49 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
क्विंटन डिकॉक बो. बोल्ट	05	08	01	00
हाशिम अमला बो. सेंटनर	55	83	04	00
फाफ डुप्लेसिस बो. फर्ग्यूसन	23	35	04	00
एडेन मार्करैम का. मुनरो बो. ग्रैंडहोम	38	55	04	00
रेसे वेन डेर डुसेन नाबाद	67	64	02	03
डेविड मिलर का. बोल्ट बो. फर्ग्यूसन	36	37	02	01
फेलुकवायो का. केन बो. फर्ग्यूसन	00	05	00	00
क्रिस मॉरिस नाबाद	06	07	01	00

अतिरिक्त : (लेबा-7, वा-4) 11

कुल : 49 ओवर में छह विकेट पर 241 रन

विकेट पतन : 1-9 (डिकॉक, 1.5), 2-59 (डुप्लेसिस, 13.6), 3-111 (अमला, 27.4), 4-136 (मार्करैम, 32.3), 5-208 (मिलर, 44.5), 6-218 (फेलुकवायो, 46.3)

गेंदबाजी :
मैट हेनरी 10-2-34-0
ट्रेंट बोल्ट 10-0-63-1
लॉकी फर्ग्यूसन 10-0-59-3
डि ग्रैंडहोम 10-0-33-1
मिशेल सेंटनर 9-0-45-1

अमला के 8000 रन पूरे

नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीकी अनुभवी बल्लेबाजी हाशिम अमला ने वनडे में अपने 8000 रन पूरे कर लिए। वह 25 रन बनाते ही वनडे में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए। यह कारनामा उन्होंने 176 पारियों में किया। इस मामले में वह केवल भारतीय कप्तान विराट कोहली से ही सिर्फ पीछे हैं। विराट ने वनडे में 175 पारियों में अपने 8000 रन पूरे किए थे।

हाशिम अमला ● एपी

ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने उतरेगा बांग्लादेश

नॉटिंघम, प्रेट्र : पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम गुरुवार को विश्व कप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए सेमीफाइनल के करीब पहुंचना चाहेगी। आरोन फिंच की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम (0.812) नेट रन रेट के आधार पर शीर्ष पर चल रही इंग्लैंड (1.862) से पीछे है। हालांकि, दोनों के पांच मैचों में आठ-आठ अंक हैं।

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ● एएफपी

प्रबल दावेदारों में शुमार ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा विश्व कप में दबदबा बनाती आई है और इस बार भी कुछ अलग नहीं हो रहा। उसने अभी तक पांच मैचों में से सिर्फ भारत के खिलाफ एकमात्र मुकाबला गंवाया है। कप्तान मशरफे मुर्तजा की बांग्लादेशी टीम ने अभी तक विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर उसे उलटफेर की उम्मीद लगानी है तो उसके खिलाड़ियों को सभी विभागों में अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा।

ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर है कि मार्कस स्टोइनिस चोटिल होने के बाद वापसी कर चुके हैं, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ उनके खेलने की संभावना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच ब्रैड हेडिन का मानना है कि अभी तक टीम टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखा सकी है, जबकि मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस विपक्षी टीमों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। आरोन फिंच और डेविड वार्नर जहां टीम को मजबूत शुरुआत दिला रहे हैं तो मध्य क्रम में स्टीव स्मिथ मौजूद हैं। बांग्लादेश की टीम की बात की जाए तो उसने अभी तक पांच में से दो मैच गंवाए हैं तो दो में जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में तो वह काफी करीब से हारी थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ उसने आसानी से 322 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरा सी भी उम्मीद लगाने के लिए उसे इसी प्रदर्शन का दोहराव करना होगा। ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने इस मैच में 124 रन की नाबाद पारी खेली थी। शाकिब शानदार फॉर्म में हैं और वह लगातार दो शतक जड़ चुके हैं।

चित्रा ने सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता

नई दिल्ली : एशियन चैंपियन पीयू चित्रा ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वीडन के सोलेंतुना में फोल्कसैम ग्रां प्रि में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। अप्रैल में दोहा एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली चित्रा ने कीनिया की मर्सी शेरोनो को पछाड़ते हुए चार मिनट 12.65 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मर्सी ने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था।

भारतीय टीम फॉर्म में है। चोट पर किसी का वश नहीं है। यह टीम मजबूत है और विश्व कप के सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेगी।
– सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय कप्तान

फुटबॉल डायरी ▸ कोपा अमेरिका में दो मौके पर वार ने आयोग्य किए ब्राजील के गोल

ब्राजील को वेनेजुएला ने गोलरहित बराबरी पर रोका

ड्रॉ के बावजूद अंक तालिका में शीर्ष पर है मेजबान टीम

साल्वाडोर (ब्राजील), एएफपी : कोपा अमेरिका में मेजबान ब्राजील की फुटबॉल टीम को वेनेजुएला ने गोलरहित (0-0) बराबरी पर रोक दिया। इस दौरान ब्राजील के स्टार फिलिप कौटिन्हो द्वारा आखिरी लम्हों में किए गए गोल को वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वार) की मदद से विवादस्पद तरीके से आयोग्य करार दिया गया।

खेल के 87वें मिनट में कौटिन्हो ने गोल करके ब्राजील के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन मुकाबले में दूसरी बार चिली के रेफरी जूलियो बास्कुनान ने ब्राजील के गोल को वार की मदद से आयोग्य करार दिया। इस गोल को लिवरपूल के लिए खेलने वाले रॉबर्टो फर्मिनो द्वारा छूने की वजह से आयोग्य करार दिया गया, लेकिन वीडियो में देखकर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह ऑफ साइड थे या नहीं। इससे पहले खेल के 38वें मिनट में भी फर्मिनो द्वारा किए गए गोल को फाउल की वजह से आयोग्य करार दिया गया था। मुकाबला खत्म होने के बाद ब्राजील के खिलाड़ियों को मैदान से निकलते समय दर्शकों ने चिढ़ाया, लेकिन गोलरहित ड्रॉ के बावजूद ब्राजील ग्रुप-ए में दो मैचों में चार अंकों के साथ शीर्ष पर बरकरार रहा। उसे ग्रुप चरण में अभी एक और मुकाबला खेलना बाकी है। वहीं वेनेजुएला के पास दो मैचों में दो अंक है और उसके भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं।

पेरू की शानदार जीत : उधर, ग्रुप-ए के ही एक अन्य मुकाबले में पेरू, बोलिविया को 3-1 से करारी शिकस्त देकर नॉकआउट में पहुंचने के करीब पहुंच गया। पेरू के लिए कप्तान पाओलो ग्यूरेरो और स्ट्राइकर जेफरसन फर्फान के अलावा एडिंसन फ्लोरेस ने गोल किए। वहीं, बोलिविया के लिए इकलौता गोल मार्सेलो मोरेनो ने किया। इस जीत के साथ चार अंक लेकर पेरू अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

साल्वाडोर में वेनेजुएला के खिलाफ गोलरहित मुकाबला खेलने के बाद निराश खड़े ब्राजील के खिलाड़ी। एएफपी

प्लाटिनी को किया गया रिहा

नांटेरे (फ्रांस), एएफपी : यूरोपियन फुटबॉल के पूर्व प्रमुख मिशेल प्लाटिनी को बुधवार को रिहा कर दिया गया। उन्हें कतर को 2022 विश्व कप की मेजबानी सौंपने के मामले की जांच कर रही फ्रांस की भ्रष्टाचार रोधी पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में लिया था। इस मामले में प्लाटिनी से घंटो पूछताछ की गई। हालांकि फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर रहे प्लाटिनी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है।

मार्ता ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

वेलेंसिएनेस (फ्रांस), एएफपी : ब्राजील की मार्ता फुटबॉल विश्व कप में सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। फीफा महिला विश्व कप में मार्ता के गोल की बदौलत ब्राजील ने इटली को 1-0 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई। 33 वर्षीय मार्ता ने 74 वें मिनट में पेनाल्टी किक पर गोल किया। यह फीफा विश्व कप में किसी भी पुरुष या महिला खिलाड़ी द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल हैं। इस मामले में मार्ता ने मिरोस्लाव क्लोस के सर्वाधिक 16 गोल के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

पाक खिलाड़ियों के भारत में खेलने का रास्ता खुला

- खेल सचिव ने आइओसी और आइओए को दिया आश्वासन
- कहा, भारत सभी योग्य खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति देगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के निलंबन से जुड़ा मसला अब सुलझता दिखाई दे रहा है। ताजा मामले में सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) को लिखित आश्वासन दिया है कि सभी पात्र खिलाड़ियों को देश में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भी भारत में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल सकेंगे।

फरवरी में भारत में हुए निशानेबाजी विश्व कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के निशानेबाजों को वीजा नहीं दिया गया था, जिसके बाद आइओसी ने भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी से जुड़ी बातचीत को रद कर दिया था। इसके साथ ही ओलंपिक समिति ने कहा था कि जब तब भारत सरकार से लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वह देश में ओलंपिक क्वालीफायर संबंधित प्रतियोगिताओं की मेजबानी नहीं करने देगा। इस बाबत खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने आइओए को पत्र लिख कर कहा है कि हर उस देश और राष्ट्रीय महासंघ को भारत में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लेने की अनुमति होगी जो आइओसी से मान्यता प्राप्त है। आइओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को केंद्रीय खेल सचिव जुलानिया ने लिखित बयान में कहा, 'भारत आइओसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या अंतरराष्ट्रीय महासंघ से संबंधित किसी राष्ट्रीय संघ के सभी योग्य खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति देगा। भारत सरकार की नीति आइओसी के अंतर्गत भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सभी योग्य एथलीटों, खिलाड़ियों और अधिकारियों की भागीदारी का आश्वासन देती है।'

पिछले साल भी भारत ने कोसोवो की मुक्केबाज डोंजेता सादिकु को दिल्ली में हुई विश्व महिला चैंपियनशिप में भाग लेने से मना कर दिया था क्योंकि भारत उस देश को मान्यता नहीं देता है। हालांकि, खेल सचिव ने कहा कि सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पत्र की एक प्रति आइओसी प्रमुख थॉमस बाक को भी भेजी गई जिसमें लिखा गया है, 'भारत सरकार ने देश में खेलों के विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। आइओसी के सहयोग से हमारी सरकार की योजना लोगों की खेल क्षमताओं को बढ़ाने की है। यह ओलंपिक चार्टर के मूल्यों और सिद्धांतो पर आधारित है।' पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा नहीं देने संबंधी दिक्कतों के बाद से भारत कई प्रमुख प्रतियोगिताओं की मेजबानी गंवा चुका है।

विश्व तीरंदाजी ने एएआइ को दिया एक महीने का अल्टीमेटम

कोलकाता, प्रेट्र : विश्व तीरंदाजी संस्था ने अपने सदस्य संघों की सूची में से भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआइ) का नाम हटा दिया है और इसे अंदरूनी समस्याएं सुलझाने के लिए एक महीने का समय दिया है, वर्ना उसे निलंबन झेलना पड़ेगा। विश्व तीरंदाजी ने कहा कि वह एएआइ के निलंबन पर फैसला करने के लिए 31 जुलाई तक इंतजार करेगी। विश्व तीरंदाजी एएआइ के विवादास्पद चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी।

एएआइ को सदस्य सूची से बाहर किए जाने के फैसले के बावजूद भारतीय तीरंदाज उन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय ध्वज के तहत भाग ले सकते हैं जिसमें प्रविष्ट्रियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं। विश्व तीरंदाजी ने दो पन्ने के फैसले में कहा, '(विश्व तीरंदाजी) कार्यकारी बोर्ड ने फैसला किया है कि काफी सबूत हैं कि एएआइ ने विश्व तीरंदाजी संविधान और नियम के धारा 1.4.2.4 और 1.4.2.5.1 का उल्लघंन किया है और विशेषकर 1.4.2.5.1 धारा के अंतिम प्वाइंट का जिसमें सुशासन जरूरी होता है। इसके चलते भारत को सदस्य संघ की सूची में शामिल नहीं किया गया और विश्व तीरंदाजी 31 जुलाई तक इंतजार करेगी। इसके बाद वह अदालत के नतीजे के आधार पर परिस्थितियों की दोबारा जांच करेगी।' अभी तक बर्लिन तीरंदाजी विश्व कप चरण (एक से सात जुलाई) और टोक्यो ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता (11 से 18 जुलाई) के लिए अंतिम प्रविष्ट्रियां, जबकि मैड्रिड विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप (19 से 25 अगस्त) के लिए 24 सदस्यीय शुरुआती प्रविष्ट्रियां भेजी जा चुकी हैं। विश्व तीरंदाजी ने तदर्थ पैनल के गठन का निर्देश दिया है जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ, खेल मंत्रालय और एएआइ के दोनों गुटों के एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

नई दिल्ली में बुधवार को भारतीय तीरंदाजों से मुलाकात करते खेल मंत्री किरण रिजिजू। प्रेट्र

खेल मंत्री रिजिजू ने तीरंदाजों को दिया आश्वासन

नई दिल्ली, प्रेट्र : खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को भारतीय तीरंदाजों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया कि सरकार उनके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी। भारतीय तीरंदाजी टीम हाल ही में नीदरलैंड्स के डेन बॉश में हुई विश्व चैंपियनशिप में एक रजत और दो कांस्य सहित तीन पदक के साथ स्वदेश लौटी है। तरुणदीप रॉय, अतानु दास और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के साथ 2020 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल किया। महिलाओं के वर्ग में ज्योति सुरेखा वेनम के शानदार खेल के दम पर भारत ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इस टीम में मुस्कान किरार और राज कौर दो अन्य सदस्य थे। 22 साल की ज्योति ने इसके बाद सिंगल्स मुकाबले में कांस्य पदक हासिल किया।

खेल मंत्री ने कहा, 'हम भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर चुके तीरंदाजों के साथ उन खिलाड़ियों को भी सहायता प्रदान करना चाहते हैं जिनके पास क्षमता है। हम उन्हें कोचों, प्रशिक्षण सुविधाओं, तकनीकी सहायता और अन्य आवश्यक चीजों के लिए धन मुहैया करवाएंगे।' भारतीय तीरंदाजी संघ ने टूर्नामेंट से पहले नीदरलैंड्स में ही तीरंदाजों के लिए 11 दिन का शिविर लगाया था जिसका बजट खेल मंत्रालय से मिला था।

अफगानिस्तान की टीम में पड़ी दरार

मैनचेस्टर, प्रेट्र : विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों हुई जबरदस्त पिटाई के बाद अफगानिस्तान की टीम में फूट पड़ गई है। बुधवार को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच और मुख्य चयनकर्ता आपस में भिड़ गए। अफगानिस्तान के कोच फिल सिमंस ने संकेत दिया कि विश्व कप से ठीक पहले असगर अफगान को कप्तानी से हटाने में मुख्य चयनकर्ता दौलत अहमदजई का हाथ था। अहमदजई ने सिमंस की अगुआई वाली कोचिंग टीम को इस लचर प्रदर्शन के लिए दोषी ठहराया है। वहीं, सिमंस ने ट्वीट किया कि मैं अफगानिस्तान के लोगों को बताऊंगा कि असगर अफगान को हटाने और हमारी तैयारियों में खलल डालने में दौलत अहमदजई की क्या भूमिका रही। इससे पहले अफगानिस्तान के एक पत्रकार ने ट्वीट किया था कि अहमदजई का मानना है कि कोचिंग स्टाफ की तैयारियों में कमी के कारण टीम का प्रदर्शन खराब रहा।

विविध

गरीबी को मात दे रहा हुनरमंद सखियों का करोड़पति मंडल

गोड्डा के फूलो झानो सखी मंडल की महिलाओं ने बदली किस्मत

विधु विनोद, गोड्डा

झारखंड के गोड्डा का फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल कई मायनों में खास है। महिलाओं की लगन और मेहनत ने इस सखी मंडल को करोड़पति बना दिया है। कभी गरीबी से जूझने वाली गांव की महिलाएं आज हुनरमंद बन गुरबत को हरा चुकी हैं। मंडल का कारोबार पांच करोड़ के पार पहुंच गया है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि इसको एसोचैम ने सम्मानित किया है। मंडल से जुड़ी हर सखी सात से आठ हजार रुपये महीने की आय अर्जित कर रही है।

जिले के सरकारी स्कूलों में पोशाक आपूर्ति की जिम्मेदारी यह सखी मंडल ही उठा रहा है। मंडल की उपलब्धियों पर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) ने रांची में उसे सम्मानित किया है। संस्था की कोषाध्यक्ष मीरा माधव को महिला सशक्तीकरण श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। पोशाक निर्माण में सखी मंडल की 1360 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन्हें प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। सखी मंडल में 116 महिला समूह हैं। सभी समूहों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। आज इन समूहों की महिलाएं एक से एक शानदार डिजाइन के परिधान बनाने में पारंगत हो गई हैं। आमदनी भी कम नहीं। फूलो झानो सखी मंडल का आज कारोबार पांच करोड़ 20 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

गरीबी उन्मूलन

कौशल विकास से बदली किस्मत : जिला प्रशासन ने फूलो झानो सखी मंडल की 1360 प्रशिक्षित महिलाओं को आधुनिक परिधान बनाने के काम का प्रशिक्षण दिलाया है। इस दिशा में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने भी अहम भूमिका निभाई। अडानी कंपनी के सीएसआर हेड सुबोध सिंह कहते हैं कि महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आइटीआइ कॉलेज परिसर में 125 अत्याधुनिक सिलाई मशीनें लगाई गईं।

इस वर्ष डेढ़ लाख पोशाक का मिला आर्डर : वर्ष 2018 में संस्था का शुभारंभ हुआ था। आज जिले के सरकारी स्कूलों में इसी संस्था की सखियां पोशाक निर्माण कर आपूर्ति कर रही हैं। इस वर्ष डेढ़ लाख पोशाक बनाने का ऑर्डर मिला है।

रोजगार की राह पर दौड़ रहीं गांव की महिलाएं : फूलो झानो सखी मंडल की अध्यक्ष लूसी झा खुद सिलाई में दक्ष हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की एक हजार से अधिक महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई हैं। सभी को उनके काम के एवज में हर माह सात से आठ हजार रुपये की आय हो जाती है। उनके बैंक खाते में यह राशि भेज दी जाती है। शिक्षा विभाग को पोशाक आपूर्ति करने से आय बढ़ी है। वह बताती हैं कि हमारे मंडल की सखियां खाली नहीं बैठतीं। हमें लगातार काम मिल रहा है, क्योंकि हम पूरी शिद्दत और लगन से गुणवत्तापूर्ण काम को अंजाम देते हैं। काम अच्छा होने से हमारी स्वतः ही ब्रांडिंग हो जाती है। जिसकी वजह से उन्हें काम मिलने में कभी भी दिक्कत नहीं होती है।

केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करती महिलाएं। जागरण

अपने परिवार के अर्थतंत्र का सबल हिस्सा बनीं महिलाएं

सखी मंडल की सांता कहती हैं कि दो दर्जन से अधिक गांवों की सैकड़ों महिलाओं को आज काम मिल गया है। मेहनत के अनुसार हम महिलाओं की आय बढ़ रही है। हम भी अब अपने परिवार के अर्थतंत्र का सबल हिस्सा बन चुकी हैं। मंडल की कोषाध्यक्ष मीरा माधव कहती हैं कि हाथ में हुनर है तो आप बेकार नहीं रहेंगे। हम लोग हुनर सीख अब इतना कमा लेते हैं कि परिवार को सहयोग करने में सक्षम हैं।

गोड्डा जिले में सखी मंडल को रोजगार से जोड़ने की मुहिम रंग लाई है। 1360 महिलाएं इस मंडल से जुड़ी हैं। इस वर्ष सखी मंडल में 500 महिलाओं को और जोड़ेंगे। प्रशिक्षित महिलाओं की आमदनी को सीधे उनके खाते में भेजा जाता है। सखी मंडल की कमेटी पारदर्शिता के साथ इसका संचालन कर रही है।
– किरण कुमार पासी, उपायुक्त, गोड्डा

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

पानी की जगह देते थे मूत्र और उखाड़ लेते थे नाखून

आपातकाल में मिली प्रताड़ना को याद कर सिहर उठते हैं राजाराम, 20 माह 20 दिन जेल में रहे थे

शैलेंद्र शर्मा, जालौन

लोकतंत्र के प्रहरी
आपातकाल के 44 साल

'उफ, याद मत दिलाइए, ब्रिटिश सरकार से ज्यादा जुल्म सहे हैं आपातकाल में। पानी मांगों तो जबरन मूत्र पिलाया जाता था। यातना इतनी कि नाखून तक उखाड़ लिए जाते थे। पेड़ से उलटा लटकाकर पीटा जाता था। अंगुलियों में पिन चुभो दी जाती थी। संघ के वरिष्ठ नेताओं की जानकारी पाने के लिए कड़ी यातना दी जाती थी।' भले ही यह दर्द 44 साल पुराना हो, लेकिन इसकी सिहरन अभी भी सेवानिवृत अध्यापक राजाराम व्यास के जेहन में ताजा है। उरई के राजेंद्र नगर में रहने वाले राजाराम आपातकाल के दौरान 20 महीने से ज्यादा जेल में रहे थे।

सात जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। 26 जून 1975 को देश के किसी भी अखबार ने संपादकीय नहीं लिखा। फिर देशभर में उत्पीड़न शुरू हो गया। झूठे मुकदमे लिख मीसा (मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) और डीआइआर (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल) जैसे काले कानूनों में जेल में बंद किया जाने लगा। संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजाराम बताते हैं कि चार जुलाई 1975 को घर को भारी फोर्स ने घेर लिया था। मानो किसी डकैत या खूनी को पकड़ने आई हो। आपातकाल की घोषणा के समय मैं गांव में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमीरपुर में तत्कालीन जिला प्रचारक ओमप्रकाश तिवारी का संदेश मिला तो वहीं जाकर संघ कार्य में जुट गया। चार जुलाई को उन्हें यमुना नदी पार कराकर किसी अज्ञात जगह भेज दिया और मैं अपने घर आ गया। उसी रात गिरफ्तारी की गई। मैं हमीरपुर में गिरफ्तार होने वाला पहला शख्स था। अगले दिन डीआइआर कानून लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। मेरे साथ ओंकार नाथ दुबे एडवोकेट, जयकरन सिंह, इंद्र बहादुर सिंह भी बंद किए गए।

नहीं था कोई इंतजाम : राजाराम कहते हैं कि प्रशासन को भी इतनी संख्या में गिरफ्तारी का अंदाजा नहीं था। जेल में कपड़े, रहने-खाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। छोटी सी बैरक में डेढ़ सौ लोग बंद थे। लेटना तो दूर बैठने में भी दिक्कत थी। व्यवस्था के लिए अनशन पर बैठे तो जेल प्रशासन ने तीन दिन बाद कहा कि मिलने के लिए लोग आए हैं। गेट पर पहुंचे तो वहां पहले से खड़े पुलिस वाहन में जबरन बैठा दिया गया। कोई नहीं जानता था, कहां जा रहे हैं। सुबह पहुंचे तो सामने का आगरा जेल का गेट था।

बाबा जय गुरुदेव के पैरों में पड़ी थीं बेड़ियां : राजाराम व्यास के मुताबिक आपातकाल का विरोध करने के कारण आगरा जेल में बाबा जय गुरुदेव भी बंदी थे। उनके पैरों में लोहे की बेड़ियां थी। उनके भक्त जेल की परिक्रमा के बाद जो फल आदि दे जाते थे, वहीं हम लोग खाते थे।

रिवॉल्वर लगा पूछा पता, फिर लटका दिया उलटा : राजाराम बताते हैं कि तानाशाही इतनी थी कि हर वह यातना जो सोच भी नहीं सकते, दी गई। संघ के सतीश शर्मा को सिर पर रिवॉल्वर लगा दी गई। ओमप्रकाश तिवारी का पता नहीं बताने पर पेड़ से उलटा लटकाकर पीटा गया। मुझे 19 नवंबर 1975 को फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। वहां तीन माह तक तनहाई बैरक में रखा गया। जेल भेजने से पहले भी पुलिस ने बहुत प्रताड़ित किया। हमीरपुर के रामकेश विश्वकर्मा व विश्वंभर शुक्ला को थाने में उस समय दारोगा प्रभुदयाल ने जो यातनाएं दीं, उसके सामने अंग्रेज कुछ नहीं थे।

मानसिक यातानाओं का भी चला था दौर

राजाराम बताते हैं कि हम लोगों को शारीरिक ही बल्कि मानसिक यातनाएं भी दी गईं। परिजनों के भेजे पत्र पहले जेलर पढ़ते थे। फिर हमें देकर वापस ले लेते थे। मिलाई संभव नहीं थी। लंबी सांस लेकर राजाराम बोलते हैं कि 23 मार्च 1977 को आए चुनाव परिणाम ने तानाशाही के बादल छांट दिए और 25 मार्च 1977 को रिहा किए गए।

उत्तर प्रदेश के उरई में आपबीती सुनाते सेवानिवृत्त शिक्षक राजा राम व्यास। जागरण

कैलास यात्रियों का पहला दल आज तिब्बत में करेगा प्रवेश

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़

कैलास मानसरोवर यात्रियों का पहला दल गुरुवार को तिब्बत में प्रवेश करेगा। दल बुधवार को अंतिम भारतीय पड़ाव नाबीढांग पहुंच गया है। वहीं, कैलास यात्रियों का दूसरा दल गुंजी पहुंचा है।

आइटीबीपी से मिली जानकारी के अनुसार पहले दल में शामिल सभी 58 यात्री भोले बाबा के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दल बुधवार की मध्यरात्रि में तिब्बत के लिए प्रस्थान करेगा। प्रातः आठ बजे तक दल के लिपूलेख दर्रे को पार कर तिब्बत पहुंच जाने की उम्मीद है। दिन में बर्फ पर धूप पड़ने से निकलने वाली चमक के चलते इस क्षेत्र में पैदल चलना खासा मुश्किल होता है। इसके चलते यात्रियों को रात में यात्रा कराई जाती है।

यात्रा पर जा रहा दूसरा दल बुधवार को दूसरे पैदल पड़ाव गुंजी पहुंच गया। यह दल गुरूवार को गुंजी में विश्राम करेगा। शुक्रवार को दल में शामिल 45 यात्रियों का स्वास्थ परीक्षण होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में जिन यात्रियों का स्वास्थ्य सही होगा उनको ही आगे की यात्रा पर रवाना किया जाएगा।

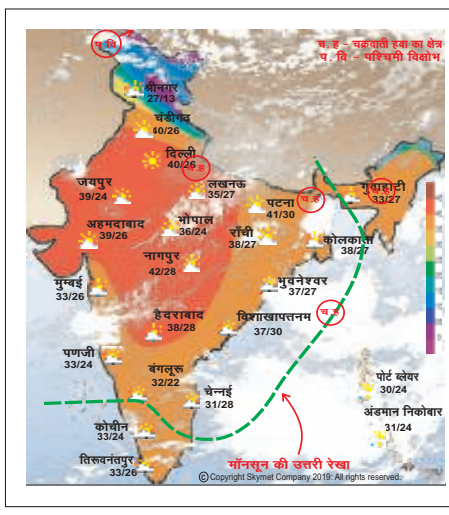

मौसम विशेष

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दिन के तापमान में वृद्धि होगी। मौसम काफी गर्म रहेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गरज और तेज हवाओं के साथ आंधी तथा हल्की वर्षा संभव है। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। नीचले भागों का मौसम गर्म रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/27/व	अहमदाबाद	40/28/व
कोलकाता	36/27/व	बड़ौदा	39/27/आंबा
चेन्नई	39/28/आंबा	नागपुर	41/29/व
हैदराबाद	34/27/व	इन्दौर	39/27/व
बंगलूरू	30/21/व	रांची	38/28/व
त्रिवेन्द्रम	32/26/व	पटना	40/30/व
गुवाहाटी	32/28/आंबा	जमशेदपुर	37/27/आंबा
गंगटोक	19/11/व	पुणे	25/23/व

दुनिया की पहली व्यावसायिक टेलीफोन सेवा शुरू

ह्यूग कोसार्ट बेकर जूनियर ने 1877 में आज ही दुनिया की पहली व्यावसायिक टेलीफोन सेवा कनाडा के हैमिल्टन में शुरू की। फिलाडेल्फिया अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में बेकर को अमेरिकी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के 1876 में किए गए टेलीफोन के आविष्कार की जानकारी मिली।

पहला मानव निर्मित रॉकेट अंतरिक्ष पहुंचा

एमडब्लू 18014 नामक जर्मन वी-2 रॉकेट को 1944 में आज ही के दिन पेनेमुंडे आर्मी रिसर्च सेंटर से लांच किया गया। यह दुनिया की पहली मानव निर्मित वस्तु थी जो बाहरी अंतरिक्ष में पहुंची। रॉकेट की लांचिंग क्षैतिज की गई, फिर भी यह अंतरिक्ष पहुंचा।

प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्रम सेठ का जन्मदिन

विक्रम सेठ का जन्म 1952 में आज ही कोलकाता में हुआ था। पद्म श्री, साहित्य अकादमी, डब्लूएच स्मिथ साहित्य जैसे अवार्डों से वे सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें उनके चार प्रमुख उपन्यासों द गोल्डन गेट, सूटेबल ब्वाय, सूटेबल गर्ल, एन इक्वल म्यूजिक के लिए जाना जाता है। 2001 में सेठ को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मां लीला सेठ हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर कई साहित्यकारों की तरह विक्रम भी साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाना चाहते थे।

इधर-उधर की

ऑनलाइन विला खरीदना पड़ा महंगा

फ्लोरिडा, एजेंसी : अगर चार पहिया वाहन की कीमत में किसी को आलीशान विला मिले तो भला कौन नहीं खरीदना चाहेगा। यहां के करविले होलनेस ने भी यह मौका नहीं गंवाया, लेकिन अब उन्हें पछताते नहीं चुक रहा है। दरअसल एक प्रॉपर्टी वेबसाइट पर बेहद सस्ते दामों पर विला खरीदने का प्रस्ताव था। होलनेस ने प्रस्ताव देखा और विला की तस्वीरें देखीं तो उन्हें यह सौदा बहुत सस्ता लगा। लिहाजा उन्होंने छह लाख रुपये में उस विला को अपना बना लिया। उनका जोश यही पर शांत नहीं हुआ। लगे हाथ उन्होंने सोचा क्यों न जाकर विला का मौका मुआयना कर लिया जाए। वे मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्हें बताया गया कि उन्होंने विला नहीं, उसके सामने हरी घास युक्त जमीन की एक छोटी सी पट्टी खरीदी है। दरअसल तस्वीर में विला के सामने घास की वह पट्टी भी दिख रही थी, लेकिन लालच विला खरीदने का दिया गया था। पश्चाताप में जल रहे होलनेस अब कंपनी पर मुकदमा करने की सोच रहे हैं।

शोध अनुसंधान

डायबिटीज का कारण बन सकता है नए भोजन का डर

आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जो किसी तरह के नए भोजन को आजमाने से डरते हैं। खासकर बच्चों में यह परेशानी ज्यादा देखी जाती है। इसे फूड नियोफोबिया कहा जाता है। ताजा शोध के मुताबिक, फूड नियोफोबिया की परेशानी दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है। इससे टाइप-2 डायबिटीज की आशंका भी बढ़ जाती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि कुछ लोग किसी भी तरह का नया भोजन नहीं आजमाना चाहते हैं। ऐसे लोग बस कुछ गिने-चुने खाद्य पदार्थ ही खाते हैं, जिनका स्वाद उन्हें पहले से पता होता है। इस आदत के कारण उनके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर फूड नियोफोबिया के शिकार लोगों के भोजन में विविधता लाई जा सके, तो उन्हें विभिन्न बीमारियों के खतरे से बचाना संभव हो सकता है। - प्रेट्र

बौनेपन के शिकार बच्चों पर कारगर पाई गई दवा

हड्डियों के विकास में मददगार एक दवा को एकोंड्रोप्लेसिया के शिकार बच्चों की लंबाई बढ़ाने में कारगर पाया गया है। एकोंड्रोप्लेसिया बौनेपन का सबसे सामान्य प्रकार है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस दवा की मदद से बौनेपन के शिकार बच्चों की लंबाई में सालाना करीब छह सेंटीमीटर तक की वृद्धि देखी गई, जो सामान्य बच्चों जैसा ही है। इस दवा के साइड इफेक्ट भी बहुत मामूली हैं। शोधकर्ता जूली हूवर ने कहा, 'अब तक अध्ययन में दवा को कारगर पाया गया है। परीक्षण में करीब चार साल तक दवा का असर देखा गया।' दवा की मदद से ऐसे बच्चे अपनी सामान्य दर से डेढ़ गुना ज्यादा तेजी से बड़े हुए। - आइएएनएस

वैज्ञानिक ऐसे करते हैं वर्ष की गणना

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- कैलेंडर वर्ष से अलग होता है वैज्ञानिक गणनाओं का वर्ष
- लीप वर्ष का नहीं होता है कोई प्रावधान

आइएयू ने तय की है दिन की परिभाषा। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन : दिन, महीने और साल गिनते-गिनते जीवन बीत जाता है। जब भी कोई बात बहुत पुरानी होती है, तो कहा जाता है कि वर्षों पहले की बात है। दिन, तारीख पता हो, तो साल की गिनती भी बता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर - भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप 36 साल पहले जीता था। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस 36 साल में कुल कितने दिन बनेंगे। इसमें कितनी बार लीप वर्ष (जब साल में दिनों की संख्या 366 होती है) आया होगा।

आमतौर पर इन सवालों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहां कई साल की बात हो, वहां कुछ दिनों की गिनती से अंतर महसूस भी नहीं होता है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। विज्ञान की दुनिया में गणना करते समय हर सेकेंड महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक गणनाओं में लीप वर्ष के भरोसे पर नहीं रहा जा सकता है। जब किसी वैज्ञानिक दस्तावेज में लिखा होता है कि अभियान दो साल 10 दिन चलेगा, तब उसमें इस भ्रम के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है कि इन दो वर्षों में लीप वर्ष शामिल होगा या नहीं। वैज्ञानिक गणनाओं के लिए समय की परिभाषा तय है। वैज्ञानिक उसी आधार पर अपने कार्यक्रम तय करते हैं और निश्चित समय में उसे अंजाम भी देते हैं।

क्या है तरीका : 1976 में पेरिस स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (आइएयू) ने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए दिन की परिभाषा तय करने का फैसला किया। इसमें तय किया गया कि 86,400 सेकेंड की अवधि को एक दिन माना जाएगा। इसी आधार पर आइएयू ने 365.25 दिन यानी 3.15576 करोड़ सेकेंड की अवधि को वर्ष का पैमाना माना। इस आधार पर अंतरिक्ष विज्ञान की गणनाओं में प्रयोग होने वाला वर्ष धरती पर प्रयोग होने वाले कैलेंडर वर्ष से थोड़ा सा अलग है। इसमें लीप वर्ष जैसी गणना नहीं होती है, बल्कि हर साल के दिन समान होते हैं। इसमें दो वर्ष 10 दिन का मतलब कुल 740.50 दिन होता है।

क्या है सेकेंड की परिभाषा?

इस गणना को पूरी तरह समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर सेकेंड की क्या माप है? वह अवधि क्या है जिसे एक सेकेंड कहा जाता है? वैज्ञानिक समुदाय इसकी भी परिभाषा तय कर चुका है। अलग-अलग परिभाषाओं से होते हुए इस समय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने सेकेंड की परिभाषा सीजियम-133 के परमाणु को आधार बनाकर तय की है। इस परिभाषा के अनुसार, एक सेकेंड वह अवधि है, जिसमें सीजियम-133 के एक स्थिर समस्थानिक (आइसोटॉप) में होने वाली विशेष प्रक्रिया के कुल 9,19,26,31,770 चक्र पूरे हो जाते हैं।

स्मार्टफोन को रोबोट में बदल देगा यह एप

स्पेक्ट्रम

- रोबोट के लिए आंख, कान और दिमाग का काम करेगा स्मार्टफोन
- अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया एप

प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एप विकसित किया है जो स्मार्टफोन को रोबोट में तब्दील कर देगा। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन ही पूरी तरह रोबोट बन जाएगा तो यह गलत है। दरअसल नए एप के इस्तेमाल से स्मार्टफोन रोबोट के लिए आंख, कान और दिमाग का काम करेगा। रोबोट से यह वायरलेस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और आपके दिए गए निर्देश के अनुसार रोबोट काम करेगा।

इस एप को विकसित करने वाली टीम में एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन पर फीड जानकारी के आधार पर ही रोबोट को अपना काम पता चलेगा और वह परफॉर्म करेगा। इस रोबोट के माध्यम से फैक्टरी और घर के छोटे-मोटे काम कराए जा सकते हैं जैसे किसी चीज को लेकर आना और किसी दूसरी चीज को कहीं और रखने जाना आदि। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस एप को विकसित किया है। इस एप के माध्यम से मोबाइल रोबोट की लागत में भी काफी कमी आएगी।

इस तरह एप करेगा काम : यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कार्तिक रमानी ने बताया कि रोबोट को जहां पर काम करना है उसकी ग्राउंड जानकारी यूजर एप में स्टोर कर सकता है। इसके बाद उस स्मार्टफोन को रोबोट से जुड़े हुए डॉक में रख देना होता है। जिसके बाद रोबोट इससे वायरलेस कनेक्ट होकर अपने काम की जानकारी ग्रहण करता है। इस एप में यह सुविधा भी है कि रोबोट के काम की रफ्तार को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। यह स्मार्टफोन ही रोबोट के लिए आंख, कान और दिमाग होता है और जब तक स्मार्टफोन रोबोट के डॉक में रहता है तब तक रोबोट काम करता है।

सौरमंडल के बाहर पृथ्वी जैसे ग्रह खोजे

अचरज भरा आकाश ▶ 'टीगार्डन स्टार' में जीवन की संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिक

दक्षिणी स्पेन में कैलार ऑल्टो ऑब्जरवेटरी की दूरबीनों से ली गई तस्वीरें

मैड्रिड, आइएएनएस : हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन जीने के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। अब वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से बाहर दो ऐसे ग्रहों की खोज की है, जो पृथ्वी जैसे ही गर्म हैं और माना जा रहा है कि उनमें पानी भी हो सकता है और जीवन जीने के लिए ये ग्रह उपयुक्त हो सकते हैं।

वैज्ञानिक 2016 के बाद से ही टेलिस्कोप के जरिये तारों के पास मौजूद ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। दक्षिणी स्पेन के अलमेरिया स्थित कैलार ऑल्टो ऑब्जरवेटरी के दूरबीनों में इन ग्रहों की तस्वीरें कैद की गई हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि हमारे सौर मंडल से लगभग 12.5 प्रकाश वर्ष दूर 'टीगार्डन स्टार' मिला है जो एक ठंडा लाल बौना तारा है। अध्यन की सह-लेखक इग्नासी रेबास ने कहा कि टीगार्डन हमारे सूरज के द्रव्यमान का केवल आठ फीसद है। सूर्य की तुलना में यह बहुत छोटा और बेहद कम चमकीला है।

हमारे सौर मंडल से लगभग 12 .5 प्रकाश वर्ष दूर है 'टीगार्डन स्टार'। प्रतीकात्मक

उन्होंने कहा आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी के करीब होने के बावजूद इसे अब तक खोजा नहीं जा सका। यह सूर्य की तुलना में 10 गुना छोटा है, इसलिए यह 1,500 गुना कमजोर है और ज्यादातर इंफ्रारेड वेव्स का विकिरण करता है।

ऐसे लगाया ग्रहों का पता : तारे के मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने डोप्लर तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके माध्यम से किसी तारे के आसपास के ग्रहों का पता लगाने के लिए तारे के त्रिज्या-वेग माप का उपयोग किया जाता है। इससे दो ग्रहों टीगार्डन बी और टीगार्डन सी की पहचान हुई।

टीगार्डन बी का द्रव्यमान पृथ्वी के समान ही है और प्रत्येक 4 से 5 दिनों में यह तारे का चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि दूसरा ग्रह परिक्रमा करने में 11 से 12 दिन का समय लेता है। रेबास ने कहा 'वास्तव में टीगार्डन बी तारे के बेहद नजदीक है। जितना प्रकाश हम सूर्य से ग्रहण करते हैं, उससे 10 प्रतिशत अधिक प्रकाश टीगार्डन बी ग्रहण करता है, इसीलिए हमारा अनुमान है कि यह बहुत गर्म हो सकता है और इसमें पानी ना हो, लेकिन इसकी जलवायु के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है तो पानी के बारे में सही जानकारी मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यह ग्रह जिस स्थान पर हैं वह रहने के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब है वहां का तापमान शून्य से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होगा और यदि ऐसा है तो यह बात और पुख्ता हो जाती है कि वहां पानी हो।

अभी एक वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और वहां जीवन संभव हो सकता है। लेकिन अब टीगार्डन की की खोज से शोधकर्ता बेहद उत्साहित हैं क्योंकि ये पृथ्वी के बेहद नजदीक हैं ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यहां भी जीवन संभव हो सकता है।

रेबास ने कहा कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक छोटा लाल बौना ग्रह है जो हमसे चार प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। धरती के आकार का प्रॉक्सिमा बी इसकी परिक्रमा करता है और इसकी खोज 2016 में हुई थी। यह सौर मंडल के इतर सबसे करीबी ग्रह है। इसके आसपास धूल की परत मिली थी। माना जाता है कि यह चट्टानों और बर्फ के कणों से बना है।

विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों का घर हैं डायनासोर के जीवाश्म

- अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर लगाया पता

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्म का अध्ययन कर उनमें रहने वाले माइक्रोब (सूक्ष्म जीवों) का पता लगाया है जो डायनासोर के संबंध में एक नई अवधारणा को प्रस्तुत कर सकता है।

अमेरिका के फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिक जिन्हें डायनासोर के जीवाश्म में संरक्षित प्रोटीन कोलेजन की तलाश थी उन्हें प्रोटीन की बजाय डायनासोर के जीवाश्म में भारी तादाद में बैक्टीरिया मिले हैं। फील्ड म्यूजियम के शोधार्थी इवान सिट्टा ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो जीव वर्षों पहले जमीन में दफन हो गए थे उनके जीवाश्मों में बैक्टीरिया कॉलोनियां बनाकर रह रहे हैं। संभवतः ऐसा मामला पहली बार सामने आया है। उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि इन सूक्ष्म जीवों के मिलना डायनासोर के अध्ययन में एक नई अवधारणा का विकास करेगा।' सिट्टा ने कहा कि अध्ययन के लिए शोधार्थियों टीम ने सेंट्रोसोरस से 75 मिलियन (लगभग 7.5 करोड़) वर्ष पुराने जीवाश्म एकत्र किए और फिर उनकी जैविक संरचना की जांच करने के लिए इन्हें प्रयोगशालाओं में लाया गया, जहां शोधार्थियों ने पाया कि माइक्रोब इनमें कॉलोनियां बनाकर रह रहे हैं।

वैज्ञानिकों ने इससे पहले अध्ययन में डायनासोर के जीवाश्म में प्रोटीन कोलेजन के निशानों की भी पहचान की थी। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन प्रोटीनों का उपयोग कर विलुप्त हो चुके डायनासोर को फिर से जीवित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि सिट्टा ने कहा कि जीवाश्मों में कुछ मॉलीक्यूल जमीन में दफन होने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं पर प्रोटीन हमेशा बना रहना मुश्किल लगता है।

टूरिस्ट एक्सपो में बिखेरी संस्कृति की छटा

चीन की राजधानी बीजिंग में नेशनल कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो के दौरान अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करते बुल्गारिया के आर्टिस्टों का ग्रुप। इस एक्पो में रूस सहित अनेक देशों के सांस्कृतिक कलाकारों की टोलियों ने शिरकत की। तीन दिन चल चले इस एक्सपो में कलाकारों ने अपने देश की संस्कृति, कला और संगीत की प्रस्तुति दी। इस एक्सो का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ देशों के बीच परस्पर सहयोग और भाईचारे की भावना को प्रगाढ़ बनाना है। एएफपी

डिजिटल आर्ट प्रदर्शनी...

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित शॉपिंग मॉल में बुधवार को डिजिटल आर्ट प्रदर्शनी के प्रोजेक्शन के दौरान स्लाइड से फिसलते लोग। जापानी डिजिटल आर्ट कंपनी टीम लैब के 'भविष्य के पार्क, फूलों के जानवर और सहजीवी जीवन' विषयक इस प्रदर्शनी में कंपनी के क्रिएशन प्रदर्शित हो रहे हैं। 20 जून से शुरू हो रही प्रदर्शनी 20 दिसंबर दिसंबर तक चलेगी। इन दिनों यह जकार्ता के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। एपी

स्क्रीन शॉट

बेरोजगार नहीं, काम चुनने की स्थिति में हैं अनुपम खेर

पिछले दिनों आई खबरों में कहा गया था कि अपने करियर के 35 वर्षों में पहली बार अनुपम खेर बेरोजगार हैं। हालांकि अनुपम खेर ने उस खबर को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करना बताया है। अनुपम अमेरिकी मेडिकल ड्रॉमा 'न्यू एम्सटर्डम' कर रहे हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी पांच अगस्त को रिलीज होगी। इसके अलावा उनकी फिल्म 'वन डेः जस्टिस डिलीवर्ड' अगले शुक्रवार को रिलीज होगी। ऐसे में काम की कमी से अनुपम साफ इनकार करते हैं।

वह स्पष्ट करते हैं कि अब वह करियर के इस दौर में अपनी पसंद का काम चुनने की स्थिति में हैं। उनके पास हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है। उसके पीछे आशय यह था कि वह विदेश में काम में व्यस्त हैं। वह अपने नए आयाम खोज रहे हैं। वह कहते हैं, 'किसी ने लिखा कि मैं काम मांग रहा हूं। काम मैं जिंदगी भर मांगता हूं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर मैंने यह नहीं सोचा था कि जब मेरे पास कोई फिल्म नहीं होगी तब भी मैं खुश रहूंगा। विदेश में काम करने के दौरान अपना नया क्षितिज ढूंढ़ा। विदेश में चल रहा मेरा शो 'न्यू एम्सटर्डम' मेरे लिए नया फलक है। मेरे लिए देश और विदेश में एक साथ काम कर पाना मुमकिन नहीं है। मैं वहां पर नौ महीने रहकर काम पूरा करने का वादा कर चुका हूं। इस दौरान मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट सुनी। एक फिल्म शुरू भी करने वाला था फिर लगा कि थोड़ा और समय लेते हैं।'

14 मिनट लंबे सीन को एक शॉट में ओके किया बिग बी ने

बड़ा कलाकार क्यों और कैसे बना जाता है, यह कोई बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से सीखे। अमिताभ की उम्र 76 वर्ष हो चुकी है, लेकिन फिल्मों में काम करने का उनका जज्बा देखते ही बनता है। हर फिल्म के किरदार में जान फूंकने की जैसे उन्हें महारत हासिल हो। लेकिन इससे भी बढ़कर अमिताभ बच्चन में एक और बात यह है कि वह फिल्म की शूटिंग को भी जल्दी पूरा करने में अपना योगदान प्रमुखता से देते हैं। हाल ही में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'चेहरे' की शूटिंग पूरी की है। अब कुछ दिनों के बाद इसी फिल्म की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। दरअसल, फिल्म में एक सीन 14 मिनट का था। अमिताभ की कलाकारी की सबसे बड़ी बानगी यह है कि उन्होंने इस लंबे सीन को एक शॉट में ही ओके कर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद ने अपने दोस्त अमिताभ की इस बात को लेकर खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा, 'मैं भाग्यशाली हूं कि इस फिल्म के ऐतिहासिक दृश्य का हिस्सा बना। इसे एक शॉट में ओके करना न केवल मुश्किल है, बल्कि इसके लिए समर्पण की भावना की भी जरूरत होती है।'

अजय देवगन को लगता है अपने फैसलों से डर?

अजय देवगन करियर की बुलंदियों पर हैं। इस साल रिलीज उनकी फिल्म 'टोटल धमाल' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। मई में रिलीज उनकी फिल्म 'दे दे प्यार दे' भी पसंद की गई। फिलहाल वह अपनी अगली पीरियड फिल्म 'तानाजीः द अनसंग वैरियर' का काम पूरा करने में व्यस्त हैं। इसके अलावा वह 'भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया' कर रहे हैं। करियर के इस मुकाम पर होने के बावजूद कुछ डर ऐसे होते हैं जो हर इंसान में होते हैं। अजय देवगन भी इसका अपवाद नहीं हैं। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन अजय यह बात स्वीकार करते हैं कि अपने लिए फैसलों को लेकर डरते हैं। उनके मुताबिक फैसलों को लेकर हमेशा आशंका रहती है कि यह सही होगा या नहीं? वैसे यह डर सभी में होता है चाहे वह कलाकार हो या कोई और। फर्क इतना है कि कलाकार की चुनी गलत फिल्म उसके करियर पर असर डाल सकती है, वहीं सही फैसला उसकी दुनिया बदल सकता है।

'सत्ते पे सत्ता' के रीमेक में नहीं होंगी कट्रीना कैफ

फिल्मों के रीमेक का दौर जोरों पर है। साउथ से लेकर पुरानी हिंदी फिल्मों का रीमेक बन रहा है। पिछले कुछ समय से वर्ष 1982 में रिलीज फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' की रीमेक की खबरें भी आ रही हैं। सुनने में आया है कि फराह खान, रोहित शेट्टी के साथ मिलकर इसका रीमेक बनाने की तैयारी में हैं। उसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी प्रमुख भूमिका में थे। हाल ही में खबरें आई थीं कि इस फिल्म के लिए रितिक रोशन को फाइनल किया गया है। उससे पहले शाहरुख खान और कट्रीना कैफ का नाम भी फिल्म के लिए सामने आ रहा था। अब इस बात से कट्रीना ने खुद ही पर्दा उठा दिया है। बकौल कट्रीना, 'पता नहीं ये सब बातें कहां से आ रही हैं। अब इन खबरों की आदत हो गई है। जब मैं सुनती हूं कि मेरा नाम उस फिल्म से जोड़ा जा रहा है जिसमें मैं नहीं हूं, तो भी मैं नॉर्मल रहती हूं। जब मैं बॉलीवुड में नई-नई आई थी, तब ऐसी खबरों को पढ़कर बुरा लगता था। अब खुद के बारे में लिखी किसी भी खबर से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है।'

अनुराग कश्यप की अगली फिल्म में सय्यामी खेर

राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'मिर्जिया' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सय्यामी खेर अब अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट होंगे मलयालम एक्टर रोशन मैथ्यू। इस बारे में सय्यामी ने बताया, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अनुराग कश्यप की फिल्म में हूं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हूं। फिलहाल फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी।' पिछले सप्ताह ही अनुराग ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। बहरहाल, इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में की जाएगी और तीन महीने में इसकी शूटिंग पूरी कर ली जाएगी।

तकनीक

विस्फोटकों का पता लगाएगा नया सेंसर

आइआइटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने बनाई कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइस, फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित तकनीक का किया उपयोग

- साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन, यह डिवाइस इतनी हल्की और छोटी है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सेंसर विकसित किया है जो डीएनटी और टीएनटी जैसे विस्फोटक का आसानी से पता लगा सकता है और इसका उपयोग आतंकवाद को खत्म करने और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी के लिए किया जा सकता है।

डीएनटी, टीएनटी जैसे नाइट्रोएरोमैटिक विस्फोटक नागरिकों और सैन्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इन रसायनों को पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जहरीले दूषित पदार्थों के रूप में भी जाना जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में बताया गया है कि यह उपकरण छोटा और हल्का है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया सकता है। साथ ही यह पर्यावरण निगरानी का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

आतंकी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है और भारी जन-धन की हानि भी होती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम ने ऐसे विस्फोटकों का पता लगाने के लिए नया सेंसर विकसित किया है। इस टीम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआइएसईआर) कोलकाता से बिनॉय मैती और प्रियदर्शी डी शामिल थे। इन्होंने मिलककर फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित तकनीक का उपयोग करके इस सेंसर को विकसित किया। जब भी कोई विस्फोटक इस नए सेंसर के संपर्क में आता है तो इसके पॉलीमर का रंग बदलने लगता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है।

नया सेंसर समय रहते पता लगा सकता है कि विस्फोट कहां रखा हुआ है। प्रतीकात्मक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के असिस्टेंट प्रोफेसर सौमित्र सतपथी ने कहा कि यह पॉलीमर यौगिकों के विस्फोटक वर्ग का पता लगा सकता है, जिसे नाइट्रोएरोमैटिक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह सेंसर रक्षा और फोरेंसिक विभाग के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। सतपथी ने कहा कि आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों की निगरानी करने के साथ ही यह सेंसर जल में घुले नाइट्रोएरोमैटिक का भी आसानी से पता कर लेता है।

प्रोफेसर सतपथी ने कहा कि इस उपकरण की लागत मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे पारंपरिक उपकरणों की तुलना में बहुत कम होगी। शोधकर्ताओं के अनुसार इस सेंसर का सार्वजनिक स्थानों जैसे हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशनों, शॉपिंग मॉल आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसे आधिकारिक रूप से भी मान्यता मिलेगी और आतंकवादरोधी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाएगा। शोधकर्ताओं की टीम अब नाइट्रो-एस्टर (नाइट्रोग्लिसरीन, पीईटीएन) और नाइट्रो-एमाइन (एचएमएक्स) जैसे अन्य विस्फोटकों का पता लगाने के लिए एक तकनीक पर काम कर रही है।